ELITE IAS

समसामयिकी

अक्टूबर - 2018

8899999931/34

A-1 Chandra House, Top Floor, (Opp. ICICI Bank), Mukherjee Nagar, Delhi-09

ELITE IAS

Our Courses

For Civil Services Preparation

CLASSROOM PROGRAM

English / Hindi

Upgraded Foundation Course
General Studies

ONLINE COURSES

General Studies Video Classes
(Interactive)

ALL INDIA TEST SERIES

English / Hindi

General Studies
Prelims + Mains + Essay

CORRESPONDENCE COURSES

General Studies Pre. & Mains
(Interactive)

Index

आलेख

1.	आधार को सुरक्षित कवच की दरकार	1-2

कला, संस्कृति, समाज एवं सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे

2.	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान आरंभ किया	3-3
3.	सिक्किम को पहला एयरपोर्ट मिला	4-4
4.	भारत में 2005-2016 के बीच 27 करोड़ लोग हुए गरीबी से बाहर: संयुक्त राष्ट्र	5-5
5.	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को मंजूरी	5-6
6.	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत	6-7
7.	महिला सुरक्षा हेतु दो पोर्टल लॉन्च	8-8
8.	कक्षाओं को डिजिटल बनाए जाने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास आरंभ	8-9
9.	भारत में 10 लाख की आबादी पर केवल 19 जज: कानून मंत्रालय	9-9
10.	अयोध्या विवाद पर 29 अक्टूबर से होगी सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट	9-10
11.	व्यभिचार कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: विवाहेतर संबंध अपराध नहीं	10-11
12.	भारत में शिशु मृत्यु दर में कमी: संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट	11-12
13.	गुजरात में शुरू हुआ देश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय	12-12

राजव्यवस्था एवं शासन, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक विकास

14.	चुनाव आयोग ने राज्य सभा और विधान परिषद चुनावों से 'नोटा' विकल्प हटाया	13-13
15.	ट्रिपल तलाक को अपराध के दायरे में लाने वाले अध्यादेश को मंजूरी	13-14
16.	सरकार ने लोकपाल खोज समिति गठित की	14-15
17.	विधि आयोग ने 'परिवार कानून में सुधार' हेतु परामर्श पत्र जारी किया	15-16
18.	समयपूर्व लोकसभा और विधानसभा भंग होते ही लागू होगी आचार संहिता	16-17
19.	सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दी	17-17
20.	सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की वैधता को मान्यता प्रदान की	17-18
21.	केंद्र सरकार ने यौन अपराधियों का राष्ट्रीय रजिस्टर जारी किया	19-19
22.	अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन	20-20

अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत और विश्व एवं वैश्विक परिदृश्य

23.	भारत और अमेरिका के बीच पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन	21-21
24.	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सुधार प्रक्रिया को लेकर जी-4 देशों के बीच बैठक	22-22
25.	संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत को 130वां स्थान हासिल हुआ	22-23
26.	इब्राहिम सोलिह ने मालदीव राष्ट्रपति चुनाव जीता	24-24
27.	भारत और सर्बिया ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने हेतु दो समझौते पर हस्ताक्षर किए	24-25
28.	अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस: 21 सितंबर	25-25
29.	भारत और मोरक्को ने कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए	26-26
30.	भारत-बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से तीन परियोजनाओं की शुरुआत की	27-27
31.	यूएस ने फिलिस्तीनी मिशन को बंद करने की घोषणा की	27-28

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास

32.	रुपये की कीमत में स्थिरता लाने के लिए पांच उपायों की घोषणा	29-29
33.	देना बैंक, विजया बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय की घोषणा	29-30
34.	सरकार द्वारा जन-धन योजना जारी रखने एवं ओवरड्राफ्ट सीमा दोगुनी करने की घोषणा	30-31
35.	आशा और आंगनवाड़ी श्रमिकों के पारिश्रमिक में वृद्धि	31-31
36.	नीति आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र के मध्य सतत विकास फ्रेमवर्क पर समझौता	32-32
37.	भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 7.8% रहेगी: फिच रिपोर्ट	32-33
38.	कैबिनेट ने जीएसटीएन को सरकारी ईकाई घोषित करने हेतु प्रस्ताव स्वीकार किया	33-33
39.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े परिचालन दिशा-निर्देशों में संशोधन	34-34
40.	'द फ्यूचर ऑफ जॉब्स' रिपोर्ट: विश्व आर्थिक मंच	35-35
41.	सेबी ने शेयर बायबैक नियमों को संशोधित किया	35-36
42.	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को मंजूरी	36-37
43.	डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष की शुरुआत	37-37
44.	इस्पात मंत्रालय ने पहली बार द्वितीयक इस्पात क्षेत्र को पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की	38-39
45.	अटल पेंशन योजना अनिश्चितकाल तक बढ़ाई गई	39-39

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं स्वास्थ्य

46.	'अप्सरा' परमाणु रिएक्टर 09 वर्ष बाद पुन: आरंभ किया गया	40-40
47.	भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त 'युद्ध अभ्यास 2018' उत्तराखंड में शुरू	40-41
48.	महिलाओं की सहायता हेतु इंदिरा शक्ति एप्प लॉन्च	41-41
49.	जर्मनी में विश्व की पहली हाइड्रोजन इंधन वाली ट्रेन का सफल परीक्षण	42-42
50.	भारत-पाक सीमा पर 'स्मार्ट फेंसिंग' प्रोजेक्ट की शुरुआत	43-43
51.	महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार पोषाहार नीति को मंजूरी	43-44
52.	जापान ने पृथ्वी से 30 करोड़ किमी दूर ऐस्टेरॉयड पर उतारे दो रोबोट रोवर	44-45
53.	ग्लोबल टीबी रिपोर्ट-2018	45-46
54.	विश्व में भुखमरी के स्तर में लगातार तीसरे वर्ष वृद्धि: संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट	46-46
55.	टी-72 टैंकों के लिए 1000 इंजनों की खरीद को मंजूरी	46-47
55.	भारतीय लड़ाकू विमान तेजस ने पहली बार हवा में ईंधन भरने का सफल परीक्षण किया	47-48
55.	इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण	48-48
56.	नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी को मंजूरी	49-49
57.	सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह पर जोधपुर में पराक्रम पर्व का उद्घाटन	50-50
58.	स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सुखोई से सफल परीक्षण	51-51
59.	आइएनएमएएस ने पहली स्वदेशी एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट तैयार की	51-52
60.	सरकार ने सेरिडॉन सहित 328 एफडीसी दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई	52-53
61.	भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रहार' का सफल परीक्षण किया	53-53
62.	जापान ने दक्षिण चीन सागर में पहली बार पनडुब्बी अभ्यास किया	54-54
63.	'मैन पोर्टेबल ऐंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल' का सफल परीक्षण	54-55
64.	इसरो ने दो ब्रिटिश उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया	55-55
65.	भारत में 21.40 लाख लोग एड्स से पीड़ित : नाको रिपोर्ट	56-56
66.	भारत और फ्रांस ने गगनयान मिशन के लिए समझौता किया	57-57
67.	बीईएल को नेवी के लिए मिसाइल बनाने का अनुबंध प्राप्त हुआ	57-58

पारिस्थितिकी और पर्यावरण

68.	अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा की पहली बैठक दो अक्टूबर को होगी	59-59
69.	तमिलनाडु सरकार द्वारा नीलकुरिंजी पौधे के संरक्षण की घोषणा	60-60
70.	जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कार्बन टैक्स जरूरी: विश्व बैंक	60-61
71.	प्रदूषण नियंत्रण हेतु 'वायु' प्रणाली का शुभारंभ	61-61
72.	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा फ्रांस के राष्ट्रपति को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान से सम्मानित किया गया	61-62
73.	गृह मंत्रालय एवं इसरो ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये	62-63
74.	डब्ल्यूडब्ल्यूएफ रिपोर्ट: गंगा विश्व की सबसे संकटग्रस्त नदियों में से एक	63-64
75.	विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सफाई अभियान 'ओशियन क्लीनअप' आरंभ	64-64
76.	झारखंड सरकार ने अधिकारिक उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक कारों की सेवा आरंभ की	65-65

अन्य `बरें

77.	नोबल पुरस्कार 2018: चिकित्सा तथा भौतिकी क्षेत्र में पुरस्कार विजेताओं की घोषणा	66-66
78.	डोना स्ट्रिकलैंड 55 वर्ष में नोबेल जीतने वाली पहली महिला	66-66
79.	दिल्ली सरकार ने 40 सेवाओं के लिए डोरस्टेप डिलीवरी योजना आरंभ की	67-67
80.	एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन	67-70
81.	पूर्व भारतीय कप्तान सरदार सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया	70-70
82.	जस्टिस रंजन गोगोई भारत के नये मुख्य न्यायाधीश नियुक्त	70-70
83.	आईसीसी ट्वेंटी-20 विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा की गई	70-70
84.	एशिया कप 2018: भारत ने बांग्लादेश को हराकर सातवीं बार खिताब जीता	71-71
85.	श्रीशंकर ने लम्बी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया	71-71
86.	राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2018 की घोषणा	72-72
87.	देश की पहली महिला आईएएस अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा का निधन	72-72
88.	के.एन. व्यास एटॉमिक एनर्जी कमीशन के प्रमुख नियुक्त	72-72

89.	सेल्सफोर्स के संस्थापक मार्क बेनिओफ ने टाइम मैगजीन को खरीदा	72-72
90.	भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में आरम्भ हुआ	73-73
91.	नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन का खिताब जीता	73-73
92.	नोवाक जोकोविच ने 14वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता	73-73
93.	अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2018	73-73
94.	बिमल जालान मुख्य आर्थिक सलाहकार चयन समिति के अध्यक्ष घोषित	74-74

ELITE IAS

आलेख
आधार को सुरक्षित कवच की दरकार

आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आखिरकार ऊहापोह का एक लंबा दौर खत्म हुआ। शीर्ष अदालत के फैसले ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े इस दस्तावेज को लेकर कई बातें स्पष्ट कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि आधार भारतीय जनजीवन का केंद्र बिंदु बन गया है। अब आधार को विधिक मान्यता मिल गई है। कुछ अपवादों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने आधार को विधिक मान्यता मिल गई है। कुछ अपवादों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी। इसे सरकार और आम लोगों, दोनो के लिए ही राहत भरा कहा जा सकता है। जहां सरकार को कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में आधार की अनिवार्यता की मंजूरी मिल गई तो वहीं आम लोगों को तमाम सेवाओं के लिए निजी कंपनियों को आधार की जानकारी साझा करने की बाध्यता से मुक्ति मिल गई। इसके लिए अदालत ने धारा 57 को गैरकानूनी घोषित किया। हालांकि इस फैसले ने आधार को संवैधानिक आवरण मुहैया करा दिया, लेकिन उसकी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। सरकार इस पर भले ही अपनी पीठ थपथपा ले, परंतु अब आधार को लेकर उसका रूख-रवैया की भविष्य में उसकी सफलता और सुरक्षा की दशा-दिशा तक करेगा। इसे इस तरह कहा जा सकता है कि आधार को लेकर अदालत ने तो अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली, लेकिन सरकार का असल काम अभी शेष है।

यह किसी से छिपा नहीं कि आधार को लेकर सबसे ज्यादा बवाल उससे जुड़ी जानकारियों के लीक होने के मसले पर हुआ। इसमें कई निजी कंपनियों की भूमिका संदिग्ध मानी गई। आधार के नियमन का जिम्मा संभालने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआडीएआइ ने पिछले साल आधार की सूचनाओं के चलते साइबर सुरक्षा को पैदा हुए खतरे के मामले में 50 से ज्यादा एफआइआर दर्ज कराई थीं। इस लिहाज से मोबाइल सिम से लेकर अन्य सेवाओं-सुविधाओं के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म करने से लोगों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी और उनकी जानकारियों के दुरूपयोग की आशंका घटेगी। यह वर्तमान और भविष्य के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन इससे अतीत में दी गई जानकारियों को लेकर निश्चित नहीं हुआ जा सकता। ऐसे में सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि निजी कंपनियों के पास आधार से जुड़ी जो जानकारियां हैं उन्हें कैसे नष्ट किया जाए या वापस लाया जाए। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा। कि उन जानकारियों का कोई दुरूपयोग भी न हो। यह एक तरह से जिन्न को वापस बोतल में बंद करने जैसा काम होगा।

सरकार के समक्ष दो स्तर पर चुनौतियां हैं- एक कानूनी स्तर है और दूसरा तकनीकी मौजूदा आधार अधिनियम में जानकारियां लीक होने की सूरत में कड़े प्रावधानों का आभाव है तो सरकार को कानून में आवश्यक संशोधनों के माध्यम से कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। जल्दबाजी में कानून को पारित कराने के फेर में सरकार इसे पूरी तरह चुस्त-दुरूस्त नहीं बना पाई। दूसरे यानी तकनीकी मोंचे पर सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि इस डिजिटल जानकारी के महासागर में कोई हैकर सेंधमारी न कर सके। इस मामले में सरकार की ओर से दलील दी गई है कि आधार डाटा 64 बिट फॉर्मेट में इनक्रिप्ट किया गया है जो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन मौजूदा दौर में ईजाद किए जा चुके शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटरों के माध्यम से इसके अलॉगरिदम में सेंध की आशंका समाप्त नहीं हो जाती। इस संदर्भ में यह तर्क भी गले नहीं उतरता कि आधार की जानकारी 13 फीट ऊंची दीवारों के दायरे में महफूज है, क्योंकि हैकरों को दीवार लांघने की दरकार नहीं होती और वे सात समंदर पार से भी अपने काम को अंजाम दे सकते हैं।

इसमे कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रीय पहचान एक बेहद गतिशील और निरंतर आकार लेने वाली कवायद है। इसकी अपनी जटिलताएं हैं जिनसे विकसित देशों को भी पार पाने में मुश्किल पेश आती है। शायद यही वजह है कि ब्रिटेन दस साल पहले ही अपने राष्ट्रीय पहचान अभियान पर विराम लगा चुका और ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल में ऐसा किया हैं। भारत भी इन समस्याओं से अछूता नहीं रहा है। आधार की शुरूआत से ही उसमें कई खामियां व्याप्त थीं। आरंभ में इसे राष्ट्रीय पहचान के प्रमाणन के रूप में ही देखा गया है इसकी साइबर सुरक्षा के जोखिमों की अनदेखी की गई। इसी वजह से समय के साथ इससे विवाद से जुड़ते गए। आधार को एक सख्त डाटा सुरक्षा कानून के साथ जोड़ने की जरूरत है। हालांकि सरकार श्रीकृष्ण समिति की सिफारिशों के आधार पर एक सामान्य डाटा सुरक्षा कानून बनाने पर विचार कर रही है, लेकिन आधार की व्यापकता को देखते हुए उसके लिए एक विशेष कानून की आवश्यकता महसूस होती हैं। वह प्रभावी सिद्ध होगा और आसन्न खतरों को लेकर उसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो पाएगी।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

समय के साथ आधार का दायरा जितना विस्तृत हुआ उसके साथ चुनौतियां भी उसी अनुपात में बढ़ती गई हैं। शुरूआत में इसे राशन कार्ड जैसे पहचान पत्र की तरह ही लिया गया और लोग इसकी बायोमीट्रिक पहचान को हल्के में लेते रहे जिसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। परिणामस्वरूप आए दिन लोगों की जानकारियां लीक होने की सूचानएं आने लगीं। इसका अर्थ यह था कि आधार से जुड़ा हमारा तंत्र जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं रहा। एक ऐसे वक्त जब आधार एक महत्वपूर्ण सूचना ढांचे का रूप ले चुका है तब उसे लेकर सतर्कता और बढ़ानी होगी। इसके माध्यम से देश के लोगों की इतनी जानकारियां जुटाई जा चुकी हैं कि कोई दुश्मन देश साइबर हमले के माध्यम से हमारी व्यवस्था की बुनियाद हिला सकता है। इससे देश की संप्रभुता भी खतरे में पड़ सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आधार की राह में खतरे कम नहीं हुए हैं। अब इन खतरों से निपटने की जरूरत है। आधार में सरकार एक सेवाप्रदाता या प्रोत्साहक की भूमिका में है जहां सभी पक्षों को उचित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा आधार के विषय में लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है ताकि वे अनावश्यक रूप से आधार संबंधित जानकारी साझा न करें। लोगों को भी यह समझना होगा कि यह केवल एक संख्या या पहचान मात्र नहीं, बल्कि उनकी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों का पुलिंदा है जिसका गट्ठर खुलने में उन्हें ही सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है।

आधार पर आए फैसले ने सरकार के समक्ष यह चुनौती बढ़ा दी है कि वह इस पहचान पत्र की हर मोर्चे बेहतर तरीके से किलेबंदी करे। साथ ही एक नागरिक और समुदाय के स्तर पर हमें भी अपनी जिम्मेदारी महसूस कर उसका उचित रूप से निर्वहन करना होगा। आधार भारत को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो सकता है। यदि हमने इन सभी बातों पर ध्यान दिया तो निश्चित रूप से आधार हमारी सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का आधार बनने की क्षमता रखता है।

——❐❐❐❐——

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

कला, संस्कृति, समाज, तथा सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान आरंभ किया

चर्चा में क्यों?

☞ स्वच्छ भारत मिशन के तहत 15 सितंबर 2018 को देश में 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान का आरंभ हुआ।

मुख्य तथ्य:

❒ 15 सितंबर से आरंभ होकर गांधी जयंती तक चलने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना स्थित सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली एवं तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब में भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद स्थापित किया।

❒ इस अभियान के तहत ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संदेश दिया और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये देश के अलग-अलग 18 स्थानों पर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से संवाद किया।

❒ प्रधानमंत्री ने सबसे पहले देश के पूर्वी इलाके असम के डिब्रूगढ के स्वच्छताग्रहियों से संवाद स्थापित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पश्चिमी छोर पर गुजरात में संवाद किया।

❒ इसके बाद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपना संदेश दिया, फिर प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा से उनका संवाद हुआ।

❒ प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में सभी से 'स्वच्छता ही सेवा' आंदोलन का हिस्सा बनने और 'स्वच्छ भारत' बनाने के प्रयासों को मजबूत करने का आग्रह किया।

अभियान का उद्देश्य

❖ 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान का उद्देश्य स्वच्छता से जुड़े कार्यों में ज्यादा से ज्यादा जन सहभागिता सुनिश्चित करना है। यह अभियान 2 अक्टूबर, 2018 को स्वच्छ भारत मिशन की चौथी वर्षगांठ से ठीक पहले आयोजित किया जा रहा है. यह महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से जुड़े समारोहों के शुभारंभ को भी दर्शाता है। स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य 2 अक्तूबर, 2019 तक स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस लक्ष्य के कारण शौचालयों के निर्माण में बढ़ोतरी हुई है और इसका उपयोग करने वालों की संख्या भी बढ़ी है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत अन्य पहलें

❒ अंतर-मंत्रिस्तरीय परियोजनाओं में स्वच्छता पखवाड़ा, नमामि गंगे, स्वच्छता कार्य योजना, स्वच्छ-स्वस्थ-सर्वत्र अभियान, स्कूल स्वच्छता अभियान, आंगनवाड़ी स्वच्छता अभियान, रेलवे स्वच्छता जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।

❒ अंतर-क्षेत्रीय सहयोग में स्वच्छ विख्यात स्थान, उद्योग जगत की भागीदारी, परस्पर धर्म सहयोग, मीडिया अनुबंध और संसद अनुबंध जैसे कार्य शामिल हैं।

❒ 76 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में स्वच्छता कार्य योजना को विकसित किया गया है।

❒ इंटरनेट आधारित पोर्टल बनाए गए हैं ताकि प्रगति की निगरानी की जा सके और कार्यान्वयन स्थिति को रेखांकित किया जा सके।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

सिक्किम को पहला एयरपोर्ट मिला

चर्चा में क्यों?

☞ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 सितम्बर 2018 को सिक्किम के पाक्योंग में बने राज्य के पहले हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसका विकास भारत के पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है।

☞ यह एयरपोर्ट राजधानी गंगटोक से करीब 33 किलोमीटर की दूरी पर है। इस एयरपोर्ट के बन जाने से इस राज्य के पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। चीन की सीमा से लगते इस एयरपोर्ट को काफी अहम माना जा रहा है।

उद्देश्य:

❒ इस योजना का उद्देश्य लोगों को सस्ते में हवाई सफर उपलब्ध कराना और दूर-दराज के इलाकों को भी हवाई संचालन से जोड़ना है।

मुख्य तथ्य:

❒ हवाई अड्डा 201 एकड़ में फैला हुआ है और पाक्योंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा 4500 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। यह भारत-चीन सीमा से करीब 60 किमी और सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 30 किमी दूर है।

❒ सरकार की कोशिश है कि इस एयरपोर्ट से आना-जाना सामान्य लोगों की पहुंच में रहे, इसलिए इसे उड़ान योजना से जोड़ा गया। आने वाले दिनों में मुख्य रनवे के बगल में 75 मीटर लंबी एक अन्य पट्टी के निर्माण के बाद भारतीय वायुसेना इस हवाई अड्डे पर विभिन्न प्रकार के विमान उतार सकेगी।

❒ एयरपोर्ट का रनवे 1.75 मीटर का है, जिसकी चौड़ाई 30 मीटर है। पाक्योंग हवाई अड्डे का निर्माण लगभग 605 करोड़ रुपये में हुआ है।

❒ इस हवाई अड्डे से उड़ानों के परिचालन की शुरुआत से पर्यटकों को निकटतम बागडोगरा हवाई अड्डे से उतरने के बाद चार-पांच घंटे का मुश्किल भरा सफर नहीं करना पड़ेगा। इस एयरपोर्ट के बन जाने के कारण पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों के लिए भी यह सफर से कम से कम 4-5 घंटे बचाएगा।

❒ इसके 1.75 मीटर लंबे रनवे के साथ 116 मीटर का टैक्सीवे है, जिससे इस हवाई पट्टी पर एक ही समय में दो विमान उतारे जा सकते हैं। एयरपोर्ट की क्षमता सौ यात्रियों की है।

❒ इस एयरपोर्ट के बनने से सिक्किम के टूरिज्म, आर्थिक विकास को बल मिलेगा। सिक्किम अकेला ऐसा राज्य था, जिसके पास अपना कोई एयरपोर्ट भी नहीं था। अब इस राज्य के पास भी अपना एयरपोर्ट हो गया। इसके साथ ही सिक्किम की कनेक्टिविटी देश के सभी शहरों के साथ मजबूत हो गई है।

❒ हवाई अड्डे के निर्माण में अत्याधुनिक जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है। यहां की मिट्टी में एयरपोर्ट की आवश्यकताओं के हिसाब से बदलाव किए गए हैं। 4,500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बना यह हवाई अड्डा इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जा रहा है।

अन्य जानकारी:

❒ पाक्योंग हवाई अड्डा देश का 100वां हवाई अड्डा है। अगले महीने से लोग सीधे सिक्किम के लिए उड़ान भर सकेंगे। स्पाइसजेट एयरलाइन सबसे पहली उड़ान को अंजाम देगी। विमान चार अक्टूबर को कोलकाता से उड़ान भरेगा।

❒ पाक्योंग हवाई अड्डा केंद्र सरकार की 'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) योजना में शामिल है। इसका निर्माण भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी(एएआई) ने किया है। ये एयरपोर्ट चीन सीमा के सबसे करीब है, लिहाजा भारत के लिए रणनीतिक तौर पर भी काफी काम आएगा।

❒ स्पाइसजेट ने इसी साल 10 मार्च को कोलकाता से पाक्योंग के बीच बॉम्बार्डियर 400 जहाज की सफल टेस्ट फ्लाइट की थी। इसके बाद कंपनी को सिक्यॉरिटी क्लियरेंस मिल गया था। हाल ही में भारतीय वायुसेना का एक डोर्नियर 228 इस हवाई अड्डे पर ट्रायल के तौर पर उतारा गया था।

पृष्ठभूमि:

❒ इस हवाई अड्डे की आधारशिला वर्ष 2009 में रखी गई थी। यहां से परिचालन शुरू होने के साथ ही सिक्किम पूरे देश से सीधे तौर पर जुड़ जाएगा। यह एयरपोर्ट सिक्किम के लोगों का जीवन आसान कर देगा सरकार के इस विजन के तहत हवाई यात्रा का किराया, रेलवे के सफर के किराए के बराबर हो गया है।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत में 2005-2016 के बीच 27 करोड़ लोग हुए गरीबी से बाहर: संयुक्त राष्ट्र

चर्चा में क्यों?

☞ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2005-06 से 2015-16 के बीच भारत में 27.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यह एक आशाजनक संकेत है जो कि गरीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई जीती जा सकती है।

☞ 2018 बहुआयामी वैश्विक गरीबी सूचकांक (एमपीआई) रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (ओपीएचआई) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है।

मुख्य तथ्य:

❒ भारत में गरीबी घटने की दर सबसे ज्यादा बच्चों, गरीब राज्यों, आदिवासियों और मुस्लिमों के बीच है।

❒ इन दस वर्षों के भीतर गरीबी दर 55 फीसदी से घटकर 28 फीसदी हो गई है. रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी की दर लगभग आधी रह गई है।

❒ इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में 1.3 अरब लोग बहुआयामी गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, जोकि एमपीआई में परिकलित किए गए 104 देशों की कुल आबादी का एक-चौथाई हिस्सा है।

❒ रिपोर्ट में कहा गया कि बहुआयामी गरीबी में जीवन बिता रहे 1.3 अरब लोगों में करीब आधे (46 फीसदी) लोग घोर गरीबी का सामना कर रहे हैं।

❒ यूएनडीपी के प्रबन्धक अचीम स्टेनर ने कहा की हालांकि गरीबी का स्तर, खासतौर से बच्चों में स्तब्ध कर देनेवाला है, इसलिए इससे निपटने के प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत है।

❒ वर्ष 1900 के बाद से भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के अन्य देशों में लोगों के जीवन जीने की प्रत्याशा 4 साल बढ़ी है और भारत में लोगों के जीवन जीने की प्रत्याशा 11 साल बढ़ी है। यह बहुआयामी गरीबी से सुधार के लिए अच्छा है।

सबसे ज्यादा और सबसे कम गरीबी:

❒ रिपोर्ट में कहा गया, भारत में सबसे ज्यादा गरीबी चार राज्यों में है। हालांकि भारत भर में छिटपुट रूप से गरीबी मौजूद है, लेकिन बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गरीबों की संख्या सर्वाधिक है।

❒ इन चारों राज्यों में पूरे भारत के आधे से ज्यादा गरीब रहते हैं, जोकि करीब 19.6 करोड़ की आबादी है।

❒ रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली, केरल और गोवा में गरीबों की संख्या सबसे कम है।

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

☞ कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत कवर किये जाने वाले बीमित व्यक्तियों (आईपी) के लिए 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' नामक एक योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत बीमित व्यक्तियों के बेरोजगार होने पर नकद राहत मिलेगी।

प्रमुख तथ्य

❒ ईएसआई निगम ने 18 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष कुमार गंगवाल की अध्यक्षता में आयोजित 175वीं बैठक में बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को उपलब्ध कराई जाने वाली अपनी सेवाओं तथा लाभों में बेहतरी की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

❒ रोजगार पद्धति में बदलाव तथा भारत में रोजगार के वर्तमान परिदृश्य, जो अनुबंध एवं अस्थायी कर्मचारियों के रूप में दीर्घकालिक रोजगार से निर्धारित अल्पावधि नियुक्ति में रूपांतरित हो गया है।

❒ अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बीमित व्यक्ति को नौकरी जाने की स्थिति में और नए रोजगार की तलाश के दौरान सीधे बैंक खाते में राहत राशि भेजी जाएगी।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अन्य निर्णय:

- ईएसआई निगम ने कर्मचारियों को प्रति व्यक्ति दस रुपये की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिससे कि उनके श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के ईएसआईसी डाटा बेस में आधार (यूआईडी) के जोड़े जाने को प्रोत्साहित किया जा सके. यह कदम एक ही बीमित व्यक्ति के विविध पंजीकरणों में कमी लाएगा तथा दीर्घकालिक अंशदायी स्थितियों के लिए आवश्यक लाभ उठाने में उन्हें सक्षम बनाएगा।
- ईएसआई निगम ने सुपर स्पेशियलिटी उपचार का लाभ उठाने के लिए अर्हता स्थितियों में रियायत देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिसमें पहले के दो वर्षों के बीमा योग्य रोजगार अवधि को घटाकर छह महीने कर दिया गया है और इसमें केवल 78 दिनों के अंशदान की आवश्यकता होगी।
- बीमित व्यक्तियों के आश्रितों के लिए सुपर स्पेशियलिटी उपचार का लाभ उठाने की अर्हता में छूट देकर अब इसे एक वर्ष के बीमा योग्य रोजगार तक घटा दिया गया है, जिसमें 156 दिनों का अंशदान होगा. इस छूट से बीमित व्यक्तियों एवं उनके लाभार्थियों को संशोधित अर्हता के अनुसार नि:शुल्क सुपर स्पेशियलिटी उपचार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
- ईएसआई निगम ने बीमित व्यक्तियों की मृत्यु पर भुगतान किए जाने वाले अंत्येष्टि व्यय में बढ़ोतरी कर इसे वर्तमान 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

स्रोत: पीआईबी

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हो चुकी है। अब इस योजना से गरीबों और वंचित तबकों का इलाज सुनिश्चित किया जा सकेगा। सरकार ने लोगों को इस खर्च के बोझ से बचाने के लिए इस स्कीम को शुरू किया है।

आयुष्मान भारत योजना:

- इसे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थकेयर स्कीम के तौर पर पेश किया जा रहा है. सरकार के मुताबिक आयुष्मान भारत योजना से करीब 50 करोड़ भारतीय लाभान्वित होंगे. 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 445 जिले के लोगों को योजना का लाभ मिलेगा.
- इस योजना के दायरे में गरीब, वंचित ग्रामीण परिवार और शहरी श्रमिकों की पेशेवर श्रेणियों को रखा गया है। नवीनतम सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना (एसईसीसी) के हिसाब से गांवों के ऐसे 8.03 करोड़ और शहरों के 2.33 परिवारों को शामिल किया गया है।
- सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रत्येक परिवार को सालाना पांच लाख रुपये की कवरेज दी जाएगी और वे सरकारी या निजी अस्पताल में कैशलेस इलाज करा सकेंगे।
- इस योजना के तहत देश के 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा देने की योजना है, जिससे 66 लाख परिवारों को हर साल गरीबी रेखा के नीचे जाने से बचाया जा सकेगा। सरकार द्वारा प्रायोजित ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
- इस बीमा के अंतर्गत 1300 बीमारियों का इलाज संभव होगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मुताबिक गरीबों के लिए सरकारी से लेकर निजी अस्पताल तक इलाज की व्यवस्था होगी जो कि पुरी तरह कैशलेस होगी. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सारे सरकारी इंस्टीच्यूट जुड़े हैं। ऐसे में वहां इलाज कराना और आसान होगा। केरल में इस तरह कई अस्पतालों का कायाकल्प हो चुका है।
- नमो केयर और मोदी केयर से विख्यात हो चुकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश के जन-जन तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचा सकेगी, ऐसा सरकारी तंत्र का दावा है।
- आयुष्मान भारत योजना को इन पांच राज्यों ने लागू करने से इन्कार कर दिया। ये राज्य तेलंगाना, ओडिशा, दिल्ली, केरल और पंजाब हैं। इन राज्यों का कहना है, की यह इस योजना से असंतुष्ट हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

आयुष्मान भारत योजना के दिशानिर्देश :

- आयुष्मान भारत योजना के दिशानिर्देशों में स्पष्ट लिखा है कि आवेदन के दौरान किसी भी तरह का पहचान पत्र मान्य होगा। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो संबंधित राज्य सरकार किसी भी पहचान पत्र के जरिए उन्हें योजना का लाभ दे सकती है।
- इस योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पिछड़े और वंचित स्तर के लोगों की पहचान के लिए मानदंड तय किए गए हैं।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना:

- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एक योजना है। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी के लिए सामान रूप से उपलब्ध करवाना है।
- इस योजना के अंतर्गत देश के पिछड़े राज्यों में चिकित्सा शिक्षा को बेहतर करने हेतु सुविधाएँ उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित है। इस योजना को मार्च 2006 में मंजूरी दी गई थी।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की अवधि को 12वीं पंचवर्षीय योजना से बढ़ाकर 2019-20 तक कर दिया है और इस उद्देश्य के लिये 14,832 करोड़ रूपये का वित्तीय आवंटन निर्धारित किया है।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जैसे छह संस्थान, बिहार (पटना),मध्यप्रदेश (भोपाल),उड़ीसा (भुवनेश्वर) , राजस्थान (जोधपुर),छत्तीसगढ़ (रायपुर) और उत्तरांचल (ऋषिकेश), प्रत्येक में एक-एक स्थापित करना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना:

- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के लिए एक केंद्र सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू किया हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है बीपीएल श्रेणी से संबंधित श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत लाभार्थी होंगे।
- यह सुविधा सभी अस्पतालों (निजी और सरकारी) में होगी। इस योजना के लिए 1 अप्रैल 2008 को नामांकन शुरू किये गए जिसमे करीबन 36 लाख लोगो ने आवेदन किया हैं. यह योजना भारत के 25 राज्यों में लागू की गयी हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य सरकारों को लचीला वित्त पोषण उपलब्ध कराकर ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य क्षेत्र को पुर्नजीवित करने का सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में चार घटक शामिल हैं। जिनके नाम हैं- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, तृतीयक देखभाल कार्यक्रम और स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रजनन और बच्चों के स्वास्थ्य से परे ध्यान केंद्रित कर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के सरकार के प्रयास को दर्शाता है।
- इसलिए इसके तहत संक्रामक और गैर-संक्रामक बीमारियों के दोहरे बोझ से निपटने के साथ ही जिला और उप जिला स्तर पर बुनियादी ढांचा सुविधाओं में सुधार किया गया है।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की सीख को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समन्वित किया गया है।
- वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिये 26,690 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं, जो भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है।

नीति आयोग के मुताबिक स्वास्थ्य पर खर्च:

- नीति आयोग के मुताबिक भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का महज 1.3 फीसदी ही स्वास्थ्य पर खर्च करता है. जबकि चीन 2. 45 फीसदी खर्च करता है और श्रीलंका मलेशिया और थाइलैंड भी स्वास्थ्य पर भारत की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का दोगुना से ज्यादा खर्च करते हैं।
- ऐसे में गांव और शहर की अच्छी खासी आबादी को मजबूरीवश अपने घरेलु बजट में कटौती कर इलाज कराना पड़ता है और उन्हें अच्छी-खासी रकम उधार लेनी पड़ती है।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

महिला सुरक्षा हेतु दो पोर्टल लॉन्च

चर्चा में क्यों?

☞ केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 20 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में महिला सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए दो अलग-अलग पोर्टल लॉन्च किए।

☞ सरकार ने महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें सख्त सजा का प्रावधान एवं जांच में सुधार लाने के लिए आधुनिक फोरेंसिक सुविधाओं का सृजन, गृह मंत्रालय मामले में महिला सुरक्षा प्रभाग की स्थापना एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित नगर परियोजनाएं शुरू करना शामिल हैं।

प्रमुख तथ्य

❒ पोर्टल "cybercrime-gov-in" चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल यौन उत्पीड़न सामग्री, दुष्कर्म एवं सामूहिक दुष्कर्म जैसी यौन रूप से स्पष्ट सामग्री से संबंधित आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट पर नागरिकों से शिकायतें प्राप्त करेगा।

❒ दूसरा पोर्टल, यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीएसओ), जो अभी केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए सुगम है, यौन अपराधों का पता लगाने एवं मामलों की जांच करने में प्रभावी रूप से सहायता करेगा।

❒ यह देश में 'यौन अपराधियों' पर एक केंद्रीय डाटाबेस है जिसका रखरखाव नियमित निगरानी के लिए एनसीआरबी द्वारा किया जाएगा एवं राज्य पुलिस द्वारा इसकी ट्रैकिंग की जाएगी।

❒ इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पीड़ितों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों का सामना करना होगा।

पृष्ठभूमि

❖ गृह मंत्रालय ने इन दोनों पोर्टल को लॉन्च करने से पहले ही साइबर अपराध जांच को सुदृढ़ बनाने के लिए साइबर फोरेंसिक व प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा पुलिस अधिकारियों, सरकारी वकीलों तथा न्यायिक अधिकारियों की क्षमताओं में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 94.5 करोड़ रुपये का अनुदान जारी कर दिया है।

स्रोत: पीआईबी

कक्षाओं को डिजिटल बनाए जाने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास आरंभ

चर्चा में क्यों?

☞ केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 23 सितंबर 2018 को राजस्थान में एक कार्यक्रम में घोषणा की गई कि कक्षाओं को डिजिटल बनाए जाने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास आरंभ किये गये हैं।

☞ 'ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड' के तहत नौवीं से स्नातकोत्तर तक की 15 लाख कक्षाओं को डिजिटल कक्षा का रूप दिया जाएगा। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और आमूल चूल परिवर्तन आएगा।

ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड

❒ ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के तहत सभी स्कूलों में अब सफेद ब्लैक बोर्ड लगाए जाएंगे. यह योजना पांच वर्षों में पूरी तरह लागू की जाएगी।

❒ इससे देश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

❒ इस योजना को केंद्र राज्य और नागरिक समुदाय तथा कार्पोरेट सामाजिक दायित्व से लागू किया जाएगा।

❒ डिजिटल बोर्ड की कीमत में कमी लाने के प्रयास भी किये जायेंगे। महाराष्ट्र नागरिक सामुदाय ने छह जिलों में 300 करोड़ रुपए स्कूलों के लिए एकत्र किए हैं। यह उपक्रम सभी राज्यों में शुरू किया गया है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

पृष्ठभूमि

- इससे पूर्व भारत में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड चलाया गया था जिसे 1987 में आरंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की सुविधा के लिए आवश्यक संस्थागत उपकरण एवं सामग्रियां प्रदान करना निर्धारित किया गया है।
- इस योजना में उस स्कूल में अतिरिक्त शिक्षक के लिए वेतन का प्रावधान है जहां लगातार दो वर्षों तक 100 से अधिक नामांकन आये हों। इस योजना को नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था।

स्रोत: पीआईबी

भारत में 10 लाख की आबादी पर केवल 19 जज: कानून मंत्रालय

चर्चा में क्यों?

- कानून मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में प्रति दस लाख लोगों पर केवल 19 जज हैं. इन आंकड़ों में बताया गया है कि देश में 6000 से ज्यादा जजों की कमी है, जिनमें 5000 से ज्यादा जजों की निचली अदालतों में कमी है।
- यह आंकड़ा उस रिपोर्ट का हिस्सा है, जिसे संसद में चर्चा के लिए मार्च में तैयार किया गया था।

रिपोर्ट से संबंधित मुख्य तथ्य:

- रिपोर्ट के मुताबिक, अधीनस्थ अदालतों में 5748 न्यायिक अधिकारियों की कमी है और 24 उच्च न्यायालयों में 406 वैकेंसी हैं।
- निचली अदालतों में फिलहाल केवल 16,726 न्यायिक अधिकारी हैं, जबकि वहां 22,474 न्यायिक अधिकारी होने चाहिए थे।
- उच्च न्यायालयों में जजों की मान्य संख्या 1079 हैं, जबकि वहां केवल 673 जज हैं।
- सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 31 हैं और वहां छह पद खाली हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतों में जजों के 6160 पद खाली हैं।

जजों की कमी का मामला:

- जजों की कमी का मामला अप्रैल 2016 में उस समय सुर्खियों में आया था जब तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने जजों की नियुक्ति में सरकार की 'निष्क्रियता' की बात कही थी।
- उन्होंने मुकदमों के अंबार के निपटने के लिए जजों की संख्या 21,000 से बढ़ाकर 40,000 करने की बात कही थी. उन्होंने इसके साथ ही कहा था कि 1987 से कुछ नहीं बदला है, जब विधि आयोग ने जजों की संख्या प्रति 10 लाख आबादी पर 10 जजों से बढ़ाकर 50 करने की सिफारिश की थी।
- लेकिन बाद में सरकार ने स्पष्ट किया था कि विधि आयोग ने यह भी टिप्पणी की थी कि मुकदमे दाखिल करने की संख्या आर्थिक और सामाजिक स्थितियों से जुड़ी है, जो विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग है।
- केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने हाल ही में देश के सभी 24 हाई कोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का आग्रह किया था. कानून मंत्री ने 14 अगस्त के पत्र में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 2,76,74,499 मुकदमों के लंबित होने का जिक्र करते हुए कहा था कि इसका एक कारण जजों की कमी भी है।

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

अयोध्या विवाद पर 29 अक्टूबर से होगी सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की सुनवाई करते हुए 27 सितंबर 2018 को अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में नमाज पढ़ने को इस्लाम का अभिन्न हिस्सा मानने से जुड़े मामले को बड़ी बेंच को भेजने से इनकार कर दिया है।
- इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह मसला अयोध्या मामले से बिल्कुल अलग है। इस फैसले के आने के बाद अब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद की सुनवाई शुरू हो सकेगी।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- जस्टिस अशोक भूषण और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस मामले को संविधान पीठ में भेजने से इनकार कर दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्ष 1994 के एक फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है।
- कोर्ट के अनुसार मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है।
- इस फैसले का असर होगा कि राम जन्मभूमि विवाद पर अब सुनवाई शुरू हो जाएगी। जो पिछले सात साल से रूकी हुई ह।
- तीन जजों की पीठ में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण ने इस मामले को बड़ी बेंच में भेजने से मना कर दिया। वहीं जस्टिस नजीर इस मामले को बड़ी बेंच में भेजना चाहते थे।

क्या था मामला?

- इस्माइल फारूकी ने अयोध्या में भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी थी जिस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि नमाज पढ़ना मस्जिद का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
- मुस्लिम समुदाय इससे सहमत नहीं था और वह चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर दोबारा से विचार करे।
- सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों की ओर से दलील दी गई थी कि मस्जिद में नमाज मामले पर जल्द निर्णय लिया जाए।
- मुस्लिम समुदाय यह भी चाहता था कि मुख्य मामले से पहले 1994 के इस फैसले पर सुनवाई हो।
- सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रखा था। इसके साथ ही राम जन्मभूमि में यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया गया था, ताकि हिंदू धर्म के लोग वहां पूजा कर सकें।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

व्यभिचार कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसलाः विवाहेतर संबंध अपराध नहीं

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एकमत से व्यभिचार कानून पर फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली इस बेंच ने कहा कि किसी भी तरह से महिला के साथ असम्मानित व्यवहार नहीं किया जा सकता है।

मुख्य तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में स्त्री और पुरुष के बीच विवाहेतर संबंध से जुड़ी IPC की धारा 497 को गैर-संवैधानिक करार दे दिया है।
- जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपना और जस्टिस एम खानविलकर का फैसला सुनाया। जिसके बाद अन्य तीन जजों जस्टिस नरीमन, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस इंदू मल्होत्रा ने भी इस फैसले पर सहमति जताई।
- केरल के एक अनिवासी भारतीय जोसेफ साइन ने इस संबंध में याचिका दाखिल करते हुए आईपीसी की धारा-497 की संवैधानिकता को चुनौती दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था और जनवरी में इसे संविधान पीठ को भेजा था।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि IPC की धारा सेक्शन 497 महिला के सम्मान के खिलाफ है।
- मुख्य न्यायधीश के अनुसार महिलाओं को हमेशा समान अधिकार मिलना चाहिए. महिला को समाज की इच्छा के हिसाब से सोचने को नहीं कहा जा सकता।
- संसद ने भी महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा पर कानून बनाया हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पति कभी भी पत्नी का मालिक नहीं हो सकता है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- चीफ जस्टिस और जस्टिस खानविलकर ने कहा कि व्याभिचार किसी तरह का अपराध नहीं है, लेकिन अगर इस वजह से आपका पार्टनर खुदकुशी कर लेता है, तो फिर उसे खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला माना जा सकता है
- इसके बाद सभी पांच जजों ने एक मत से इस धारा को असंवैधानिक करार दिया।
- सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ में जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदू मल्होत्रा और जस्टिस ए एम खानविलकर शामिल थे।

धारा-497 क्या है?

- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-497 के तहत यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी अन्य शादीशुदा महिला के साथ आपसी रजामंदी से संबंध बनाता है तो उक्त महिला का पति एडल्टरी (व्यभिचार) के नाम पर उस पुरुष के खिलाफ केस दर्ज करा सकता है।
- हालांकि, ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है और न ही विवाहेतर संबंध में लिप्त पुरुष की पत्नी इस दूसरी महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है।
- इस धारा के तहत ये भी प्रावधान है कि विवाहेतर संबंध में लिप्त पुरुष के खिलाफ केवल उसकी साथी महिला का पति ही शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करा सकता है। किसी दूसरे रिश्तेदार अथवा करीबी की शिकायत पर ऐसे पुरुष के खिलाफ कोई शिकायत नहीं स्वीकार होगी।

स्रोतः द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस

भारत में शिशु मृत्यु दर में कमीः संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी (यूएनआईजीएमई) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया है कि वर्ष 2017 में शिशु मृत्यु दर पिछले पांच वर्षों में सबसे कम दर्ज की गई हैं। इससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।
- यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि यासमीन अली हक ने कहा है कि शिशु मृत्यु दर के मामले में भारत में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत में जन्म से लेकर पांच वर्ष आयु वर्ग तक के बच्चों की मृत्यु दर इसकी इसी आयु वर्ग के जन्म दर के समान है।

संयुक्त राष्ट्र रिपोर्टः मुख्य तथ्य

- यूएनआईजीएमई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2017 में 6,05,000 नवजात शिशुओं की मौत दर्ज की गई, जबकि पांच से 14 साल आयु वर्ग के 1,52,000 बच्चों की मृत्यु हुई।
- भारत में वर्ष 2017 में कुल 8,02,000 बच्चों की मौत हुई और यह आंकड़ा पांच वर्ष में सबसे कम है।
- वर्ष 2016 में भारत में शिशु मृत्यु दर 44 शिशु प्रति 1,000 थी. यदि लैंगिक आधार पर शिशु मृत्यु दर की बात करें, तो 2017 में लड़कों में यह प्रति 1,000 बच्चे पर 30 थी, जबकि लड़कियों में यह प्रति 1,000 बच्चियों पर 40 थी।
- अस्पतालों में प्रसव में वृद्धि, नवजात शिशुओं के देखभाल के लिए सुविधाओं का विकास और टीकाकरण होने से शिशु मृत्यु दर में कमी आयी है।
- पिछले पांच वर्षों में लिंगानुपात में सुधार आया है और बालिकाओं के जन्म और जीवन प्रत्याशा दर में वृद्धि हुई है।
- यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाग और विश्व बैंक समूह की ओर से जारी मृत्यु दर के नये अनुमानों के मुताबिक 2017 में 15 साल से कम आयु के बच्चों में ज्यादातर की मौतों को रोका जा सकता था, या उनकी तकलीफों का इलाज किया जा सकता था।

शिशु मृत्यु दर

- शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्में शिशुओं में से एक वर्ष या इससे कम उम्र मे जीवित न बच पाने वाले शिशुओं की संख्या है।
- परंपरागत रूप से दुनिया भर में शिशु मृत्यु का सबसे आम कारण दस्त से हुआ निर्जलीकरण है। दुनिया भर में माताओं को नमक और चीनी के घोल के बारे में दी गयी जानकारी की वजह से शिशुओं के निर्जलीकरण से मरने की दर में और कमी की दर्ज की गई है।
- 1990 के दशक के अंत तक निर्जलीकरण से शिशुओं की मृत्यु, शिशु मृत्यु की दूसरी सबसे आम वजह थी। अधिक विकसित देशों में शिशु मृत्यु के प्रमुख कारणों जन्मजात विकृति, संक्रमण और एस आई डी एस शामिल हैं।

स्रोतः द हिंदु

गुजरात में शुरू हुआ देश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय

चर्चा में क्यों?

☞ गुजरात के वडोदरा में बने देश के पहले राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय ने काम करना शुरू कर दिया है. 05 सितम्बर 2018 को शिक्षक दिवस के दिन गुजरात के वडोदरा में भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय शुरू किया गया.

फिलहाल यह वडोदरा स्थित भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी से ही काम कर रहा है। कैलिफॉर्निया, बर्कले और कॉर्नेल विश्वविद्यालय जैसे विदेशी पार्टनर्स के साथ काम कर रहे इस रेलवे विश्वविद्यालय ने अभी 2 ग्रैजुएट प्रोग्राम शुरू किए हैं। यह प्रोग्राम बीएससी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी और बीबीए ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट हैं। हर कोर्स में 50 छात्र हैं।

मुख्य तथ्यः

- यह विश्वविद्यालय यूसीजी की नोवो श्रेणी (मानित विश्वविद्यालय संस्थान) नियमन, 2016 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ है।
- यह विश्वविद्यालय भारतीय रेल को आधुनिकीकरण के रास्ते पर ले जाएगा और उत्पादकता बढ़ाकर तथा 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहन देकर परिवहन क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेता बनाने में सहायक होगा।
- विश्वविद्यालय कुशल मानव शक्ति संसाधन का पूल बनाएगा और भारतीय रेल में बेहतर सुरक्षा, गति और सेवा प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिक का लाभ उठायेगा।
- विश्वविद्यालय टेक्नोलॉजी को सक्रिय करके तथा टेक्नोलॉजी प्रदान करके 'स्टार्ट अप इंडिया' तथा 'स्किल इंडिया' को समर्थन देगा तथा उद्यमियता को बढ़ावा देने के साथ-साथ बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करेगा. इससे रेलवे तथा परिवहन क्षेत्र में परिवर्तन होगा तथा लोगों और वस्तुओं की आवाजाही में तेजी आएगी।

पृष्ठभूमिः

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मानव संसाधन कौशल और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के वडोदरा में देश की पहली रेल यूनिवर्सिटी की स्थापना को 20 दिसम्बर 2017 को मंजूरी दी थी। इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए वडोदरा स्थित भारतीय रेल की राष्ट्रीय अकादमी (एनएआईआर) की मौजूदा जमीन का इस्तेमाल किया गया है।
- 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की रेलवे प्रणाली के रिसर्च और आधुनिकीकरण के लिए रेलवे यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी। इसे आतंरिक रूप से राष्ट्रीय रेल परिवहन यूनिवर्सिटी के नाम से जाता है।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

राजव्यवस्था एवं शासन, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक विकास

चुनाव आयोग ने राज्य सभा और विधान परिषद चुनावों से 'नोटा' विकल्प हटाया

चर्चा में क्यों?

☞ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों के मतपत्रों से 'उपर्युक्त में से कोई भी नहीं' (नोटा) विकल्प 11 सितंबर 2018 को हटाने की घोषणा की. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा और विधान परिषद (MLC) के चुनावों में बैलेट पेपर से नोटा का विकल्प प्रकाशित नहीं करने के आदेश जारी किए हैं।

☞ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं जैसे प्रत्यक्ष चुनावों में नोटा एक विकल्प के रूप में जारी रख सकता है। फैसले में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के प्रमुख निर्वाचन अधिकारियों को जारी एक आदेश में कहा कि अब से इन चुनावों के मतपत्रों में नोटा के लिए कॉलम मुद्रित नहीं किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

❒ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में नोटा लागू करना पहली निगाह में बुद्धिमत्तापूर्ण लगता है, लेकिन अगर उसकी पड़ताल की जाए तो ये आधारहीन दिखता है क्योंकि इसमें ऐसे चुनाव में मतदाता की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया गया है, इससे लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास होता है।

❒ कोर्ट के अनुसार, शुरुआत में यह सोच आकर्षक लग सकती है लेकिन इसके व्यवहारिक प्रयोग से अप्रत्यक्ष चुनावों में समाहित चुनाव निष्पक्षता समाप्त होती है। वह भी तब जबकि मतदाता के मत का मूल्य हो और वह मूल्य ट्रांसफरेबल हो. ऐसे में नोटा एक बाधा है।

❒ कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में नोटा लागू करने से न सिर्फ संविधान के दसवीं अनुसूची मे दिये गए अनुशासन का हनन होता है (अयोग्यता के प्रावधान) बल्कि दल बदल कानून में अयोग्यता प्रावधानों पर भी विपरीत असर डालता है।

नोटा (NOTA)

❒ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प दिया गया है जिसे आप चुनाव में अपने पंसद के प्रत्याशी न होने पर नोटा बटन का प्रयोग कर सकते हैं।

❒ इंडिया में नोटा 2013 में सुप्रीम कोर्ट के दिये गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ।

❒ पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जनता को मतदान के लिये नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए।

❒ भारत नोटा का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का 14वाँ देश है।

स्रोत: द हिंदू

ट्रिपल तलाक को अपराध के दायरे में लाने वाले अध्यादेश को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

☞ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 19 सितंबर 2018 को ट्रिपल तलाक को अपराध के दायरे में लाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी देते हुए राष्ट्रपति के पास भेजा था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब ट्रिपल तलाक अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।

मुख्य तथ्य

❖ यह अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा। इस दौरान सरकार को इसे संसद से पारित कराना होगा. सरकार के पास अब बिल को शीत सत्र तक पास कराने का वक्त है। तीन तलाक देना अब अपराध है।

❖ तीन तलाक विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है लेकिन राज्यसभा में लंबित है। कांग्रेस सहित विपक्ष के कुछ दल इस विधेयक के कुछ प्रावधानों में बदलाव की मांग करते रहे हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले:

- गौरतलब है कि बीते 22 अगस्त 2017 को उच्चतम न्यायालय ने एक बार में तीन तलाक को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दिया था।
- सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने 3:2 के मत से सुनाए गए फैसले में तीन तलाक को कुरान के मूल तत्व के खिलाफ बताया।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिमों में तीन तलाक के जरिए दिए जाने वाले तलाक की प्रथा अमान्य, अवैध और असंवैधानिक है।
- इस याचिकओं पर सुनवाई करने वाले पांच न्यायाधीश अलग-अलग पांच धर्मों से थे, मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर (सिख), न्यायाधीश कुरियन जोसेफ (ईसाई), न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन (पारसी), न्यायाधीश उदय ललित (हिंदू) और न्यायाधीश अब्दुल नजीर (मुस्लिम)।

तीन तलाक अध्यादेश से संबंधित मुख्य तथ्य:

- नए बिल में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के मामले को गैर जमानती अपराध माना गया है लेकिन संशोधन के हिसाब से अब मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा।
- इसके तहत किसी भी तरह का तीन तलाक (बोलकर, लिखकर या ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से) गैरकानूनी होगा।
- विधेयक में जो तीन संशोधन किए गए हैं उसके तहत तत्काल तीन तलाक के मामले में जमानत देने का प्रावधान किया गया है।
- साथ ही समझौते का रास्ता खोल दिया गया है. यही नहीं, तत्काल तीन तलाक की शिकायत करने का अधिकार पत्नी या उसके रक्त संबंधी तक सीमित कर दिया गया है।
- तीन तलाक पर अध्यादेश लाकर सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने की कोशिश तो की है लेकिन सरकार की यह कोशिश तब तक सफल नहीं होगी जब तक कि यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो जाता।
- तीन तलाक पर अध्यादेश को कानून बनाने के लिए सरकार को आगामी शीतकालीन सत्र में इसे पारित कराना होगा।

पृष्ठभूमि:

- मार्च, 2016 में उतराखंड निवासी शायरा बानो नाम की महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके तीन तलाक, हलाला निकाह और बहु-विवाह की व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की.
- शायरा बानो ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन कानून 1937 की धारा 2 की संवैधानिकता को चुनौती दी. शायरा बानो द्वारा कोर्ट में दाखिल याचिका के अनुसार मुस्लिम महिलाओं के हाथ बंधे होते हैं और उन पर तलाक की तलवार लटकी रहती है।

स्रोतः द हिंदू

सरकार ने लोकपाल खोज समिति गठित की

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने 27 सितम्बर 2018 को भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के अध्यक्ष और इसके सदस्यों के नामों की सिफारिश करने हेतु आठ सदस्यीय एक खोज समिति का गठन किया।

मुख्य तथ्य

- ये समिति लोकपाल के उम्मीदवारों की तलाश करेगी फिर उनके नाम सरकार के पास भेजेगी। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी।
- कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से लोकपाल अधिनियम में संशोधन करने का अनुरोध किया था, ताकि लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को चयन समिति में शामिल किया जा सके और इस सिलसिले में एक अध्यादेश लाया जाए।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

लोकपाल खोज समिति के सदस्य:

- खोज समिति के सदस्य भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य, प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) प्रमुख एएस किरन कुमार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सखा राम सिंह यादव, गुजरात पुलिस के पूर्व प्रमुख शब्बीर हुसैन एस खंडवावाला, राजस्थान कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ललित के. पवार और पूर्व सॉलीसीटर जनरल रंजीत कुमार हैं।
- आठ सदस्यीय खोज समिति को लोकपाल और इसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों की एक सूची की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है।
- सर्च (खोज) कमेटी के सदस्यों का चुनाव करने के लिए चयन समिति की इस साल (वर्ष 2018) एक मार्च, 10 अप्रैल, 19 जुलाई, 21 अगस्त और चार और 19 सितंबर को चयन समिति की कुल छह बैठकें हुई।
- पहली बैठक में प्रसिद्ध न्यायविद के रूप में पीपी राव शामिल थे। लेकिन उनकी निधन के बाद भारत के पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी को उनकी जगह सदस्य बनाया गया।

लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013:

- लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम को 2013 में पारित किए जाने के चार साल बाद खोज समिति का गठन करने का फैसला किया गया है। लोकपाल चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं।
- इसके सदस्यों में लोकसभा स्पीकर, निचले सदन (लोकसभा) में विपक्ष के नेता, देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) या उनके द्वारा नामित शीर्ष न्यायालय के कोई न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले एक प्रख्यात न्यायविद या अन्य शामिल हैं।

लोकपाल का लाभ:

- लोकपाल के पास सेना को छोड़कर प्रधानमंत्री से लेकर नीचे चपरासी तक किसी भी जन सेवक (किसी भी स्तर का सरकारी अधिकारी, मंत्री, पंचायत सदस्य आदि) के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की सुनवाई का अधिकार होगा।
- वह साथ ही इन सभी की संपत्ति को कुर्क भी कर सकता है। विशेष परिस्थितियों में लोकपाल को किसी आदमी के खिलाफ अदालती ट्रायल चलाने और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी अधिकार होगा।

स्रोत: द हिंदू

विधि आयोग ने 'परिवार कानून में सुधार' हेतु परामर्श पत्र जारी किया

चर्चा में क्यों?

- विधि आयोग ने हाल ही में सुझाव दिया कि महिलाओं और पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र समान होनी चाहिए। विधि आयोग ने कहा कि वयस्कों के बीच शादी की अलग अलग उम्र की व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए।
- भारतीय कानून के तहत, शादी के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष और पुरुषों की शादी की कानूनी उम्र 21 वर्ष निर्धारित है। 'परिवार कानून में सुधार' पर अपने परामर्श पत्र में विधि आयोग ने कहा, ''यदि व्यस्क होने की सार्वभौमिक उम्र को मान्यता है जो सभी नागरिकों को अपनी सरकारें चुनने का अधिकार देती है तो निश्चित रूप से, उन्हें अपना जीवनसाथी चुनने में सक्षम समझा जाना चाहिए।''

विधि आयोग का परामर्श

- व्यस्क होने की उम्र (18 साल) को भारतीय बालिग अधिनियम 1875 के तहत महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए शादी की कानूनी उम्र के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए।
- पत्र में कहा गया, ''पति और पत्नी के लिए उम्र में अंतर का कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि शादी कर रहे दोनों लोग हर तरह से बराबर हैं और उनकी साझेदारी बराबर वालों के बीच वाली होनी चाहिए।''
- सांस्कृतिक विविधता से इस हद तक समझौता नहीं किया जा सकता है कि समानता के प्रति हमारा आग्रह क्षेत्रीय अखंडता के लिये ही खतरा बन जाए।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- किसी मजबूत लोकतंत्र में अंतर नहीं होना चाहिए। 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द का अर्थ केवल तभी चरितार्थ होता है जब यह किसी भी प्रकार के अंतर की अभिव्यक्ति को आश्वस्त करता है।
- आयोग ने नजरिया साझा किया कि महिलाओं और पुरुषों की विवाह उम्र में अंतर बनाए रखना इस दकियानूसी बात में योगदान देता है कि पत्नियां अपने पति से छोटी होनी चाहिए।

समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग के विचार

- विधि आयोग ने पत्र में कहा कि इस समय समान नागरिक संहिता की 'न तो जरूरत है और ना ही वांछित'।
- समान नागरिक संहिता पर पूर्ण रिपोर्ट देने की बजाए विधि आयोग ने परामर्श पत्र को तरजीह दी क्योंकि समग्र रिपोर्ट पेश करने के लिहाज से उसके पास समय का अभाव था।
- परामर्श पत्र में कहा गया कि समान नागरिक संहिता एक व्यापक मुद्दा है और उसके संभावित नतीजे अभी भारत में परखे नहीं गए हैं। इसलिये दो वर्षों के दौरान किए गए विस्तृत शोध और तमाम परिचर्चाओं के बाद आयोग ने भारत में पारिवारिक कानून में सुधार को लेकर यह परामर्श पत्र प्रस्तुत किया है।''
- आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी एस चौहान ने पूर्व में कहा था कि समान संहिता की अनुशंसा करने के बजाए, आयोग पर्सनल लॉ में 'चरणबद्ध' तरीके से बदलाव की अनुशंसा कर सकता है।
- समान नागरिक संहिता समस्या का समाधान नहीं है बल्कि सभी व्यक्तिगत कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है ताकि उनके पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी तथ्य प्रकाश में आ सकें और संविधान के मौलिक अधिकारों पर इनके नकारात्मक प्रभाव का परीक्षण किया जा सके।

स्रोतः द हिंदू

समयपूर्व लोकसभा और विधानसभा भंग होते ही लागू होगी आचार संहिताः

चुनाव आयोग

चर्चा में क्यों?

☞ हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि किसी भी विधानसभा के समय से पहले भंग हो जाने पर राज्य में तत्काल प्रभाव से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी और यह नई सरकार के गठन तक जारी रहेगी.

मुख्य तथ्यः

- चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव और सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि अब समयपूर्व लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं भंग होने की स्थिति में चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी जाएगी।
- कुछ सप्ताह पहले तेलंगाना में विधानसभा को निर्धारित कार्यकाल (जून 2019) पूरा होने से पहले ही भंग किए जाने के परिप्रेक्ष्य में आयोग का यह निर्णय महत्वपूर्ण है। इसके तहत तेलंगाना में भी आयोग द्वारा यह स्थिति स्पष्ट किये जाने के साथ ही आचार संहिता लागू मानी जायेगी।
- आयोग ने आचार संहिता के प्रावाधानों का हवाला देते हुये कहा है कि इस तरह की स्थिति में संहिता के भाग सात के अनुसार राज्य में विधानसभा भंग होने के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो जाती है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है। ऐसे समय में राज्य की कार्यवाहक सरकार और केन्द्र सरकार संबद्ध राज्य के जुड़ी कोई नयी परियोजना की घोषणा नहीं कर सकेगी।
- आयोग ने कहा कि यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के 1994 के उस फैसले के अनुरूप है जिसमें कार्यवाहक सरकार को सिर्फ सामान्य कामकाज करने का अधिकार होने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में कार्यवाहक सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकती है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

चुनाव आचार संहिता

- चुनाव आचार संहिता (आदर्श आचार संहिता/आचार संहिता) का मतलब है चुनाव आयोग के वे निर्देश जिनका पालन चुनाव खत्म होने तक हर पार्टी और उसके उम्मीदवार को करना होता है।
- अगर कोई उम्मीदवार इन नियमों का पालन नहीं करता तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है और दोषी पाए जाने पर उसे जेल भी जाना पड़ सकता है।

स्रोत: द हिंदू

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दी

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी करते हुए देश भर की अदालती कार्यवाही का अब सीधा प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीधा प्रसारण सेवा की शुरुआत वह अपने यहां से करेगा।

मुख्य तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण एवं वीडियो रिकॉर्डिंग करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया।
- मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविल्कर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जनहित में जारी है, और इससे पारदर्शिता आएगी।

लाइव स्ट्रीमिंग से संबंधित मुख्य तथ्य:

- कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी जिससे न्यायिक व्यवस्था की जवाबदेही बढ़ेगी।
- हालांकि, कोर्ट ने अयोध्या और आरक्षण जैसे मुद्दों को संवेदनशील बताते हुए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत देने से इनकार कर दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह कोर्ट की कार्यवाही के लाइव प्रसारण के लिए नियम बनाएगी।
- न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत लाइव स्ट्रीमिंग के नियम-कानून बनाए जाएं।
- हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि फिलहाल इसे प्रायोगिक तौर पर ही लागू करने पर विचार किया जा रहा है।
- कोर्ट ने कहा कि अदालत की कार्यवाही के सीधे प्रसारण से श्रजनता का जानने का अधिकार पूरा होगा।

पृष्ठभूमि

- गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त को राष्ट्रीय महत्व के मामलों में अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर फैसला सुरक्षित रखा था।
- शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा की इसे सुप्रीम कोर्ट से शुरू किया जाएगा पर इसके लिए कुछ नियमों का पालन किया जाएगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग और उसके सीधे प्रसारण को लेकर केंद्र से जवाब मांगा था।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की वैधता को मान्यता प्रदान की

चर्चा में क्यों?

☞ सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2018 को केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आधार आम आदमी की पहचान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार की संवैधानिकता कुछ बदलावों के साथ बरकरार रहेगी।

☞ मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ में जस्टिस एके सीकरी, एएम खानविलर, डीवाई चंद्रचूण और अशोक भूषण ने आधार की अनिवार्यता पर बुधवार को अहम फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट का आधार पर फैसला

❒ सीबीएसई, नीट (NEET) में आधार जरूरी नहीं है। इसके आलावा स्कूल में एडमिशन के लिए भी आधार कार्ड जरूरी नहीं है।

❒ आधार को मोबाइल से लिंक करना आवश्यक नहीं हैं। बैंक खाते से आधार को लिंक करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।

❒ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार से पैन कार्ड को जोड़ने का फैसला बरकरार रहेगा।

❒ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार के पीछे तार्किक सोच। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑथेंटिकेशन डाटा सिर्फ 6 महीने तक ही रखा जा सकता है। कम से कम डेटा होना चाहिए।

❒ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ते वक्त कहा कि आधार से समाज के बिना पढ़े-लिखे लोगों को पहचान मिली है।

❒ सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आधार आम आदमी की पहचान है।

❒ पैन कार्ड के साथ-साथ सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए भी आधार नंबर आवश्यक बना रहेगा।

❒ सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आधार अन्य आईडी प्रमाणों से भी अलग है क्योंकि इसे डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता।

❒ फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 99.76 प्रतिशत लोगों को सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता है। समाज को इससे फायदा हो रहा है तथा दबे कुचले तबके को इससे फायदा मिल रहा है।

❒ सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सुरक्षा मामलों में एजेंसियां आधार की मांग कर सकती हैं। सुरक्षा लहजे से आधार की मांग करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए मान्य होगा।

पृष्ठभूमि

❒ सुप्रीम कोर्ट ने मई 2018 में आधार और इससे जुड़ी 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली थी।

❒ 38 दिन तक चली सुनवाई के बाद 10 मई को पांच न्यायाधीशों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था। पीठ ने उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तस्वामी की याचिका सहित 31 याचिकाओं पर सुनवाई की थी।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)

❒ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) एक सांविधिक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 ("आधार अधिनियम, 2016") के प्रावधानों के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत् दिनांक 12 जुलाई, 2016 को की गई।

❒ यूआईडीएआई की स्थापना भारत के सभी निवाधसियों को "आधार" नाम से एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) प्रदान करने हेतु की गई थी ताकि इसके द्वारा

(क) दोहरी और फर्जी पहचान समाप्त की जा सके और

(ख) उसे आसानी से एवं किफायती लागत में सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके।

प्रथम यूआईडी नम्बर महाराष्ट्र केनन्दूरबार की निवासी रंजना सोनवाने को 29 सितम्बर 2010 को जारी किया गया।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

केंद्र सरकार ने यौन अपराधियों का राष्ट्रीय रजिस्टर जारी किया

चर्चा में क्यों?

- देश में यौन अपराधों के दोषियों की निजी जानकारी डेटा के रूप में रखने के लिए नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स (एनआरएसओ) अर्थात् यौन अपराधियों के राष्ट्रीय रजिस्टर की 20 सितंबर 2018 से शुरुआत की गई।
- इसके साथ ही भारत दुनिया का नौवां देश बन गया है जहां एनआरएसओ के तहत यौन अपराधियों से जुड़ी निजी व बायोमैट्रिक जानकारियां डेटाबेस में रखी गई हैं। भारतीय रजिस्ट्री में ऐसे अपराधियों के नाम, तस्वीरें, घर का पता, उंगलियों के निशान, डीएनए के नमूने और पैन व आधार नंबर शामिल किए जाएंगे।

मुख्य तथ्य

- डेटाबेस में साढ़े चार लाख से ज्यादा मामलों को रजिस्टर किया जाएगा।
- इनमें पहली बार और बार-बार यौन अपराध करने वालों के नाम शामिल होंगे।
- वे समाज के लिए कितने खतरनाक हैं, इस आधार पर उन्हें उनके आपराधिक रिकॉर्ड के हिसाब से अलग-अलग श्रेणी में रखा जाएगा।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) इस डेटाबेस की देखरेख करेगा।
- इसे जांच एजेंसियों के अलग-अलग उद्देश्यों व कामों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- भारत में इस रजिस्ट्री के तहत अपराधियों को तीन श्रेणियों में रखा जाएगा। 15 साल की श्रेणी में 'कम खतरनाक' वाले अपराधियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा।
- 'मध्यम (या थोड़ा) खतरनाक' अपराधियों को 25 साल वाली श्रेणी में रखा जाएगा।
- वहीं, आजीवन श्रेणी में 'आदतन अपराधियों, हिंसक अपराधियों, सामूहिक बलात्कार के दोषियों और यौन अपराध के दोषी सरकारी अधिकारी' को रखा जाएगा।

अन्य देशों में यौन अपराधियों का राष्ट्रीय रजिस्टर

- भारत में यह रजिस्ट्री केवल जांच एजेंसियों के उपलब्ध रहेगी। अमेरिका में इस तरह का डेटाबेस एफबीआई के साथ आम लोगों के लिए उपलब्ध रहता है।
- इन दोनों के अलावा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और त्रिनिदाद व टोबागो में भी यौन अपराधियों की रजिस्ट्री रखी जाती है। इन देशों में भी केवल जांच एजेंसियां इसका इस्तेमाल कर सकती हैं।

पृष्ठभूमि

- नाबालिगों के साथ होने वाले यौन अपराधों को देखते हुए अप्रैल 2018 में फैसला किया गया था कि ऐसे अपराधियों के नेशनल रजिस्ट्री होनी चाहिए. जम्मू-कश्मीर के कठुआ सामूहिक बलात्कार व हत्या मामले के बाद इसकी मांग बढ़ गई थी।
- इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने 'आपराधिक कानून अध्यादेश, 2018' को मंजूरी प्रदान की थी जिसके तहत 12 साल से नीचे के नाबालिग के साथ यौन शोषण करने वाले को मौत की सजा दिए जाने का प्रावधान है।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने 18 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में 'पेंशन अदालत' का उद्घाटन किया।
- इसका आयोजन भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा किया गया। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि इसके जरिए पेंशनभोगियों को 'जीवन निर्वाह में सुगमता' का अधिकार दिया गया है।

मुख्य तथ्य:

- इस अवसर पर डॉ. जितेन्द्र सिंह ने 'केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए सतत सुधारों का एक युग' नामक पुस्तिका का विमोचन भी किया।
- इस पुस्तिका में नियमों के सरलीकरण और शिकायत पोर्टल को मजबूत करने एवं इसे उपयोगकर्ताओं (यूजर) के लिए अनुकूल बनाने हेतु उठाए गए कदमों का उल्लेख किया गया है।
- पेंशन अदालतों से मौके पर ही पेंशनभोगियों की शिकायतों का निवारण करने में मदद मिलेगी।
- डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह निर्देश दिया है कि पेंशनभोगियों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए बाधा मुक्त प्रशासनिक प्रणाली सुलभ कराई जानी चाहिए।
- केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय एक ही दिन अपनी-अपनी ओर से पेंशन अदालतों का आयोजन करेंगे और इस दौरान दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा।
- सरकार ने पेंशनभोगियों की सहूलियत के लिए अनेक सुधार लागू किए हैं। सरकार द्वारा अन्य कई पहल भी की गई हैं जिनमें भविष्य, संकल्प, जीवन प्रमाण-डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, पुराने कानूनों को समाप्त करना और स्व-सत्यापन भी शामिल हैं।
- पेंशनभोगियों से जुड़े मामलों के समस्त हितधारक जैसे कि विभाग, वेतन एवं लेखा अधिकारी एवं संबंधित बैंक के साथ-साथ पेंशनभोगी अथवा उनके प्रतिनिधि वर्तमान नियमों के दायरे में रहते हुए अपनी-अपनी शिकायतों का समाधान करेंगे।
- यह पेंशनभोगियों द्वारा अदालतों का दरवाजा खटखटाने की अनावश्यक जरूरत को समाप्त कर सर्वाधिक तेजी से शिकायतों को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा सुधारात्मक कदम है।

अनुभव पुरस्कार-2018:

- केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने केन्द्र सरकार के उन छह कर्मचारियों को तृतीय 'अनुभव' पुरस्कार-2018 प्रदान किए है, जिन्होंने केन्द्र सरकार की निरंतर पीढ़ियों के लिए संस्थागत स्मृति संयोजित करने के उद्देश्य से तैयार किए गए अनुभव पोर्टल में उल्लेखनीय योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर अनुभव योजना का शुभारंभ वर्ष 2015 में किया गया था।

अनुभव योजना क्या है?

- अनुभव योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्त हुए केंद्रीय कर्मचारियों को एक मंच प्रदान करना है, जिन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान लेखन के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किया था. लेखन के माध्यम से अपने मूल्यवान अनुभवों या सुझावों को प्रस्तुत करने के लिए रिटायर हुए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक वार्षिक पुरस्कार योजना की स्थापना की गई है।
- अनुभव पहल में एक ऑनलाइन सिस्टम भी है जहा रिटायर हुए कर्मचारी अपने द्वारा किये गए शानदार कार्यों की जानकारी को ऑनलाइन के माध्यम से जमा कर सकते हैं, जिससे रिटायर कर्मचारियों को संतुष्टि मिलती है।
- इससे रिटायर हुए कर्मचारियों के जरूरी और उपयोगी सूचनाओं और सूचनाओं का डाटाबेस भी तैयार करने में भी मदद मिलती है. अनुभव प्लेटफॉर्म पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देश के सामाजिक पूंजी के विकास के लिए अपने अनुभव, कौशल और समय देने का अवसर मिलता है।

स्रोत: पीआईबी

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध भारत और विश्व एवं वैश्विक परिदृश्य

भारत और अमेरिका के बीच पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन

चर्चा में क्यों?

- भारत और अमेरिका ने 06 सितम्बर 2018 को नई दिल्ली में पहली बार टू प्लस टू (2+2) वार्ता का आयोजन किया।

मुख्य तथ्य

- टू प्लस टू बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत अमेरिका की अफगान नीति का समर्थन करता है।
- इसके बाद स्वराज ने भारत और अमेरिका की ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट में मीडिया को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि एनएसजी में जल्द से जल्द भारत की सदस्यता को लेकर बातचीत हुई जिसपर सभी ने सहमति जताई है।
- इस वार्ता में दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल हुए. इस मीटिंग में शामिल होने के लिए अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस और विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो 05 सितंबर को दिल्ली पहुंचे थे।

क्या है 2+2 वार्ता?

- जब दो देश दो-दो मंत्रिस्तरीय वार्ता में शामिल होते हैं तो इसे विदेश नीति के संबंध में 2+2 वार्ता कहा जाता है। सामान्य तौर पर 2+2 वार्ता में दोनों देशों की तरफ से उनके विदेश और रक्षा मंत्री हिस्सा लेते हैं. वर्ष 2010 में भारत और जापान के बीच भी इस तरह की वार्ता हो चुकी है।
- यह वार्ता न सिर्फ सांकेतिक रूप से दोनों ही देशों के बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके जरिए दोनों ही देश अपने मनमुटाव दूर करने की कोशिश करेंगे।
- एशिया-प्रशांत में चीन का दबदबा बढ़ रहा है। चीन और अमेरिका के संबंध कड़वे हैं। ऐसे में अमेरिका को चीन का मुकाबला करने हेतु भारत से ज्यादा सक्षम देश कोई और नजर नहीं आता।
- इसलिए अमेरिका भारत को अपनी ओर करना चाहता है। ऐसे में ये मीटिंग दोनों देशों के लिए अपने-अपने हितों को जाहिर करना और सामने वाले की स्थिति भांपने के लिए काफी अहम है।
- अमेरिका दो बार इस वार्ता को टाल चुका है. ये पहले अप्रैल में होनी थी, फिर जून में और अब आखिरकार ये 6 सितंबर को होने वाली है।
- दोनों ही बार वार्ता टालने के कोई स्पष्ट कारण नहीं बताए गए थे. ये वार्ता अबसे प्रत्येक साल होगी. दोनों देश बारी-बारी से इसकी मेजबानी करेंगे।

वार्ता से संबंधित मुख्य तथ्य:

- विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की यथाशीघ्र सदस्यता के लिए सहमति बनी, अमेरिका इसके लिए सहयोग करेगा। दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी आगे बढ़ रही है।
- दोनों देशों में तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था से दोनों को ही फायदा हो रहा है। अमेरिका भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, कारोबार को संतुलित और परस्पर लाभकारी बनाने की कोशिश हो रही है।
- भारत और अमेरिका दोनों ही देश साझा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों ही देश शांति और नागरिकों की समदृता के लिए काम करने पर राजी हुए हैं। दोनों देश साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटीस ने वार्ता के बाद कहा कि भारत और अमेरिका साथ मिलकर काम करते रहेंगे और साथ ही उन्होंने एक बार फिर से भारत को अमेरिका का सबसे बड़ी रक्षा साझीदार करार दिया।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सुधार प्रक्रिया को लेकर जी-4 देशों के बीच बैठक

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सुधार प्रक्रिया को लेकर जी-4 देशों के बीच बैठक आयोजित की गई। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सुधार प्रक्रिया में कोई ठोस प्रगति नहीं होने पर जी-4 देशों भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने चिंता जताई है।
- इन देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा कि यह प्रक्रिया लंबे समय से ठंडे बस्ते में है। संयुक्त राष्ट्र की इस शक्तिशाली संस्था के औचित्य और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए इसमें शीघ्र सुधार की जरूरत है।

मुख्य तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र में स्थित भारतीय मिशन में जी-4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई।
- भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मेजबानी में हुई इस बैठक में सुधार प्रक्रिया की समीक्षा की गई।
- इस बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया, शविदेश मंत्रियों ने सुरक्षा परिषद में सुधार के मसले पर चर्चा की और अपने राजनयिकों को सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के तरीकों पर गौर करने को कहा।
- सुधार की इस प्रक्रिया को अंतर सरकारी वार्ता के तौर पर जाना जाता है. जी-4 के चारों देश सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रमुख पक्षधर हैं।
- विदेश मंत्रियों द्वारा दिये गए सामूहिक बयान में संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था की कार्यपद्धति को मजबूत करने के साथ-साथ एक-दूसरे की उम्मीदवारी के लिये उनके समर्थन पर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

जी-4 समूह

- सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग के लिये जापान, जर्मनी, भारत और ब्राजील ने जी 4 के नाम से एक गुट बनाया है और स्थायी सदस्यता के मामले में एक-दूसरे का समर्थन करते हैं।
- सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में विस्तार का यूएफसी देश विरोध करते हैं। इनमें इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको, मिस्र, स्पेन, अर्जेंटीना और दक्षिण कोरिया जैसे 13 देश शामिल हैं, जिन्हें 'कॉफी क्लब' कहा जाता है।
- यह देश स्थायी सदस्यता के विस्तार के पक्षधर न होकर अस्थायी सदस्यता के विस्तार के समर्थक हैं।

सुरक्षा परिषद

- यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 1945 में हुआ था और इसके पाँच स्थायी सदस्य (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन) हैं।
- सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्वयुद्ध के बाद के उस शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है, जब सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था।
- इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को दो साल के लिये अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है।
- स्थायी और अस्थायी सदस्य बारी-बारी से एक-एक महीने के लिये परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत को 130वां स्थान हासिल हुआ

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की ओर से जारी मानव विकास रैंकिंग (Human Development Indeñ) में भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को वर्ष 2018 की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार मिला जिससे भारत 189 देशों के बीच 130वां नंबर मिला है।
- वर्ष 2017 के लिए भारत का एचडीआई मूल्य 0.640 है। जिसके कारण भारत को मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। यह दक्षिण एशिया के औसत 0.638 से अधिक है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत की स्थिति में सुधार का कारण

- वर्ष 2016 में भारत 0.624 मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के साथ 131वें स्थान पर था. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1990 से 2017 के बीच सकल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में 266.6 फीसदी का सुधार हुआ है।
- भारत की क्रय क्षमता के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय करीब 4.55 लाख रुपये पहुंच गई है जो पिछले साल से 23,470 रुपये अधिक है।
- इसलिए भारत की स्थिति में एक अंक का सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, इस सूची में बांग्लादेश 0.608 एचडीआई के साथ 136वें और पाकिस्तान एचडीआई 0.562 के साथ 150वें स्थान पर है।

भारत के संदर्भ में रिपोर्ट

- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा के मामले में स्थिति बेहतर हुई है।
- वर्ष 1990 से 2017 के बीच भारत में जन्म के वक्त जीवन प्रत्याशा में करीब 11 सालों की बढ़ोतरी हुई है।
- भारत में जीवन प्रत्याशा 68.8 साल है जबकि 2016 में यह 68.6 साल और 1990 में 57.9 साल थी।
- रिपोर्ट के अनुसार, स्कूली शिक्षा के मामले में भी स्थिति सुधरी है, जबकि 1990 और 2017 के बीच भारत की सकल राष्ट्रीय आय (GNI) प्रति व्यक्ति 266.6 प्रतिशत बढ़ी है।
- इसके अलावा 189 देशों में से 59 देशों को उच्च मानव विकास की श्रेणी में, जबकि 38 देशों को न्यूनतम मानव विकास की श्रेणी में शामिल किया गया है।
- हालाँकि, असमानताओं के कारण भारत के भ्क्प् मान में 26.8 प्रतिशत की कमी हुई है, जो दक्षिण एशियाई पड़ोसियों (क्षेत्र के लिये औसत नुकसान 26.1 प्रतिशत) के मुकाबले ज्यादा है।
- इस रिपोर्ट में लैंगिक असमानता सूचकांक के स्तर पर भारत 160 देशों की सूची में 127वें स्थान पर है और बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुकाबले बेहतर स्थान हासिल किया है।

भारत के समक्ष चुनौतियां

- मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, भारत में नीति और विधायी स्तर पर प्रगति होने के बावजूद महिलाएं पुरुषों की तुलना में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कम सशक्त हैं।
- उदाहरण के रूप में, महिलाओं के हिस्से केवल 11.6 प्रतिशत संसदीय सीटें हैं। 64 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में केवल 39 प्रतिशत वयस्क महिलाएं कम से कम माध्यमिक स्तर तक पहुंची है।
- श्रम के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कम है। 78.8 पुरुषों की तुलना में केवल 27.2 प्रतिशत महिलाएं हैं।
- इसके बावजूद भारत इस मामले में अपने पड़ोसी देशों बांग्लादेश और पाकिस्तान से बेहतर है। लिंग असमानता सूचकांक पर 160 देशों में भारत 127वें स्थान पर है।

संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक

- यह सूचकांक मानव विकास के तीन बुनियादी आयामों (लंबा एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान तक पहुँच तथा जीवन जीने का एक सभ्य स्तर) द्वारा प्रगति का आकलन करने का एक वैश्विक मानक है।
- इसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक द्वारा बनाया गया था, जिसका 1990 में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा समर्थन किया गया और बाद में इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा प्रकाशित किया गया।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

इब्राहिम सोलिह ने मालदीव राष्ट्रपति चुनाव जीता

चर्चा में क्यों?

- मालदीव में 23 सितंबर 2018 को आयोजित राष्ट्रपति चुनावों में मालदिवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के इब्राहिम मोहम्मद सोलिह मालदीव ने जीत दर्ज की है। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को हरा दिया।
- मालदीव के चुनाव आयोग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इब्राहिम सोलिह को 58.3 प्रतिशत वोट हासिल हुए। इब्राहिम सोलिह को भारत की ओर झुकाव रखने वाला माना जाता है जबकि अब्दुल्ला यामीन चीनी समर्थक थे।

मालदीव राष्ट्रपति चुनाव : मुख्य तथ्य

- राष्ट्रपति चुनावों में जीत दर्ज करने वाले 54 वर्षीय सोलिह को 2,62,000 हजार वोटों में से 1,33,808 वोट मिले, जबकि यामीन को 95,526 वोट हासिल हुए।
- राष्ट्रपति चुनाव में 88 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. इस चुनाव में इन दोनों के अतिरिक्त कोई अन्य उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ था, क्योंकि उनमें से कई उम्मीदवार जेल में थे या फिर कुछ को देश छोड़ना पड़ा था।
- फरवरी 2018 में आपातकाल लागू किया गया था तथा संविधान को निलंबित कर दिया गया था।
- यामीन के खिलाफ महाभियोग की कोशिश कर रहे सांसदों को रोकने के लिए सैनिकों को भेजा गया था तथा कई वरिष्ठ जजों और प्रमुख विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था।
- इन सभी कारणों के चलते इब्राहिम सोलिह को जनता तथा विपक्ष का समर्थन प्राप्त हुआ।

भारत के लिए मालदीव राष्ट्रपति चुनावों की अहमियत

- इन चुनावों से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन का झुकाव चीन की ओर अधिक माना जाता था। उनके कार्यकाल के दौरान चीन ने इन्फ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं में बड़े स्तर पर निवेश किया।
- सवा चार लाख की आबादी वाला मालदीव भारत के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। माना जाता है कि चीन ने वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत यहां निवेश करना शुरू किया है।
- वर्ष 2011 तक चीन का मालदीव में कोई दूतावास भी नहीं था, लेकिन अब चीन वहां मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी आरंभ कर दी थी। हिंद महासागर में होने के कारण मालदीव भारत के लिए बेहद अहम है।

भारत-मालदीव संबंध

- मालदीव हिंद महासागर में स्थित 1200 द्वीपों का देश है, जो भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से काफी अहम है। मालदीव के समुद्री रास्ते से ही जापान, चीन होते हुए भारत को उर्जा सप्लाई होती है।
- अदन की खाड़ी में समुद्री लुटेरों के खिलाफ चलाये जाने वाले अभियानों के नाम पर मालदीव अंतरराष्ट्रीय राजनीति में काफी अहम बन चुका है।
- मालदीव सार्क (SAARC) का भी सदस्य है इसलिए इस क्षेत्र में भारत को अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए मालदीव को अपने साथ रखना जरूरी है।
- मालदीव के साथ भारत के वर्षों से घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। मालदीव के साथ नई दिल्ली का धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक और व्यावसायिक संबंध है। 1965 में आजादी के बाद मालदीव को सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में भारत शामिल था।

स्रोतः द हिंदू

भारत और सर्बिया ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने हेतु दो समझौते पर हस्ताक्षर किए

चर्चा में क्यों?

- भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और सर्बिया के प्रेजिडेंट अलेक्जेंडर वुसिस ने 15 सितंबर 2018 को द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दो समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- इसके बाद दोनों नेताओं ने आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद और महान वैज्ञानिक निकोला टेसला की याद में डाक टिकट जारी किए।

मुख्य तथ्य:

- नायडू ने सर्बिया पैलेस में वुसिस से व्यापार, रक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने पर बात की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध मुख्य हितों के मुद्दों पर पारस्परिक विश्वास, आपसी समझ और एक-दूसरे के समर्थन पर आधारित हैं।
- सर्बिया के राष्ट्रपति और भारत के उप राष्ट्रपति ने बेलग्रेड में संयुक्त रूप से भारत-सर्बिया व्यापार मंच की बैठक में हिस्सा लिया। दोनों देशों के बीच गैर-गठबंधन आंदोलन के सह-संस्थापक के रूप में ऐतिहासिक और विशेष संबंध हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सर्बिया की राष्ट्रीय असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और सर्बिया का संयुक्त राष्ट्र और दूसरे बहुपक्षीय मंचों पर काफी करीबी सहयोग रहा है। हमारे बीच इस बात पर सहमति बनी है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार करने की जरूरत है, ताकि इसमें आज की वास्तविकता को प्रतिबिंबित किया जा सके और वर्तमान वैश्विक चुनौतियों से निपटा जा सके।
- दोनों देशों के नेताओं ने आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जतायी. नायडू ने कहा कि आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में दोनों पक्ष कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा विनिर्माण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, ढांचागत क्षेत्र, पर्यटन और औषधि क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।

दो समझौते पर हस्ताक्षर:

- भारत और सर्बिया ने हर तरह के आतंकवाद से लड़ने का संकल्प व्यक्त करते हुए रक्षा विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और अवसंरचना क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया।
- दोनों देशों के बीच पौधों के स्वास्थ्य और उन्हें बीमारियों से बचाने तथा संशोधित हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। पौधों के स्वास्थ और उन्हें बीमारियों से बचाने के क्षेत्र में सहयोग के समझौते से दोनों देशों के बीच कृषि उत्पादों का व्यापार बढ़ेगा।
- इसके साथ ही, भविष्य में सर्बिया और भारत के बीच सीधी विमान सेवा शुरू होने से व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में कई मुद्दे उठे. उन्होंने आपसी हितों के क्षेत्र में सहयोग और तेज करने पर सहमति जतायी।

पृष्ठभूमि:

- उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत और सर्बिया के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने 70 साल पूरे हुए होने के उपलक्ष्य में 14 सितंबर 2018 को सर्बिया पहुंचे थे।
- उनकी यात्रा का मकसद आर्थिक, पर्यावरण, व्यापार और सांस्कृतिक क्षेत्र में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है।

स्रोत: पीआईबी

अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस: 21 सितंबर

चर्चा में क्यों?

- विश्वभर में 21 सितंबर 2018 को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया. यह दिवस हर जगह स्वतंत्रता, शांति और खुशी फैलाने के लिए मानाया जाता है।

मुख्य तथ्य

- इस दिवस पर किसी विशेष क्षेत्र में अस्थायी संघर्ष विराम की अवधि तय की जाती है. शांति सभी को प्यारी होती है।
- शांति का संदेश दुनिया के कोने-कोने में पहुँचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कला, साहित्य, सिनेमा, संगीत और खेल जगत की विश्वविख्यात हस्तियों को शांतिदूत भी नियुक्त कर रखा है।
- यह दिवस विश्व शांति, सौहार्द फैलाने एवं युद्ध तथा हिंसा से दूर रहने के प्रति जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य पूरी पृथ्वी पर शांति और अहिंसा स्थापित करना है।

भारत में विश्व शांति:

- भारत में विश्व शांति के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा पांच मूल सिद्धांत दिए गए थे, जिन्हें पंचशील के सिद्धांत कहा गया। यह पांच सिद्धांत हैं:

(i) एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना।

(ii) एक दूसरे के विरूद्ध आक्रमक कार्यवाही न करना।

(iii) एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना।

(iv) समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना।

(v) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत और मोरक्को ने कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए

चर्चा में क्यों?

✸ भारत व मोरक्को ने 19 सितंबर 2018 को संशोधित हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस आधुनिक समझौते से दोनों देशों के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी।

मुख्य तथ्य

❒ दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने विगत वर्षों में तीन बार बैठकें कीं। इस दौरान दोनों देशों के बीच बाजारों को उदार बनाने और वर्तमान हवाई सेवा समझौते का अद्यतन करने की दिशा में प्रयास किए गए।

❒ दोनों पक्षों ने कानूनी एवं तकनीकी बाधाएं दूर की और इसके साथ ही दोनों देशों ने हवाई सेवा समझौते का आधुनिक मसौदा तैयार करने पर सहमति जताई। इसके बाद दोनों पक्षों ने अपने-अपने यहां की सरकार से हवाई सेवा समझौते के स्वीकृत मसौदे पर मंजूरी प्राप्त की।

❒ इस समझौते पर पर्यटन, हवाई परिवहन, हस्तशिल्प और सामाजिक अर्थव्यवस्था मंत्री मोहम्मद साजिद की भारत यात्रा के दौरान औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

❒ मोरक्को पक्ष की ओर से मोहम्मद साजिद और भारतीय पक्ष की ओर से केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

संशोधित हवाई सेवा समझौता:

❒ इस समझौते के परिणामस्वरूप भारत एवं मोरक्को के बीचे हवाई कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और इसके साथ ही दोनों देशों की एयरलाइनें आपस में कोड को साझा कर सकेंगी।

❒ इस समझौते के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों की संख्या बढ़ाने में अब और भी अधिक आजादी संभव होगी।

❒ नागरिक उड्डयन क्षेत्र में इन घटनाक्रमों या समझौतों से एक देश के लोगों को दूसरे देश की यात्रा करने में सहूलियत होगी जिससे पारस्परिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध और ज्यादा सुदृढ़ होंगे।

समझौते से होने वाले लाभ:

❒ समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा।

❒ यह समझौता व्यापक सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही दोनों देशों की विमान सेवाओं के लिए व्यापारिक संभावनाएं उपलब्ध कराएगा और निर्बाध हवाई संपर्क के लिए अनुकूल वातावरण भी तैयार करेगा।

❒ यह समझौता नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में भारत और मोरक्को के बीच आपसी संबंध को बढ़ायेगा।

पृष्ठभूमि:

❒ नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में बढ़ते अवसरों तथा दोनों देशों के बीच हवाई सेवाओं को आधुनिक और निर्बाध बनाने के उद्देश्य से मौजूदा हवाई सेवा समझौते में संशोधन किया जा रहा है।

❒ भारत और मोरक्को के बीच मौजूदा हवाई सेवा समझौता वर्ष 2004 में किया गया था. इसमें निर्दिष्ट एयर लाइनों की सुरक्षा, संरक्षा और वाणिज्यिक गतिविधियों से जुड़े प्रावधानों में समय के अनुरूप बदलाव की व्यवस्था नहीं थी।

स्रोत: पीआईबी

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत-बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से तीन परियोजनाओं की शुरुआत की

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2018 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बांग्लादेश में तीन आधारभूत परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।
- इन तीनों परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी, उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने संयुक्त रूप से उदघाटन किया।

भारत-बांग्लादेश संयुक्त परियोजनाएं

- भारत-बांग्लादेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं - भरमार (बांग्लादेश)-बहरामपुर (भारत) अंतरसंपर्क के जरिए भारत से बांग्लादेश को 500 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली आपूर्ति, अखौरा-अगरतला रेल लिंक और बांग्लादेश रेलवे के कुलौरा ख्र शाहबाजपुर खंड का पुनरूद्धार कुलौरा-शाहबाजपुर खंड का पुनरूद्धार: इस परियोजना के तहत, पुल और पुल भवन का निर्माण किया गया है. इसमें प्लेटफार्म के साथ स्टेशन और पैदल क्रॉसिंग और रेलवे लाइन के सुधार के साथ शेड भी बनाया गया. इसके अंतर्गत 44.77 किलोमीटर की मेनलाइन तथा 7.77 किलोमीटर की लूपलाइन का भी पुनर्निर्माण किया गया है।
- भारत से बांग्लादेश को 500 मेगावाट विद्युत् आपूर्ति: भारत द्वारा मौजूदा भरमार (बांग्लादेश) से बहरामपुर (भारत) में इंटरकनेक्टिविटी स्थापित की गई है. इसके द्वारा भारत बांग्लादेश को 1.16 गीगावाट बिजली आपूर्ति करेगा. इस परियोजना के बारे में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बांग्लादेश यात्रा के दौरान वर्ष 2015 में घोषणा की गई थी.
- अखौरा-अगरतला रेल लिंक: इस रेल परियोजना को वर्ष 2010 में तय किया गया था. इसके उपरांत दोनों देशों ने वर्ष 2013 में एक एमओयू पर हस्ताक्षर करके इस रेल परियोजना को आरंभ किया. माना जा रहा है कि यह रेल लाइन वर्ष 2019 में काम करना आरंभ कर देगी। इसके तहत 15.054 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का निर्माण किया जाना है। इस रेल लिंक द्वारा भारत और बांग्लादेश क्रॉस बॉर्डर संपर्क करने में सक्षम हो जायेंगे। इससे न केवल दोनों देशों के मध्य आर्थिक-सामाजिक तालमेल बढ़ेगा बल्कि सांस्कृतिक तालमेल भी बढ़ेगा।

स्रोत: पीआईबी

यूएस ने फिलिस्तीनी मिशन को बंद करने की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) ने 10 सितंबर 2018 को वाशिंगटन, डीसी में फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (पीएलओ) कार्यालय को बंद करने की घोषणा की।

फिलिस्तीनी मिशन को बंद करने का कारण:

- पीएलओ ने इसराइल के साथ सीधी और सार्थक बातचीत की शुरुआत आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। इसके उलट पीएलओ ने बिना देखे अमरीकी शांति योजना की आलोचना की और शांति प्रयासों में अमरीकी सरकार के साथ काम करने से इनकार कर दिया।
- इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) में इजराइल के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच करने के फिलिस्तीन के प्रयासों के चलते अमेरिका ने यह कदम उठाया है।

मामला क्या है?

- अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप काफी समय से लंबित मध्य-पूर्व शांति योजना को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं।
- लेकिन, दिसंबर 2017 में अमरीका ने जब यरुशलम को इजराइल की राजधानी मानने का घोषणा किया था,
- उसके बाद से फिलिस्तीनी अधिकारियों ने इस योजना में अमरीका के साथ काम करने से इनकार कर दिया था।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (पीएलओ):

- फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (पीएलओ), जो फिलीस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली मुख्य इकाई के रूप में कार्य करता है।
- पीएलओ की स्थापना 28 मई 1964 को हुई थी। इसका नेतृत्व महमूद अब्बास करते हैं। 100 से अधिक राष्ट्रों ने इसे फिलिस्तीनी लोगों का एकमात्र वैधानिक प्रतिनिधि स्वीकार किया है।
- यह वर्ष 1974 से संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रेक्षक के रूप में मान्य है।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास

रुपये की कीमत में स्थिरता लाने के लिए पांच उपायों की घोषणा

चर्चा में क्यों?

✸ पिछले कुछ समय से डॉलर के मुकाबले रुपये के गिरते स्तर में सुधार हेतु केंद्र सरकार ने रुपये के मूल्य में स्थिरता लाने तथा चालू खातों के घाटे को कम करने के लिए कुछ उपायों की घोषणा की है। इसका लक्ष्य घाटे में कमी लाकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है।

रुपये स्थिरता हेतु किये गये उपाय

अनावश्यक आयात पर कटौती:

❒ गैर जरूरी आयात को नियंत्रित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय किये गये हैं। चालू खाता घाटा को कम करने के लिये सरकार गैर-आवश्यक सामानों के आयात में कमी लाने का प्रयास करेगी।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर लगे प्रतिबंधो की समीक्षा:

❒ विदेशी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) से संबंधित नियमों को आसान बनाने से लेकर कॉरपोरेट बांड बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के उपाय किये गये हैं। इसके तहत एक कॉर्पोरेट इकाई में एफपीआई द्वारा किया जाने वाला निवेश उनके कॉर्पोरेट बॉण्ड पोर्टफोलियो के 20% से अधिक नहीं हो सकता है। एफपीआई जारी किये गए किसी भी कॉर्पोरेट बॉण्ड में 50% से अधिक निवेश नहीं कर सकते हैं।

मसाला बॉण्ड जारी करने वाले बैंकों प्रतिबंध नहीं:

❒ भारतीय निगमों को मसाला बॉण्ड की खरीद में वृद्धि करने के लिये सरकार 31 मार्च, 2019 तक मसाला बॉण्ड जारी करने वाले सभी बैंकों को छूट प्रदान करेगी।

❒ मसाला बॉण्ड भारत के बाहर जारी किये गए बॉण्ड होते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्रा की बजाय इन्हें भारतीय मुद्रा में निर्दिष्ट किया जाता है। डॉलर बॉण्ड के विपरीत (जहाँ उधारकर्त्ता को मुद्रा जोखिम उठाना पड़ता है) मसाला बॉण्ड में निवेशकों को जोखिम उठाना पड़ता है। नवंबर 2014 में विश्व बैंक के इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा पहला मसाला बॉण्ड जारी किया गया था।

विनिर्माण कंपनियों को 5 करोड़ डॉलर तक की ईसीबी को एक्सेस करने की अनुमति:

❒ ईसीबी के माध्यम से 50 मिलियन डॉलर तक की उधार लेने वाली विनिर्माण कंपनियाँ केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ऐसा करने में सक्षम होंगी। उल्लेखनीय है कि पहले यह अनुमति तीन साल की अवधि के लिये थी।

बाह्य वाणिज्यिक उधार के संदर्भ में आधारभूत संरचना ऋण हेतु अनिवार्य हेजिंग शर्तों की समीक्षा:

❒ बाह्य वाणिज्यिक उधार मार्ग के माध्यम से आधारभूत संरचना ऋण के लिये अनिवार्य हेजिंग (वित्तीय हानि से बचाव) स्थितियों की समीक्षा की जाएगी। गौरतलब है कि वर्तमान में इन ऋणों को संभालने के लिये उधारकर्त्ताओं पर कोई बाध्यता नहीं है।

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

देना बैंक, विजया बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय की घोषणा

चर्चा में क्यों?

❒ सरकार ने 17 सितंबर 2018 को देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय किए जाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार द्वारा देश की बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने हेतु तीनों सरकारी बैंकों को मिलाकर एक करने का फैसला लिया गया है।

मुख्य तथ्य

❒ वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई आर्थिक समीक्षा बैठक के बाद मीडिया को दी गई जानकारी में बताया गया कि सरकार विलय के बाद बनने वाले बैंक को पूंजीगत सहायता देती रहेगी।

❒ गौरतलब है कि सरकार ने इस वर्ष का बजट पेश करने के दौरान बैंकों के एकीकरण का खाका पेश किया था।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- अभी देश में बैंक ऑफ बड़ौदा के 5,502, विजया बैंक के 2,129 और देना बैंक के 1,858 ब्रांच हैं। इनके विलय के बाद नए बैंक के 9,489 ब्रांच हो जाएंगे। इसी प्रकार बैंक ऑफ बड़ौदा के अभी 56,361 कर्मचारी, विजया बैंक के 15,874 कर्मचारी और देना बैंक के 13,440 कर्मचारी हैं।
- इन्हें मिलाकर नए बैंक में कुल कर्मचारियों की संख्या 85,675 हो जाएगी। इसके साथ ही, नए बैंक का कुल बिजनस 14 लाख 82 हजार 422 करोड़ रुपये का हो जाएगा।

बैंकों के विलय से होने वाले लाभ

- विलय से बना नया बैंक देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा।
- आर्थिक पैमानों पर यह मजबूत प्रतिस्पर्धी बैंक होगा।
- इसमें तीनों बैंकों के नेटवर्क्स एक हो जाएंगे, डिपॉजिट्स पर लागत कम होगी और सब्सिडियरीज में सामंजस्य होगा।
- इससे ग्राहकों की संख्या, बाजार तक पहुंच और संचालन कौशल में वृद्धि होगी. साथ ही, ग्राहकों को ज्यादा प्रॉडक्ट्स और बेहतर सेवा ऑफर किए जा सकेंगे।
- विलय के बाद भी तीनों बैंकों के एंप्लॉयीज के हितों का संरक्षण किया जाएगा।
- बैंकों की ब्रैंड इक्विटी सुरक्षित रहेगी।
- तीनों बैंकों को फिनैकल सीबीएस प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा।
- नए बैंक को पूंजी दी जाएगी।
- गौरतलब है कि इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोगी बैंकों का एसबीआई में विलय किया जा चुका है. सरकार का मानना है कि कुछ बैंकों के संचालन लागत के मुकाबले फायदे कम हैं, इसलिए बैंकों के विलय को लेकर लगातार विचार-विमर्श होता रहा है। इसी क्रम में सरकार द्वारा देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय की घोषणा की गई।

स्रोतः बिजनेस स्टैंडर्ड

सरकार द्वारा जन-धन योजना जारी रखने एवं ओवरड्राफ्ट सीमा दोगुनी करने की घोषणा

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना को विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना बताते हुए इसे आगे जारी रखने की घोषणा की है। साथ ही, इसका प्रति परिवार की अपेक्षा प्रति वयस्क व्यक्ति तक विस्तार करने का निर्णय लिया है।
- इसके अतिरिक्त जनधन खाते में मिलने वाली ओवर ड्राफ्ट (ओडी) और बीमा राशि को दोगुना कर दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 05 सितंबर 2018 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिये गये।

मुख्य तथ्य

- प्रारंभ में जन-धन योजना को चार वर्षों के लिए शुरू किया गया था जो इस वर्ष 14 अगस्त को समाप्त हो गया।
- अब यह योजना अगले फैसले तक जारी रहेगी और इसे कब समाप्त करना है, यह निर्णय बाद में लिया जायेगा।
- जन-धन योजना का उद्देश्य पहले एक परिवार एक खाता था लेकिन अब हर परिवार के सभी वयस्कों का जनधन खाता खोला जा सकेगा।
- वर्तमान जन-धन खातों पर ओवरड्राफ्ट (ओडी) की सीमा 5,000 रुपये ही रहेगी लेकिन नये खातों के लिए यह सीमा 10 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है।
- इसके साथ ही इसके तहत मिले 'रुपे' कार्ड से जुड़ी दुर्घटना बीमा योजना के तहत मिलने वाली राशि की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है जो 28 अगस्त 2018 के बाद खुलने वालों खाताधारकों के लिए होगा।
- दो हजार रुपये तक की ओडी के लिए कोई शर्त नहीं होगा और ओडी लेने वालों की आयु पहले 18 से 60 वर्ष थी जिसे बढ़ाकर अब 65 वर्ष कर दी गयी है।
- अटल पेंशन योजना में 1.11 लाख लोग जुड़े हैं और यह योजना अगस्त 2018 में समाप्त हो रही थी लेकिन अब इसे आगे भी जारी रखने का फैसला किया गया है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

जन-धन योजना

- विश्व बैंक ने जन-धन योजना को विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना बताया है क्योंकि पिछले चार वर्षों में भारत में इसके तहत 32.41 करोड़ खाते खुले हैं जबकि पूरी दुनिया में यह 51.50 करोड़ है।
- इनमें से 53% खाते ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के हैं और 59% बैंक खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। अभी तक 83% बैंक खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है और 24.4 करोड़ लोगों के पास 'रुपे' कार्ड है।
- 31 जनवरी 2015 से पहले के खातों में 30 हजार रुपए के बीमा की सुविधा से 4981 परिवारों को लाभ मिला है. एक रुपया महीना की जीवन बीमा योजना को 13.98 करोड़ लोगों ने अपनाया है और उसमें 19 हजार 436 दावों का निस्तारण किया गया है।

स्रोत: द हिंदू

आशा और आंगनवाड़ी श्रमिकों के पारिश्रमिक में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितम्बर 2018 को आशा और आंगनवाड़ी योजना से जुड़े लोगों को मिलने वाले पारिश्रमिक में वृद्धि की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने देश की आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया के जरिए सीधे संवाद किया।
- आशा और आंगनवाड़ी श्रमिकों के यह बढ़ा हुआ पारिश्रमिक अगले माह यानी एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने देशभर के आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में केंद्र के हिस्से में बढ़ोतरी कर दी है।

मुख्य तथ्य

- आशाकर्मियों की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर दुगुना किया जाएगा वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रुपये से बढ़ा कर 4500 रुपये करने का फैसला किया गया है।
- जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 2250 रुपए था, उन्हें अब 3500 रुपए मिलेगा. आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 1500 रुपए के स्थान पर 2250 रुपए मिलेंगे।
- आशा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मुफ्त दी जाएंगी. इसका मतलब हुआ कि दो-दो लाख रुपए की इन दोनों बीमा योजना के तहत कोई प्रीमियम नहीं देना होगा और यह खर्च सरकार उठाएगी।
- प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि विभिन्न तकनीकों जैसे कि कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (आईसीडीएस-सीएएस) का उपयोग करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राप्त होंगे। 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के प्रोत्साहन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका के प्रदर्शन पर आधारित होंगे।
- प्रधानमंत्री ने देश भर में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और एएनएम (सहायिका नर्स मिडवाइफ) की टीमों के साथ संवाद किया। उन्होंने आपस में मिल-जुल कर काम करने, अभिनव साधनों एवं प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने, स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं बेहतर ढंग से सुलभ कराने और 'पोषण' अभियान के लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात देश भर में कुपोषण में कमी करने के उद्देश्य से अथक प्रयास करने के लिए इन कार्यकर्ताओं की सराहना की। उल्लेखनीय है कि संसद में भी विभिन्न दलों के सदस्य आशा कर्मियों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने की समय-समय पर मांग करते रहे हैं।
- प्रधानमंत्री ने कहा की सरकार का ध्यान पोषण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने पर है। टीकाकरण की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। इससे महिलाओं और बच्चों को खासी मदद मिलेगी। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों और 85 लाख से ज्यादा महिलाओं का टीकाकरण कराया गया है।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

नीति आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र के मध्य सतत विकास फ्रेमवर्क पर समझौता

चर्चा में क्यों?

- नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के साथ 2018-2022 के लिए सतत विकास फ्रेमवर्क पर 28 सितंबर 2018 को हस्ताक्षर किये।
- इस समझौते के तहत सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करेंगे।
- नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और भारत में संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय संयोजक यूरी अफान्सीव ने फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किये।

फ्रेमवर्क के प्रमुख तथ्य

- फ्रेमवर्क में भारत सरकार और भारत में संयुक्त राष्ट्र के दल के बीच विकास में सहयोग की रणनीति तय की गयी है जिससे सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।
- इसमें 'गरीबी एवं शहरीकरण', 'स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता', 'शिक्षा', 'पोषण एवं खाद्य सुरक्षा', 'जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा और आपदा से निपटने की तैयारी', 'कौशल, उद्यमिता एवं रोजगार सृजन' तथा 'लैंगिक समानता एवं युवा विकास' पर फोकस होगा।
- फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन के लिए कुल 11,000 करोड़ के रुपये बजट का प्रावधान है जिसमें 47 प्रतिशत क्रियान्वयन के दौरान निजी तथा सरकारी क्षेत्र समेत विभिन्न स्रोतों से जुटाया जायेगा।
- इसमें कम आय वाले सात राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र और नीति आयोग द्वारा चिह्नित अति पिछड़े जिलों पर फोकस किया जायेगा।

मुख्य उद्देश्य

- वर्ष 2022 में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगाँठ मनायी जानी है और इसलिए देश के विकास में 2018 से 2022 का काल महत्वपूर्ण है।
- इस सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क का महत्त्व और बढ़ जाता है. यह वर्ष 2022 तक 'न्यू इंडिया' के निर्माण को गति देगा।
- भारत और संयुक्त राष्ट्र की टीमें मिलकर गरीब, कमजोर तथा हाशिये पर स्थित तबकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा ताकि उन्हें देश के तेज आर्थिक विकास का लाभ मिल सके।

स्रोत: द हिंदू

भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 7.8% रहेगी: फिच रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने मार्च 2019 में खत्म होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7.4% से बढ़ाकर 7.8% कर दिया।
- एजेंसी ने कहा कि आने वाले दिनों में वित्तीय स्थिति की मजबूती, बढ़ते तेल खर्च और बैंकों की कमजोर बैलेंस शीट जैसी चुनौतियों पर नजर रखनी होगी।

मुख्य तथ्य:

- फिच रेटिंग्स ने अपनी 'ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक' (वैश्विक आर्थिक परिदृश्य) शीर्षक ताजा रिपोर्ट में वित्तीय स्थिति के तंग होने, तेल आयात बिल बढ़ने और बैंकों के कमजोर बैलेस-शीट को भारत की वृद्धि के रास्ते की चुनौतियों में गिना है।
- फिच ने कहा है की 2018 की दूसरी तिमाही (चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही) में उम्मीद से बेहतर परिणाम को देखते हुए हमने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पूर्व के 7.4 प्रतिशत के वृद्धि दर के पूर्वानुमान में संशोधन कर उसे 7.8 फीसदी कर दिया।
- चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में आर्थिक वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत थी. फिच ने पहले इस तिमाही के लिए जीडीपी में 7.7 फीसदी की वृद्धि का अनुमान लगाया था।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में वृद्धि दर के पूर्वानुमान में 0.2 फीसदी की कमी करते हुए उसे 7.3 प्रतिशत पर रखा है।
- रिपोर्ट में फिच ने कहा कि 2019 की शुरुआत में होने वाले चुनाव के मद्देनजर भारत की राजकोषीय नीति के विकास दर के लिहाज से अनुकूल रहने की संभावना है।
- सार्वजनिक क्षेत्र, खास कर सरकारी उद्यमों द्वारा अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश बढ़ाए जाने निवेश/जीडीपी अनुपात में गिरावट का रुझान रोकने में मदद मिली है।
- फिच रेटिंग्स ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्तीय स्थिति के तंग होने, तेल आयात बिल बढ़ने और बैंकों के कमजोर बैलेंसशीट को भारत के लिए बड़ी चुनौतियां माना है। फिच ने रिपोर्ट में कहा है की रुपये में गिरावट को लेकर आरबीआई की कोशिशों के बावजूद ब्याज दरों में अनुमान से अधिक इजाफा किया गया है।

स्रोतः बिजनेस स्टैंडर्ड

कैबिनेट ने जीएसटीएन को सरकारी ईकाई घोषित करने हेतु प्रस्ताव स्वीकार किया

चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु व सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को सरकारी इकाई के रूप में अंगीकृत करने के लिए लाये गये प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस फैसले से जीएसटीएन की शत प्रतिशत हिस्सेदारी सरकार के पास आ जाएगी।
- जीएसटीएन के माध्यम से वस्तु व सेवा कर के पंजीकरण, रीटर्न फाइलिंग, टैक्स अदायगी, रिफंड प्रसंस्करण इत्यादि कार्य किये जाते हैं।

पृष्ठभूमि

- वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में मई 2018 में वस्तु व सेवा कर परिषद् की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था।
- यह सहमति व्यक्त की गई कि जीएसटीएन को सरकारी इकाई बनाया जायेगा।
- इसमें जीएसटीएन की आधी अर्थात 50 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र सरकार तथा शेष 50 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्यों को दिए जाने पर एकमत राय व्यक्त की गई थी।
- जीएसटीएन पोर्टल पर 1.1 करोड़ से अधिक व्यापारिक इकाईयां पंजीकृत हैं।
- जीएसटीएन टैक्स कलेक्शन से लेकर डाटा एनालिटिक्स जैसे कार्य करता है, इसलिए सरकार के लिए यह सूचना प्राद्योगिकी ईकाई की रीढ़ की हड्डी के समान है।

वस्तु व सेवा कर नेटवर्क

- जीएसटीएन की स्थापना वर्ष 2013 में एक गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी तथा निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में की गयी थी। इसकी स्थापना जीएसटी के लिए आईटी अधोसंरचना व सेवा उपलब्ध करवाने के लिए की गयी थी।
- वर्तमान में जीएसटीएन में केंद्र सरकार और राज्यों सरकारों की हिस्सेदारी 49% (24.5% ख़ 24.5%) है, शेष 51% हिस्सेदारी पांच निजी वित्तीय संस्थानों आईसीआईसीआई बैंक, एनएसई, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक व एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास हैं।
- जीएसटी के तहत प्राप्त होने वाले यूजर चार्ज का उपयोग इसी सिस्टम को आत्म-निर्भर बनाने के लिए किया जाता है।

स्रोतः बिजनेस स्टैंडर्ड

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े परिचालन दिशा-निर्देशों में संशोधन

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने 18 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत बीमा दावों के निपटान में देरी होने की स्थिति में राज्यों और बीमा कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान शामिल करने का फैसला किया है।
- नए परिचालन दिशा-निर्देशों में बीमा कंपनियों के आकलन के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया के साथ-साथ सेवाएं मुहैया कराने में अप्रभावी पाए जाने पर इस योजना से हटाए जाने का विवरण भी दिया गया है। सरकार ने प्रायोगिक आधार पर पीएमएफबीवाई के दायरे में बारहमासी बागवानी फसलों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए नए दिशानिर्देश:

- यदि कोई बीमा कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान के दावे का भुगतान करने में देरी करती है तो बीमा कंपनी को मुआवजे पर 12 प्रतिशत ब्याज का भी भुगतान करना होगा।
- बीमा कंपनियों की ओर से अपनी मांग प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के तीन माह बाद सब्सिडी में राज्य का हिस्सा जारी करने पर विलम्ब होने के कारण राज्य सरकारें 12 प्रतिशत ब्याज देंगी।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत किसानों के दावे का निपटारा दो माह के भीतर होगा।
- नए परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, जंगली जानवरों के हमले के कारण फसल नुकसान होने की स्थिति में भी बीमा कवर देने को इस योजना में जोड़ा गया है। इसे प्रायोगिक आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा।
- लाभार्थियों द्वारा फिर से लाभ उठाने की स्थिति से बचने के लिए 'आधार' नंबर को इसमें अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा।
- इस योजना के तहत और ज्यादा संख्या में गैर कर्जदार किसानों का बीमा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के अलावा बीमा कंपनियों को पिछले संबंधित सीजन की तुलना में 10 प्रतिशत ज्यादा गैर कर्जदार किसानों को नामांकित करने का लक्ष्य भी दिया जाता है।
- बीमा कंपनियों को इस योजना का प्रचार-प्रसार करने और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति सीजन प्रति कंपनी सकल प्रीमियम का 0.5 प्रतिशत अनिवार्य रूप से खर्च करना होगा।
- नए परिचालन दिशा-निर्देशों के तहत अनेक कारगर समाधान पेश करने की बदौलत इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों से पार पा लिया गया है।
- बीमा कंपनियों के लिए यह जरूरी नहीं है कि वे अग्रिम सब्सिडी के लिए कोई अनुमान व्यक्त करें. एकमुश्त प्रीमियम सब्सिडी को सीजन के आरंभ में ही जारी कर दिया जाएगा जो भारत सरकार/राज्य की सब्सिडी के रूप में पिछले वर्ष के संबंधित सीजन की सब्सिडी में कुल हिस्सेदारी के 50 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक पर आधारित होगी।
- अंतिम कारोबारी आंकड़ों पर आधारित पोर्टल पर उपलब्ध समस्त कवरेज डेटा के मिलान के बाद अंतिम किस्त का भुगतान किया जाएगा। इससे किसानों के दावों के निपटान में पहले के मुकाबले कम देरी होगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

- किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिये नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी।
- यह योजना सभी किसानों के लिए है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुयी हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम करायेगी।
- इस योजना के लिये 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च किया जायेगा. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत, किसानों को बीमा कम्पनियों द्वारा निश्चित, खरीफ की फसल के लिये 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान करेगा।
- इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचा रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके।

स्रोत: पीआईबी

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

'द फ्यूचर ऑफ जॉब्स' रिपोर्ट: विश्व आर्थिक मंच

चर्चा में क्यों?

- विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा हाल ही में 'द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018' रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2025 तक 50% से अधिक नौकरियों पर स्वचालित मशीनों का कब्जा होगा।
- यह अनुमान लगाया गया है कि स्वचालित रोबोट के अधिक इस्तेमाल के कारण इंसानों के काम करने का तरीका तथा मानव श्रम भी हमेशा के लिए बदल जाएगा। विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने कामों के मशीनीकरण की रफ्तार तथा उसमें आने वाले बदलाव का विश्लेषण करते हुए यह अनुमान लगाया है।

'द फ्यूचर ऑफ जॉब्स' :

मुख्य तथ्य

- 'द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018' रिपोर्ट में उद्योग क्षेत्रों की विस्तृत श्रृंखला से 300 से अधिक वैश्विक कंपनियों को शामिल किया गया है।
- इस सर्वे में 1.5 करोड़ से अधिक कर्मचारी और 20 विकसित तथा उभरती अर्थव्यवस्थाएँ शामिल थीं जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 70 प्रतिशत धारण करती हैं।
- वर्तमान में कुल कार्य का 71% हिस्सा मानव श्रम द्वारा होता है।
- वर्ष 2022 तक आते-आते यह हिस्सा 58% तक रह जाएगा, वहीं 2025 तक यह हिस्सेदारी 48% पर सिमट जाएगी।
- रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रोबोट क्रांति यानी ऑटोमेशन की इस प्रक्रिया के दौरान अगले पाँच सालों में 5 करोड़ 80 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा।
- लगभग 20 देशों की कंपनियों और 1.5 करोड़ कर्मचारियों के सर्वे के आधार पर विश्व आर्थिक मंच का अनुमान है कि इन तकनीकों से दुनियाभर में करीब 13.3 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी।
- ऑटोमेशन (रोबोट क्रांति) के आने से जिन नौकरियों के खत्म होने की उम्मीद है, उनमें डेटा एंट्री क्लर्क, अकाउंटिंग क्लर्क और परोल क्लर्क जैसे वाइट कॉलर जॉब शामिल हैं।
- विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार आज मशीनों के माध्यम से जहां 29 प्रतिशत कार्य हो रहे हैं. वहीं वर्ष 2025 तक मौजूदा कार्यभारों का तकरीबन आधा मशीनों के माध्यम से सम्पन्न होगा। इस अध्ययन के अनुसार ई-कॉमर्स एवं सोशल मीडिया सहित सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस जैसी जिन नौकरियों में ''मानव कौशल'' की आवश्यकता होती है उनमें मानव कौशल में इजाफा देखा जा सकता है। इसी तरह से रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और प्रबोधन जैसे कार्यों में भी मानव कौशल बना रहेगा।

स्रोतः द हिंदू

सेबी ने शेयर बायबैक नियमों को संशोधित किया

चर्चा में क्यों?

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 17 सितम्बर 2018 को शेयरों को वापस खरीदने (बायबैक) के नियमों में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य शेयर बायबैक के लिए सार्वजनिक रूप से कोई घोषणा करने की जरूरत पर और ज्यादा स्पष्टता लाना है।
- सेबी के अनुसार क्रेडिट रेटिंग संस्थाएं पब्लिक या राइट्स इश्यू के जरिये ऑफर की गई सिक्युरिटीज की रेटिंग के अलावा और किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल नहीं होंगी।

मुख्य तथ्यः

- सेबी के मुताबिक रेटिंग कंपनी को वित्तीय प्रतिभूतियों की रेटिंग तय करने और आर्थिक अथवा वित्तीय शोध एवं विश्लेषण कार्य अलावा दूसरे कामों को अलग कंपनी में बांटने का नियम लागू किया है। इसके लिए दो साल का समय दिया गया है।
- नए नियमों के तहत सेबी ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों को किसी कंपनी में शेयर खरीदने या ओपन ऑफर में बोली लगाने से प्रतिबंधित कर दिया है।
- सेबी ने 11 सितंबर को जारी अधिसूचना में कहा कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी किसी भी कंपनी के ओपन ऑफर के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बोली नहीं लगा सकता है। इसके साथ ही कंपनी अधिनियम 2013 के अनुरूप 'मुक्त आरक्षित भंडार' के बारे में स्पष्टीकरण को नये ढांचे में शामिल किया गया है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- सेबी ने भाषा के सरलीकरण, अस्पष्टता खत्म करने और अप्रैल 2014 में अस्तित्व में आए नए कंपनी कानून के हिसाब से नए रेफरेंस जोड़ने के लिए शेयर बायबैक के नियमों में संशोधन किया है।
- कोई भी कंपनी जिसे शेयरों की वापस खरीद की अनुमति दी जाती है उसे दो कार्यदिवसों के भीतर इसकी सार्वजनिक घोषणा करनी होगी।

बायबैक क्या है?

- बायबैक एक निर्धारित समय में पूरी की जाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें निवेशकों के अतिरिक्त शेयरों को अपने सरप्लस का इस्तेमाल कर खुले बाजार से खरीदा जाता है. ये शेयर बाजार मूल्य या उससे ज्यादा कीमत पर खरीदे जाते हैं।
- अधिसूचना के मुताबिक कंपनी निदेशक मंडल की बायबैक के लिये मंजूरी मिलने और इस पेशकश को स्वीकार करने वाले शेयरधारकों को भुगतान मिलने की तिथि को बायबैक अवधि के तौर पर परिभाषित किया गया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी):

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है. इसकी स्थापना सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 में हुई।
- सेबी का मुख्यालय मुंबई में हैं और क्रमशः नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
- सेबी के अस्तित्व में आने से पहले पूंजी निर्गम नियंत्रक नियामक प्राधिकरण था, जिसे पूंजी मुद्दे (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त थे।
- सेबी का प्रमुख उद्देश्य भारतीय स्टाक निवेशकों के हितों का उत्तम संरक्षण प्रदान करना और प्रतिभूति बाजार के विकास तथा नियमन को प्रवर्तित करना है।

स्रोतः इकोनॉमिक टाइम्स

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 12 सितंबर 2018 को एक नई समग्र योजना 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (पीएम-आशा) को मंजूरी प्रदान की है।

मुख्य तथ्यः

- यह किसानों की आय के संरक्षण की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है जिससे किसानों के कल्याण में काफी हद तक सहूलियत होने की आशा है।
- सरकार उत्पादन लागत का डेढ़ गुना तय करने के सिद्धांत पर चलते हुए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में पहले ही वृद्धि कर चुकी है।
- यह उम्मीद की जा रही है कि एमएसपी में वृद्धि की बदौलत राज्य सरकारों के सहयोग से खरीद व्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी।

'पीएम-आशा' के घटक

- मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस)
- मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना (पीडीपीएस)
- निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट पायलट योजना (पीपीपीएस)
- धान, गेहूं एवं पोषक अनाजों/मोटे अनाजों की खरीद के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) की अन्य मौजूदा योजनाओं के साथ-साथ कपास एवं जूट की खरीद के लिए कपड़ा मंत्रालय की अन्य वर्तमान योजनाएं भी जारी रहेंगी, ताकि किसानों को इन फसलों की एमएसपी सुनिश्चित की जा सके।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

व्यय

- कैबिनेट ने 16,550 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सरकारी गारंटी देने का फैसला किया है जिससे यह कुल मिलाकर 45,550 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई है।
- इसके अलावा खरीद परिचालन के लिए बजट प्रावधान भी बढ़ा दिया गया है और पीएम-आशा के क्रियान्वयन के लिए 15,053 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना है, जिसकी घोषणा वर्ष 2018 के केन्द्रीय बजट में की गई है।
- सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत उत्पादकता बढ़ाने, खेती की लागत घटाने और बाजार ढांचे सहित फसल कटाई उपरांत प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
- अनेक बाजार सुधारों को लागू किया गया है। इनमें मॉडल कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम, 2017 और मॉडल अनुबंध खेती एवं सेवा अधिनियम, 2018 भी शामिल हैं। अनेक राज्यों ने कानून के जरिए इन्हें अपनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं।
- एक नया बाजार ढांचा स्थापित करने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि किसानों को उनकी उपज के उचित या लाभकारी मूल्य दिलाये जा सकें। इनमें ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) की स्थापना करना भी शामिल है, ताकि खेतों के काफी निकट ही 22,000 खुदरा बाजारों को प्रोत्साहित किया जा सके।
- इसी तरह ई-नाम के जरिए एपीएमसी पर प्रतिस्पसर्धी एवं पारदर्शी थोक व्यापार सुनिश्चित करना और एक व्यवस्थित एवं किसान अनुकूल निर्यात नीति तैयार करना भी इन प्रयासों में शामिल हैं।

स्रोत: पीआईबी

डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष की शुरुआत

चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि का शुभारंभ किया।

मुख्य तथ्य:

- इस योजना से 50 हजार गांवों में 95 लाख दूध उत्पादकों के लाभान्वित होंगें। इसके साथ ही अनेक कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल कर्मियों को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा।
- विश्व बैंक पोषित राष्ट्रीय डेयरी प्लान चरण- 1 योजना का कार्यान्वयन भी एनडीडीबी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से संबंधित राज्य के सहकारी दुग्ध संगठनों/दुग्ध फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है। सरकार ने इस योजना का क्रियान्वयन 14 राज्यों से बढ़ाकर 18 राज्यों में कर दिया गया है।

योजना की विशेषताएं

- इस योजना के तहत प्रतिदिन 126 लाख लीटर की अतिरिक्त दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता, प्रतिदिन 210 टन दूध को सुखाने की क्षमता, 28000 ग्रामीण स्तर पर बल्क मिल्क कूलर की स्थापना से प्रतिदिन 140 लाख लीटर की दुग्ध अवशीतन क्षमता का सृजन किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत दुग्ध सहकारी संस्थाओं को 8004 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता ऋण के रूप मे 6.5% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान की जाएगी जिसकी भरपाई 10 वर्ष की अवधि में करनी होगी।
- ऋण पर भारत सरकार ने ब्याज सब्सिडी का प्रावधान भी रखा है. अब तक 1148 करोड़ रुपये की कुल 15 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनमें कर्नाटक (776.39 करोड़ रुपये - 5 उप-परियोजनाएं), पंजाब (318.01 करोड़ रुपये की 4 उप-परियोजनाएं) और हरियाणा (54.21 करोड़ रुपये की 6 उप-परियोजनाएं) शामिल हैं।
- उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत वर्तमान सरकार द्वारा मार्च, 2018 तक 29 राज्यों से आये प्रस्तावों के लिए 1600 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 686 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। 20 गोकुल ग्राम इसी योजना के अंतर्गत स्थापित किये जा रहे हैं।

स्रोत: पीआईबी

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

इस्पात मंत्रालय ने पहली बार द्वितीयक इस्पात क्षेत्र को पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

✸ हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने पहली बार द्वितीयक इस्पात क्षेत्र को पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की।

मुख्य तथ्य:

- इन पुरस्कारों का शुभारंभ इसलिए किया गया है ताकि द्वितीयक इस्पात क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सके।
- दरअसल, द्वितीयक इस्पात क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन के लिए एक विकास इंजन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के दमदार प्रदर्शन से भारत में इस्पात उत्पादन में और भी ज्यादा वृद्धि संभव हो पाई है।
- भारत सरकार ने समग्र क्षमता को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर करने के लिए अनेक पहल की हैं।
- कम ऊर्जा खपत वाली परियोजनाओं (ऊर्जा संरक्षण एवं जीएचजी उत्सर्जन का नियंत्रण) और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) से जुड़ी गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करना।
- संस्थागत सहायता को मजबूती प्रदान करना। विदेश से लागत से भी कम कीमत पर होने वाले आयात से घरेलू उत्पादकों को एंटी-डंपिंग उपायों के जरिए संरक्षण प्रदान करना।
- कम ऊर्जा खपत वाली प्रौद्योगिकियों एवं अभिनव उपायों को अपनाने वाली प्रगतिशील इकाइयों (यूनिट) के उत्कृष्ट कार्यकलापों की सराहना एवं प्रोत्साहित करने के लिए एक पुरस्कार योजना शुरू करना।

विकास संभावनाएं:

- विकास के वर्तमान रुख को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि भारत इस क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाकर चीन के बाद दूसरे पायदान पर पहुंच जाएगा।
- राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 में वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।
- उत्पादन क्षमता पहले ही बढ़कर वर्ष 2017-18 में 137.97 मिलियन टन (एमटी) के स्तर पर पहुंच चुकी है।

द्वितीयक इस्पात क्षेत्र: महत्व:

- द्वितीयक इस्पात क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ लोगों तक है जिनके जरिए यह ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली मांग को पूरा करता है।
- प्राथमिक इस्पात क्षेत्र के साथ तालमेल बैठाते हुए तेजी से प्रगति कर रहे द्वितीयक इस्पात क्षेत्र में देशव्यापी विकास एवं अवसरों के लिए असीम क्षमता है।
- प्राथमिक इस्पात क्षेत्र के मुकाबले इस क्षेत्र को कुछ विशिष्ट बढ़त हासिल है जैसे कि इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम पूंजी एवं भूमि की आवश्यकता पड़ती है और यह विशेष टुकड़ों एवं ग्राहकों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने वाले उत्पादों को तैयार करने में सक्षम है।
- अपनी इन विशेषताओं के बल पर इस क्षेत्र द्वारा वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात की उत्पादन क्षमता के विकास लक्ष्य को हासिल करने में मुख्य भूमिका निभाना तय है।

क्षेत्र की संरचना:

- द्वितीयक इस्पात क्षेत्र में कई उप-क्षेत्रों जैसे कि स्पंज आयरन इकाइयों, ईएएफ, आईएफ इकाइयों, रि-रोलिंग मिलों, कोल्ड रोलिंग मिलों, जस्ता चढ़ाने वाली इकाइयों एवं वायर ड्राइंग इकाइयों के साथ-साथ विभिन्न उप-क्षेत्र शामिल हैं।
- इन उप-क्षेत्रों में 1 मिलियन टन से कम की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले टिनप्लेट उत्पादक भी शामिल हैं।
- ये उप-क्षेत्र देश में मूल्य-वर्द्धित उत्पादों का उत्पादन करने संबंधी मांग को पूरा करते हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

पृष्ठभूमि:

- उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर में वर्ष 1928 में एक छोटी स्टील रि-रोलिंग मिल (एसआरआरएम) के साथ सामान्य शुरुआत हुई थी।
- यह उद्योग आने वाले वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी तेजी से प्रगति पथ पर अग्रसर हो गया।
- वर्ष 1968 तक यह क्षेत्र हर वर्ष और भी ज्यादा प्रगति कर लगभग 5 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन करने लगा।
- पश्चिम बंगाल में कोलकाता, महाराष्ट्र में मुम्बई और पंजाब में मंडी गोबिन्दगढ़ देश भर में द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के आरंभिक तीन क्लस्टर थे।
- अस्सी के दशक के आरंभ में इंडक्शन फर्नेस (आईएफ) मेल्टिंग यूनिटों का आगमन होने से द्वितीयक इस्पात क्षेत्र का और ज्यादा विस्तार देश भर में हो गया।

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

अटल पेंशन योजना अनिश्चितकाल तक बढ़ाई गई

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना का अनिश्चितकाल तक विस्तार करने का फैसला किया है, जो अगस्त 2018 में खत्म हो रहा था। इसके अलावा उम्र सीमा में पांच साल का विस्तार किया गया है तथा दुर्घटना बीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है।

मुख्य तथ्य:

- अटल पेंशन योजना (एपीवाई) एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे सरकार ने 2015 में 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का पेंशन मुहैया कराने के लिए लांच किया था।
- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि इस योजना का लक्ष्य घरों को दायरे में लाने की बजाए लोगों को इसके दायरे में लाने पर है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सरकार की इस फ्लैगशिप योजना का लाभ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उठाया है।

अटल पेंशन योजना: नई घोषणा

- पहले इस योजना में 18 से 60 साल तक के उम्र के व्यक्ति ही भाग ले सकते थे लेकिन औसत जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी को देखते हुए हमने अब अधिकतम सीमा बढ़ाकर 65 साल कर दी गई है।
- 28 अगस्त के बाद खोले गए सभी खातों का दुर्घटना बीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है।
- इस योजना की ओवरड्राफ्ट सुविधा को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है।
- अटल पेंशन योजना का आवेदन देने के लिए आपके पास आधार नंबर, बैंक अकाउंट और वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए।
- यह वैकल्पिक योजना है। इस योजना में लोगों को 80 CCD के तहत टैक्स छूट भी मिलती है।
- देश के सभी बड़े बैंक अटल पेंशन योजना में खाता खोलने की सुविधा देते हैं। दाज घर में जाकर भी इसका खाता खोल सकते हैं।

अटल पेंशन योजना: विशेषताएं

- इस योजना में हर महीने, तिमाही और छमाही आधार पर निवेश किया जा सकता है। इसमें सरकार जमाकर्ता के कुल योगदान में 50 फीसदी या 1000 रुपए जो भी कम होगा वह जोड़ेगी। यह रकम 5 वर्ष के लिए डाली जाएगी। निवेशक की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को भी यह पेंशन मिलती रहेगी। पत्नी (या पति) की मृत्यु के बाद 60 वर्ष की आयु पर जो भी आपके पेंशन फण्ड में राशि थी, वह आपके नॉमिनी को दे दी जायेगी।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं स्वास्थ्य

'अप्सरा' परमाणु रिएक्टर 09 वर्ष बाद पुनः आरंभ किया गया

चर्चा में क्यों?

✸ देश के सबसे पुराने न्यूक्लियर रिएक्टर 'अप्सरा' को अधिक क्षमता के साथ फिर से शुरू किया गया है। इस रिएक्टर की मरम्मत कर इसे नया रूप देने के लिए 2009 में स्थाई तौर पर बंद कर दिया गया था।

मुख्य तथ्यः

❒ रिएक्टर को और बेहतर बनाने के बाद 10 सितंबर 2018 को फिर से शुरू किया गया। अप्सरा रिएक्टर के इस मॉडल को 'अप्सरा-अपग्रेडेड' (अप्सरा-यू) के नाम से जाना जायेगा।

❒ अप्सरा एक हल्के स्विमिंग पूल जैसा रिएक्टर है जिसकी अधिकतम क्षमता एक मेगावाट थर्मल है। यह रिएक्टर एल्यूमीनियम मिश्रित प्लेटों के रूप में समृद्ध यूरेनियम को प्रयोग करता है।

अप्सरा-यू अनुसंधान रिएक्टर

❒ अप्सरा अस्तित्व में आने के बाद 62 साल बाद उच्च क्षमता का यह स्विमिंग पूल आकार का रिएक्टर दोबारा आरंभ हुआ है।

❒ रिएक्टर, स्वदेशी, समृद्ध यूरेनियम (LEU) से बने प्लेट ईंधन तत्वों का उपयोग करता है।

❒ यह रिएक्टर चिकित्सा क्षेत्र के लिए स्वदेशी उत्पादन या रेडियो-आइसोटोप को लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ा देगा।

❒ इस रिएक्टर का इस्तेमाल विकिरण क्षति के अध्ययन, फोरेंसिक शोध, न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी और परिरक्षण प्रयोगों के लिए होता है।

❒ इस रिएक्टर की अधिकतम क्षमता एक मेगावाट थी जिसका उन्नयन कर इसे 2 मेगावाट किया गया है।

❒ इस अनुसंधान रिएक्टर द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की स्वास्थ्य सुविधाओं, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए जटिल सुविधाओं के निर्माण करने की क्षमता पर फिर से जोर दिया जायेगा।

स्रोतः द हिंदू

भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त 'युद्ध अभ्यास 2018' उत्तराखंड में शुरू

चर्चा में क्यों?

✸ भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 16 सितंबर 2018 से उत्तराखंड के अल्मोडा जिले में बसे चौबटिया में शुरू हो गया। यह अभ्यास 29 सितंबर 2018 को समाप्त होगा।

मुख्य तथ्य

❒ युद्ध अभ्यास-2018 सबसे लंबे चलने वाले संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यासों में से एक है और भारत तथा अमेरिका के बीच एक प्रमुख द्विपक्षीय रक्षा सहयोग प्रयास है।

❒ इस युद्ध अभ्यास का उद्घाटन सेना की मध्य कमान मुख्यालय में भव्य तरीके से हुआ। दोनों देशों ने अपने राष्ट्रगान और ध्वज के साथ इसकी शुरूआत की। इसके बाद निकाले गए मार्चपास्ट में अधिकारियों को सलामी दी गई। मार्च पास्ट का नेतृत्व भारतीय सेना के कमांडर कर्नल एसवी चेरियन और अमेरिका सेना के मेजर जनरल विलियम द्वारा किया गया।

❒ यह दोनों देशो के बीच 14 वां संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन दोनो देश बारी-बारी से करते हैं।

❒ पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग में काफी वृद्धि हुई है। इस संयुक्त अभ्यास से दोनो देशो की सेना के मध्य आपसी सहयोग ओर विकसित होगा। इससे पहले वर्ष 2017 में रूस के साथ व्लादिवोस्टोक में युद्ध अभ्यास में भारत की तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया था।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

उद्देश्य:

✸ इस अभ्यास का उद्देशय दोनों देशों की सेनाओं के बीच आतंक विरोधी ऑपरेशन में दक्षता को वृद्धि करना है। इस बार 'युद्ध अभ्यास' में बटालियन स्तरीय प्रशिक्षण तथा डिवीजन स्तरीय कमांड पोस्ट अभ्यास किया जा रहा है।

'युद्ध अभ्यास 2018' से संबंधित मुख्य तथ्य:

❒ इस संयुक्त युद्धाभ्यास में अमेरिकी सेना की ओर से प्रथम इन्फैंटी बटालियन, 23 इन्फैंटी रेजिमेन्ट, 2 स्टाइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम, 7 इन्फैंटी डिविजन ने प्रतिनिधित्व किया जबकि भारतीय सेना की ओर से कांगो ब्रिगेड, गरूड़ डिविजन, सूर्या कमान ने प्रतिनिधित्व किया।

❒ इस युद्धाभ्यास के दौरान जवाबी एवं आतंकवाद विरोधी कार्रवाईयों से निपटने की उनकी कार्यकुशलता तथा तकनीकी कौशल देखने को मिलेगा।

❒ इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं की ओर से निगरानी तथा ट्रेकिंग, उपकरण, आतंकवादियों से निपटने के लिए विशेष हथियारों, विस्फोटक और आईईडी डिटेक्टर्स अथवा नवीनतम संचार उपकरणों का प्रयोग किया जायेगा।

❒ दोनों देश संयुक्त रूप से किसी प्रकार के खतरों से निपटने के लिए एक सुविकसित कुशल ड्रिल को अमल में लाकर योजनाबद्ध तरीके से प्रशिक्षण लेगें जिसे संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए आयोजित ऑपरेशनों में प्रयोग किया जा सके।

❒ दोनों देशों के सैन्य विशेषज्ञ पारस्परिक लाभ हेतु विविध विषयों पर एक दूसरे के अनुभवों को साझा करने के लिए विचार-विमर्श भी करेगें।

❒ इस संयुक्त अभ्यास में अमेरिकी और भारतीय सेना के 350-350 जवान भाग ले रहे हैं।

❒ अभ्यास के दौरान प्रारंभ में दोनो देशो के सैन्य बल एक दूसरे के संगठनात्मक ढांचे, हथियार, साजो सामान, विश्वास प्रशिक्षण और सुनियोजित अभ्यास से परिचय प्राप्त करेंगे।

❒ सैन्य अभ्यास में दोनों देशों की सैन्य टुकडियां एक-दूसरे की संगठनात्मक, हथियारों और सैन्य उपकरणों से रूबरू होंगे। वहीं परस्पर रणनीतिक, तकनीकि, कार्रवाई एवं ऑपरेशन से जुड़े अनुभव भी साझा किये जायेगें।

❒ प्रशिक्षण की समाप्ति दोनो देशो के सैन्य बलो द्वारा काल्पनिक लेकिन सजीव परिस्थिति में संयुक्त रूप से आंतकवाद विरोधी अभियान के आयोजन से होगी।

❒ भारत और अमेरिका की सेनाओ के पास उग्रवाद और आंतकवाद विरोधी अभियान संचालन का विशाल अनुभव है और विविधतापूर्ण वातावरण में एक दूसरे के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास और सैन्य कार्यक्रम को सांझा करने की बड़ी अहमियत है।

❒ यह अभ्यास दो लोकतांत्रिक देशो की सेनाओ को एक साथ सैन्य प्रशिक्षण लेने और एक दूसरे के संचालन अनुभव को साझा करने का बेहतर अवसर प्रदान करेगा।

स्रोत: द हिंदू

महिलाओं की सहायता हेतु इंदिरा शक्ति एप्प लॉन्च

चर्चा में क्यों?

❒ राजीव गांधी की 74वीं जयंती के अवसर पर बिहार में 20 अगस्त 2018 को इंदिरा शक्ति एप्प लॉन्च किया गया। इस मोबाइल एप्प का उद्देश्य मुसीबत में फंसी महिलाओं को त्वरित सहायता एवं सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

❒ यह एप्प भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है. भारत में विभिन्न एप्प कार्यरत हैं लेकिन बिहार में अभी तक किसी एप्प की विशेष पहुंच नहीं थी जिसके चलते इंदिरा शक्ति एप्प को लॉन्च किया गया।

इंदिरा शक्ति एप्प की विशेषताएं

❒ यह एप्प महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया बेहद उपयोगी एप्प है। एक बार डाउनलोड करने के बाद यह एप्प ऑफलाइन भी काम करता है।

❒ इसमें सेफ्टी फीचर के तौर पर महिला को चार लोगों के मोबाइल नंबर दर्ज करने होते हैं। आपातकाल में उपयोग हेतु इसमें दो विकल्प दिए गये हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- पहला, आवश्यकता पड़ने पर एप्प ऑन करें और 'प्रेस' बटन को दबाना होता है। बटन दबाते ही दर्ज किये गये नंबर पर स्वत: ही कॉल तथा मेसेज चला जायेगा।
- दूसरा, यदि महिला अथवा उपयोगकर्ता मोबाइल अनलॉक करने की स्थिति में नहीं है तो वह मोबाइल के पावर बटन को तीन बार दबाये, इससे दर्ज किये गये नंबरों पर कॉल तो जाएगा ही साथ ही सहायता की मांग का मेसेज भी चला जायेगा।

विशेषता

- सबसे खास विशेषता यह है कि दोनों ही विकल्पों में मेसेज के साथ-साथ मुसीबत में पड़े व्यक्ति की लोकेशन भी दर्ज किये गये नंबरों पर मेसेज के साथ ही भेजी जाती है। इसे गूगल प्ले स्टोर से नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।
- इसे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को समर्पित किया गया है तथा उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है।
- एप्प विकसित करने में विशेष योगदान देने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के राष्ट्रीय सचिव (बिहार प्रभारी) राजेश लिलोथिया के अनुसार, एप्प के बारे में अधिक से अधिक महिलाओं को जोडने के इरादे से प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालय प्रोफेसरों से मदद ली जा रही है तथा उन्हें सुरक्षा उपायों के बारे में जागरुक भी किया जा रहा है। यह एप्प 'एसओएस' की तर्ज पर काम करता है।

स्रोत: द हिंदू

जर्मनी में विश्व की पहली हाइड्रोजन इंधन वाली ट्रेन का सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों?

- जर्मनी में 18 सितंबर 2018 को विश्व की पहली हाइड्रोजन इंधन वाली ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया। यह ट्रेन पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है अर्थात् डीजल इंजन की भांति इससे प्रदूषण नहीं होता।
- विश्व में बढ़ रही प्रदूषण की समस्या के चलते इस ट्रेन का निर्माण किया गया है. उत्तरी जर्मनी में हमबर्ग के पास एक रेलवे लाइन पर इस ट्रेन की का सफल ट्रायल हुआ. इस ट्रेन का नाम कोराडिया आई लिंट (ब्वतंकपं पस्पदज) रखा गया है।

मुख्य तथ्य

- इसको फ्रांस की कंपनी एलस्टॉम (Alstom) ने दो साल की मेहनत के बाद तैयार किया है।
- कंपनी द्वारा दावा किया गया है कि यह ट्रेन जीरो एमिशन पैटर्न पर चलती है अर्थात् इससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती बल्कि इससे भाप उत्पन्न होती है।
- इसकी स्पीड और यात्रियों को ले जाने की क्षमता डीजल ट्रेन की तुलना में कम नहीं है। इसकी टॉप स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है।
- कोराडिया आई लिंट ट्रेन सिंगल टैंक हाइड्रोजन भरे जाने पर 1,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, ऐसा दावा किया गया है।
- इस ट्रेन के परीक्षण के तौर पर इसे उत्तरी जर्मनी में कक्सहेवन, ब्रेमेरहेवन, ब्रेमर्वोर्डे और बक्सटेहुड के कस्बों और शहरों के बीच एक 100 किलोमीटर की दूरी पर चलाया गया।
- इस ट्रेन की विशेषता यह भी है कि एक बार इसका टैंक फुल होने के बाद यह करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है।

हाइड्रोजन ट्रेन की उपयोगिता

- हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने में डीजल इंजन की तुलना खर्च थोड़ा ज्यादा आता है. हाइड्रोजन ट्रेनों में फ्यूल शेल होता है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने के बाद बिजली उत्पन्न करती हैं।
- इस प्रक्रिया के दौरान उत्सर्जन के रूप में सिर्फ भाप और पानी निकलता है. यही कारण है कि इसे जीरो उत्सर्जन यानि कि प्रदूषण न करने वाला इंजन बताया जाता है।
- इस दौरान बिजली का जो अधिक उत्पादन होता है, उसे ट्रेन में आयन लिथियम बैटरी में अतिरिक्त जमा की जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो इसके उत्पादन में खर्च अधिक है लेकिन लम्बे समय के लिए इसके अनेक लाभ भी हैं।
- इस ट्रेन से जर्मनी के कई शहरों में प्रदूषण से निपटा जा सकता है। जर्मनी के अलावा ब्रिटेन, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, इटली, कनाडा जैसे देशों में भी हाईड्रोजन ट्रेन चलाने की संभावना पर काम किया जा रहा है।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत-पाक सीमा पर 'स्मार्ट फेंसिंग' प्रोजेक्ट की शुरुआत

चर्चा में क्यों?

✸ केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 17 सितम्बर 2018 को जम्मू में भारत-पाकिस्तान सीमा पर 5.5 किलोमीटर लंबे 'स्मार्ट फेंसिंग' पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की।

मुख्य तथ्य

❒ यह देश की पहली ऐसी स्मार्ट फेंसिंग है जिससे आतंकियों के बॉर्डर पार करते ही इसकी सूचना मिल जएगी।

❒ आधुनिक तकनीक से लैस इस फेंसिंग से घुसपैठियों पर नजर रखना आसान होगा। भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसपैठ और अवैध आव्रजन रोकने के लिए यह पहल एक समग्र एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआइबीएमएस) का हिस्सा है।

❒ सरकार ने दोनों देशों से लगी भारतीय सीमा को पूरी तरह से सील करने के लिए यह फैसला लिया है। इस तकनीक का इस्तेमाल सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) करेगा।

स्मार्ट फेंसिंग में कई उपकरणों का इस्तेमाल:

❒ सीआईबीएमएस के तहत अत्याधुनिक सर्विलांस टेक्नोलॉजी, थर्मल इमेजर्स, इन्फ्रारेड और लेजर आधारित घुसैपठ अलार्म हैं, जो एक अदृश्य जमीनी चारदीवारी की तरह काम करेंगे।

❒ हवाई निगरानी के लिए एयरोस्टेट, सुरंगों के जरिए घुसपैठ का पता लगाने में मदद के लिए ग्राउंड सेंसर, पानी के रास्ते सेंसर युक्त सोनार सिस्टम, जमीन पर ऑप्टिकल फाइबर सेंसर हैं।

❒ स्मार्ट फेंस में सतर्कता, निगरानी, संचार और डाटा स्टोरेज के लिए कई उपकरणों का इस्तेमाल होता है. सेंसर जैसे थर्मल इमेजर, अंडरग्राउंड सेंसर, फाइबर ऑप्टिकल सेंसर, रडार और सोनार आदि उपकरण स्मार्ट फेंस में विभिन्न स्थानों जैसे एयरोस्टैट, टावर और खंभों पर लगे होते हैं।

स्मार्ट फेंसिंग क्यों खास है?

❒ इन स्मार्ट फेंसिंग परियोजनाओं को जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5.5 किलोमीटर क्षेत्र में तैयार गया है. यह अपनी तरह की पहली हाईटेक निगरानी प्रणाली होगी, जो जमीन, पानी, हवा और भूमिगत स्तर पर एक अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक दीवार का काम करेगी, जिससे सीमा सुरक्षाबल (बीएसएफ) के जवानों को अत्यधिक दुर्गम क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने में मदद मिलेगी।

❒ नयी प्रणाली में सीमा की 24 घंटे निगरानी हो सकती है और यह धूलभरी आंधी, तूफान, धूंध या बारिश जैसे विभिन्न मौसमों में भी काम करती है।

❒ पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा चार राज्यों- जम्मू कश्मीर (1,225 किमी एलओसी समेत), राजस्थान (1,037 किमी), पंजाब (553 किमी) और गुजरात (508 किमी) से गुजरती है।

❒ इसमें सभी जगहों पर घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा रही है. इसके लिए काम भी शुरू हो चुका है. पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की 2,400 किलोमीटर लंबी सीमा पर ऐसी प्रणाली तैनात की जाएगी।

स्रोतः द हिंदू

महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार पोषाहार नीति को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

✸ नीति आयोग ने 09 सितंबर 2018 को महिला और बाल विकास मंत्रालय की बनाई हुई पोषाहार नीति को मंजूरी प्रदान की है. यह मंजूरी विभाग की मंत्री मेनका गांधी एवं महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिए गये सुझावों पर विचार करने के बाद दी गई है.

मुख्य तथ्य

❒ महिला और बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास योजना के तहत देश में 14 लाख आंगनवाड़ियों से 10 करोड़ बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन और घर ले जाने के लिए राशन देने की योजना थी।

❒ मेनका गांधी का सुझाव था कि घर ले जाने वाला भोजन उन स्वयं सहायता समूह से प्राप्त किया जाए जिनके पास पर्याप्त संख्या में निर्माण की सुविधा हो या फिर सरकारी या निजी संस्थाओं से इसे लिया जाए।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- रिपोर्ट के मुताबिक, विभाग की मंत्री मेनका गांधी, गर्म भोजन परोसने के भी खिलाफ थीं। वह चाहती थीं कि 'रेडी टू ईट' पैकेटबंद खाना लाभार्थी बच्चों को बांट दिया जाए।
- महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी इस पक्ष में थे कि बच्चों को दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ सिर्फ स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्रियों से निर्मित किया जाए।
- मेनका गांधी ने नीति निर्माताओं से कहा था कि हमें सिर्फ खाना देने के बारे में सोचने की जगह पोषण देने के बारे में सोचना चाहिये, जबकि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने नीति आयोग को सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्य सुरक्षा का अर्थ जरूरतमंदों तक तय मात्रा में खाद्य अनाज और भोजन पहुँचाना है।

पृष्ठभूमि

- जून 2018 में महिला और बाल विकास विभाग के सचिव आर.के. श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री कार्यालय को नियम तय करने में हो रही देरी पर पत्र लिखा।
- उन्होंने इस मामले में पीएमओ से दखल की मांग करते हुए शीघ्र निर्णय लेने और अधिकारियों की स्थिति को वापस लाने के लिए कहा।
- पीएमओ ने इसके बाद सुझाव दिया कि ये मामला कैबिनेट सचिवालय और नीति आयोग से ही निस्तारित होगा। इसके बाद नीति आयोग के उप-चेयरमैन राजीव कुमार ने दिशा निर्देशों को मंजूर कर दिया।

एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS)

- यह योजना वर्ष 1975 में 6 साल से कम आयु के बच्चों के सर्वांगीण विकास (स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा) के लिये एक पहल के रूप में शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य शिशु मृत्यु दर, बाल कुपोषण को कम करना और पूर्व-विद्यालय शिक्षा प्रदान करना है।
- आईसीडीएस योजना की निगरानी संबंधी समग्र जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) की है।
- आईसीडीएस योजना के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माँ की पहुँच चार मुख्य सेवाओं जैसे- प्रतिरक्षा,पूरक पोषण, स्वास्थ्य जाँच, रेफरल सेवाएँ तक सुनिश्चित करना है।
- इसके अतिरिक्त आईसीडीएस के तहत 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की पहुँच पूर्व-स्कूल गैर-औपचारिक शिक्षा तक सुनिश्चित कराना।

स्रोतः पीआईबी

जापान ने पृथ्वी से 30 करोड़ किमी दूर ऐस्टेरॉयड पर उतारे दो रोबोट रोवर

चर्चा में क्यों?

✸ जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (जेएएक्सए) के मुताबिक, पृथ्वी से 30 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित 'रोइगु' ऐस्टेरॉयड पर उसने सफलतापूर्वक दो रोबोट रोवर उतार लिए हैं। रोवर्स को सामूहिक रूप से MINIRVA कहा जा रहा है।

मुख्य तथ्य

- जापानी अंतरिक्ष एजेंसी ने एक एस्टेरॉयड पर दो मानव रहित रोवर्स की सफलतापूर्वक लैंडिंग करके इतिहास बना दिया है। 22 सितम्बर 2018 को जापान के हेवसुसा 2 अंतरिक्ष यान से अलग होकर ये रोवर्स एस्टेरॉयड की सतह पर उतरे थे।
- किसी भी ऐस्टेरॉयड की सतह पर यह दुनिया का पहला चलता हुआ रोबोटिक ऑब्जर्वेशन है. सही से काम कर रहे दोनों रोवर ने रोइगु की सतह का सर्वे करना शुरू कर दिया है।
- हेवसुसा-2 यान ने 20 सितम्बर 2018 को लगभग 20 किमी की कक्षा ऊंचाई से एस्टेरॉयड रोइगु के लिए लैंड करना शुरू किया था।
- हेवसुसा-2 यान रोइगु से दिसंबर 2019 में वापस धरती के लिए रवाना होगा और वर्ष 2020 के अंत तक यहां पहुंच जाएगा. यह यान अपने साथ क्षुद्रग्रह से जुटाए गए कुछ सैंपल भी लेकर आएगा।
- अगर अंतरिक्ष यान की वापसी सफल रही तो यह ष्सी-टाइप के एस्टेरॉयड से दुनिया का पहला नमूना रिटर्न मिशन होगा।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

रोवर्स ने पहली तस्वीर ली:

- रोवर्स ने अपने पहले चरण की तस्वीरों में एक किमी चौड़ी अंतरिक्ष की चट्टान की तस्वीरें ली हैं। हीरे की तरह दिखने वाली इस चट्टानिक एस्टेरॉयड पर पानी और कार्बनिक पदार्थों के समृद्ध भंडार होने की उम्मीद है। वैज्ञानिकों को इस तस्वीर से ष्पृथ्वी के निर्माण खंडों और इसके महासागरों और जीवन के विकास के क्रम को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलेगी।

रोबोट रोवर का डिजाइन:

- विशेष रूप से डिजाइन किए पहले रोवर पर चार और दूसरे पर तीन कैमरे लगाए गए हैं। दोनों रोवर्स तापमान गेज और ऑप्टिकल सेंसर के साथ-साथ एक्सेलेरोमीटर और जीरोस्कोप के साथ लैस हैं।
- रोवर ऐसे वाहन को कहते हैं जो किसी अन्य ग्रह या खगोलीय वस्तु पर घूमने-फिरने की क्षमता रखता हो। कुछ रोवर रोबोट होते हैं और बिना किसी व्यक्ति की मौजूदगी के चलते हैं और कुछ मनुष्यों को स्थान-से-स्थान ले जाने के लिए बने होते हैं। आम तौर पर रोवर किसी ग्रह पर किसी अन्य यान के अन्दर ले जाए जाते हैं जो उस ग्रह की सतह पर उतरता हो।

स्रोत: द हिंदू

ग्लोबल टीबी रिपोर्ट-2018

चर्चा में क्यों?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2018 जारी की है। इस रिपोर्ट में टीबी के बारे में व्यापक और नवीनतम आकलन दिया गया है। डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्वभर के देशों को टीबी की रोकथाम के लिए जो उपाय करने चाहिए, वह अभी भी नहीं किए जा रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त, इस रिपोर्ट में यह जानकारी भी दी गई है कि वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इस बीमारी को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं एवं उनमें क्या प्रगति आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरी दुनिया में पिछले वर्ष एक करोड़ लोग टीबी से पीड़ित हुए, जिनमें 27 प्रतिशत लोग भारत से हैं।

डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य

- रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक स्तर पर आकलन के मुताबिक वर्ष 2017 में एक करोड़ लोगों को टीबी हुई, इनमें से 58 लाख पुरुष, 32 लाख महिलाएं और दस लाख बच्चे हैं।
- विश्वभर में टीबी के कुल मरीजों में दो तिहाई आठ देशों में हैं। इनमें से भारत में 27 प्रतिशत मरीज हैं।
- चीन में 9 प्रतिशत, इंडोनेशिया में 8 प्रतिशत, फिलीपींस में 6 प्रतिशत, पाकिस्तान में 5 प्रतिशत, नाइजीरिया में 4 प्रतिशत, बांग्लादेश में 4 प्रतिशत तथा दक्षिण अफ्रीका में 3 प्रतिशत लोग टीबी की बीमारी से पीड़ित हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया कि टीबी के कारण प्रतिदिन लगभग 4,000 लोगों की जान चली जाती है।
- डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट के अनुसार विश्वभर में रोगों से होने वाली मौत की दसवीं सबसे बड़ी वजह टीबी है।
- विदित हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2030 तक दुनिया से टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य तय कर रखा है।

टीबी रोकथाम असफलता के कारण

- डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि टीबी की रोकथाम के लिए इस बीमारी से ग्रस्त मरीजों की पहचान और उनका उचित इलाज करने की दिशा में उठाए गए कदम भी नाकाफी हैं।
- संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017 में 1 करोड़ लोगों को टीबी की बीमारी हुई, लेकिन इनमें से 64 लाख लोगों का केस ही आधिकारिक रूप से सरकारी आंकड़ों में दर्ज किया जा सका।
- संगठन के अनुसार 36 लाख से ज्यादा लोगों की बीमारी की न तो सही समय पर पहचान हो सकी और न ही उन्हें इलाज की उचित सुविधाएं मुहैया कराई जा सकी अर्थात् टीबी से ग्रस्त 64 प्रतिशत मरीजों का ही इलाज हो सका।
- संगठन का कहना है कि टीबी से ग्रस्त मरीजों की पहचान और उनके इलाज के आंकड़े को 64 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करना होगा, इसके बाद ही दुनिया से टीबी की बीमारी का उन्मूलन संभव हो पाएगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस , द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विश्व में भुखमरी के स्तर में लगातार तीसरे वर्ष वृद्धि: संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

✸ संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्वभर में भुखमरी की समस्या में लगातार तीसरे वर्ष भी वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अफ्रीका भूख की समस्या से सबसे अधिक ग्रस्त है, इसके बाद एशिया और अमेरिका का नंबर आता है।

मुख्य तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट द्वारा चेतावनी दी कि वर्ष 2030 तक भूख की समस्या को खत्म करने के वैश्विक लक्ष्य को बाधित करते हुए संघर्षों एवं जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप भूख की समस्या में वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2017 में भुखमरी से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या: 821 मिलियन अथवा विश्व का प्रत्येक नौंवां व्यक्ति
- एशिया में भुखमरी से पीड़ित लोगों की संख्या: 515 मिलियन
- अफ्रीका में भुखमरी से पीड़ित लोगों की संख्या: 256.5 मिलियन
- लैटिन अमेरिका तथा कैरीबियन भुखमरी से पीड़ित में लोगों की संख्या: 39 मिलियन
- आयु की तुलना में कम लंबाई वाले पांच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की संख्या: 150.8 मिलियन (22.2%)
- आयु की तुलना में कम वजन वाले पांच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की संख्या: 50.5 मिलियन (7.5%)
- मोटापे से पीड़ित वयस्कों की संख्या: 672 मिलियन (13% अथवा प्रत्येक आठवां व्यक्ति)

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति की वैश्विक 2018 रिपोर्ट के अनुसार, लगभग पूरे अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भूख की समस्या बढ़ रही है तथा 2017 में नौ में से एक व्यक्ति या 821 मिलियन लोग भूख से ग्रसित रहे।
- रिपोर्ट में कहा गया कि यह लगातार तीसरा वर्ष है जब एक दशक तक गिरावट के बाद वैश्विक भूख के स्तर में वृद्धि हुई है।
- तापमान में बढ़ती विविधता; तीव्र, अनियमित वर्षा और बदलते मौसम आदि ने खाद्य की उपलब्धता और गुणवत्ता को प्रभावित किया है।
- संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि खाद्य पदार्थों की कमी के कारण अनुमानत: 2.3 मिलियन लोगों ने जून माह में वेनेजुएला छोड दिया था।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भोजन की अनिश्चित या अपर्याप्त उपलब्धता मोटापे में भी योगदान देती है क्योंकि सीमित वित्तीय संसाधन वाले लोग सस्ते, ऊर्जा-सघन प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का चयन कर सकते हैं जिसमें वसा, नमक और चीनी की उच्च मात्रा शामिल होती है।
- संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि पिछले वर्ष 51 देशों में लगभग 124 मिलियन लोगों ने संघर्ष और जलवायु आपदाओं से प्रेरित भूख के संकट के स्तर का सामना किया।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि यमन, सोमालिया, दक्षिण सूडान और अफगानिस्तान जैसे कई राष्ट्र जो लंबे समय से संघर्षों से जूझ रहे हैं, सूखे और बाढ़ जैसे एक या अधिक जलवायु खतरों से भी पीड़ित हैं, उनमें भुखमरी की समस्या अधिक देखी गई है।

स्रोत: द हिंदू

टी-72 टैंकों के लिए 1000 इंजनों की खरीद को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख युद्धक टैंक टी-72 के लिए 1,000 इंजन की खरीद को मंजूरी दी है जिस पर 23,000 करोड रूपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है।
- रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में इस खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। परिषद ने रक्षा सौदों के अमल में होने वाली देरी और प्रक्रियागत जटिलताओं को कम करने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया में कुछ संशोधनों को भी मंजूरी दी।

प्रमुख तथ्य

- इन इंजनों की खरीद से टी-72 टैंकों में गतिशीलता, फुर्ती और गति में इजाफा होगा और युद्ध क्षेत्र में वे और ज्यादा प्रभावशाली साबित होंगे।
- मंत्रालय के अनुसार टी-72 टैंकों में लगाए जाने वाले 1,000 बीएचपी के 1,000 इंजनों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इस पर तकरीबन 2300 करोड़ रूपये की लागत आएगी।
- केंद्रीय सैन्य पुलिस बल (सीएपीएफ) और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) जैसे अन्य संगठनों की खरीद को शामिल कर लिया गया है। इससे रक्षा सौदों को अमली जामा पहनाने में लगने वाले समय में कमी आयेगी।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- इसके अलावा रक्षा खरीद परिषद ने इस तरह की खरीदारी के लिए नियमावली के तौर पर काम करने वाली रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी)-16 में भी कुछ संशोधन के करने की मंजूरी दी है।
- इसके तहत संशोधित ऑर्डर को मूल सौदे की वारंटी की अवधि पूरा होने के पांच साल में पूरा करना होगा।

रक्षा खरीद परिषद

- देश की रक्षा एवं सुरक्षा हेतु की जाने वाली खरीद और अधिग्रहण के लिए 11 अक्टूबर 2001 को रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना की गई थी। रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) रक्षा मंत्रालय के तहत एक व्यापक संरचना, रक्षा खरीद योजना प्रक्रिया के समग्र मार्गदर्शन के लिए गठित की गई थी।

डीएसी की संरचना

- रक्षा मंत्री: अध्यक्ष, रक्षा राज्य मंत्री: सदस्य, सेना प्रमुख के प्रमुख: सदस्य, नौसेना प्रमुख के प्रमुख: सदस्य, प्रमुख वायु कर्मचारी: सदस्य, रक्षा सचिव: सदस्य, सचिव रक्षा अनुसंधान एवं विकास: सदस्य, सचिव रक्षा उत्पादन: सदस्य रक्षा खरीद परिषद का उद्देश्य मांग की गई क्षमताओं के संदर्भ में सशस्त्र बलों के अनुमोदित आवश्यकताओं की शीघ्र खरीद, और आवंटित बजटीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करके, निर्धारित समय सीमा को सुनिश्चित करना है।

स्रोत: पीआईबी , द हिंदू

भारतीय लड़ाकू विमान तेजस ने पहली बार हवा में ईंधन भरने का सफल परीक्षण किया

चर्चा में क्यों?

- भारतीय वायुसेना (आईएएफ) ने हाल ही में स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान 'तेजस' में पहली बार सफलतापूर्वक हवा में ही ईंधन भरा।
- भारतीय वायुसेना (आईएएफ) वर्तमान में एक प्रारंभिक ऑपरेटिंग क्लीयरेंस (आईओसी) मानक में निर्मित नौ तेजस लड़ाकू विमानों का संचालन करती है। इन जेटों को तमिलनाडु के सुलूर वायुसेना स्टेशन पर आधारित नंबर 45 स्क्वाड्रन, फ्लाइंग डैगर्स द्वारा उड़ाया जा रहा है।

मुख्य तथ्य:

- रूस निर्मित आईएल-78 एमकेआई टैंकर ने तेजस एमके आई के एक विमान में ईंधन भरा। इस दौरान एक अन्य तेजस विमान इस पूरी प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखे हुए था।
- ये टैंकर आगरा में वायुसेना अड्डे से भेजा गया था, जबकि लड़ाकू विमान ने ग्वालियर से उड़ान भरा था। विशेष रूप से निर्मित तेजस विमान ने टैंकर के साथ ड्राई कॉन्टैक्ट सहित कई परीक्षणों को पूरा किया।
- इस मिशन के दौरान तेजस को ग्रुप कैप्टन जोशी और आईएल-78 टैंकर को ग्रुप कैप्टन आर अरविंद उडा रहे थे।
- परीक्षण उड़ान से पहले सभी तरह के जमीनी परीक्षण भी किये गये थे। इस सफल परीक्षण से स्वदेशी तेजस की ताकत बढी है और यह लंबी अवधि के मिशन को भी बखूबी अंजाम देने में सक्षम बन गया है।
- यह परीक्षण तेजस के लिए'फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस'का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- ईंधन को टैंकर से लड़ाकू में स्थानांतरित करने के लिए 'वेट' परीक्षणों सहित इस क्षमता को मान्य करने के लिए नौ और परीक्षण आयोजित किए जाएंगे।
- तेजस में एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग की जांच अंतरराष्ट्रीय एयरोस्पेस सिस्टम प्रमुख कोबम द्वारा डिजाइन की गई है।

एलसीए तेजस:

- एलसीए तेजस भारत द्वारा विकसित किया जा रहा एक हल्का और कई तरह की भूमिकाओं वाला जेट लड़ाकू विमान है। यह हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा विकसित एक सीट और एक जेट इंजन वाला विमान है। अनेक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम एक हल्का युद्धक विमान है।
- यह बिना पूँछ का, कम्पाउण्ड-डेल्टा पंख वाला विमान है। विमान का आधिकारिक नाम तेजस 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था।
- यह विमान पुराने पड़ रहे मिग-21 का स्थान लेगा। एलसीए कार्यक्रम 1983 में दो प्राथमिक उद्देश्यों के लिए शुरू किया गया था। एलसीए के कार्यक्रम का अन्य मुख्य उद्देश्य भारत के घरेलू एयरोस्पेस उद्योग की चौतरफा उन्नति के वाहक के रूप में कार्य करना था।

तेजस की विशेषताएं:

- लड़ाकू विमान तेजस 50 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है।
- विमान तेजस में हवा से हवा में मार करने वाली डर्बी मिसाइल समाहित की गयी है।
- तेजस में जमीन पर निशाना लगाने हेतु आधुनिक लेजर गाइडेड बम लगे हुए हैं।
- ताकत के मामले में यह पुराने मिग-21 से कही अधिक दमदार है और इसकी तुलना मिराज-2000 से की जा सकती है।
- इसमें सेंसर तरंग रडार लगाया गया है जो दुश्मन के विमान या जमीन से हवा में दागी गई मिसाइल के तेजस के पास आने की सूचना देता है।

स्रोत: द हिंदू

इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों?

- भारत ने 23 सितंबर 2018 को ओडिशा के मिसाइल परीक्षण केन्द्र से इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

मुख्य तथ्य

- इसके साथ ही भारत ने दो परतों वाली बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है।
- इंटरसेप्टर मिसाइल को अब्दुल कलाम द्वीप से रात में आठ बजकर पांच मिनट पर प्रक्षेपित किया गया। इसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के वैज्ञानिक ने कहा कि यह पृथ्वी रक्षा यान (पीडीवी) मिशन पृथ्वी के वायुमंडल में 50 किमी से ऊपर की ऊंचाई पर लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए है।

इंटरसेप्टर मिसाइल की मुख्य विशेषताएं

- परीक्षण के उपरांत कुछ समय बाद पृथ्वी रक्षा यान (पीडीवी) इंटरसेप्टर और लक्ष्य मिसाइल दोनों सफलतापूर्वक जुड़ गए थे।
- पीडीवी मिशन पृथ्वी के वायुमंडल में 50 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई पर लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए है।
- इस तकनीक को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है।
- परीक्षण के दौरान राडार से आ रहे आंकड़ों का कंप्यूटर नेटवर्क ने सटीक विश्लेषण किया और आने वाली लक्ष्य मिसाइल को मार गिराया गया।
- इंटरसेप्टर मिसाइल उच्च दक्षता वाले इंट्रियल नेविगेशन प्रणाली (आईएनएस) से निर्देशित हुई।
- इससे पूर्व 11 फरवरी 2017 को इसी स्थान से इंटरसेप्टर का परीक्षण किया गया था।
- भारत में ही बनने वाली इस इंटरसेप्टर मिसाइल के अलावा कई और मिसाइल भी पहले सफलतापूर्वक जांची जा चुकी है। इससे पहले डीआरडीओ ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल 'प्रहार' को टेस्ट किया था। 'प्रहार' पूरी तरह से स्वदेशी अत्याधुनिक मिसाइल है। भारतीय सेना में 'प्रहार' जैसी मिसाइल के शामिल होने से सेना की मारक क्षमता में इजाफा होगा साथ ही यह युद्ध प्रणाली के लिए जरूरी अल्ट्रा-मॉर्डन टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाने में सक्षम है। इंटरसेप्टर का नाम पृथ्वी डिफेंस व्हीकल (पीडीवी) मिशन दिया गया।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने 26 सितंबर 2018 को नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी (NDCP) को मंजूरी प्रदान की। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक टेलीकॉम सेक्टर में 10 हजार करोड़ का निवेश और 40 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है।
- नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में नेट निरपेक्षता पर भी जोर दिया गया है। इसके साथ ही डिजिटल विषयवस्तु के साथ कोई भेदभाव न करते हुए पारदर्शिता को बढ़ावा देने की बात कही गई है।

नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के प्रमुख तथ्य

- इसके तहत सभी के लिए ब्रॉडबैंड का प्रावधान किये जाने की बात कही गई है।
- नई दूरसंचार नीति के तहत वर्ष 2020 तक देश के हर एक नागरिक को 50 एमबीपीएस की तथा हर एक ग्राम पंचायत को एक जीबीपीएस की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- डिजिटल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लगभग 40 लाख रोजगारों का सृजन किया जाएगा।
- देश के जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान आठ प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है जबकि वर्ष 2017 में यह छह प्रतिशत था।
- सूचना एवं संचार तकनीकी विकास सूचकांक में देश को वर्तमान 134वें स्थान से सुधारकर शीर्ष 50 देशों में शामिल करना।
- उपभोक्ताओं की जरूरत को हल करने के लिए एक नए दूरसंचार लोकपाल के गठन और वेब आधारित शिकायत व्यवस्था कायम करने की प्रणाली विकसित करना।
- संचार नीति में स्पेक्ट्रम और टावर नीतियों में अहम बदलाव का सुझाव दिया गया है ताकि इनका कारोबार आसानी से चल सके।
- पॉलिसी में कर्ज की समस्या से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर को नया जीवन देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिए ज्यादा निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- वैश्विक मानकों के अनुरूप डेटा सुरक्षा के मानक विकसित करने पर भी जोर दिया गया है। यह सुझाव भी दिया गया है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षा के मसले पर जागरूक किया जाए।

डाटा सुरक्षा पर विशेष फोकस

- नई नीति में डिजिटल संचार से निजता, स्वायत्तता तथा व्यक्तिगत चयन के अधिकारों के हनन की संभावनाओं को निरस्त करने के भी उपाय किए गए हैं।
- इसके लिए नीति में सुरक्षित संचार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ डाटा सुरक्षा का समग्र व सशक्त तंत्र विकसित करने का वादा किया गया है। यह काम राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना और राष्ट्रीय फाइबर प्राधिकरण के गठन से होगा।
- इससे केंद्र, राज्यों तथा स्थानीय निकायों के बीच सहयोग का ऐसा तंत्र विकसित होगा जिससे वे साझा 'राइट ऑफ वे' के अलावा सेवाओं की लागत और समय सीमाओं के मानक सुनिश्चित कर सकेंगे।

नई दूरसंचार नीति का उद्देश्य

- नई दूरसंचार नीति का उद्देश्य 5जी टेलीकॉम सेवाओं, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, और मशीन-टू-मशीन कम्युनिकेशन तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आइओटी) तकनीकों में अग्रणी स्थान प्राप्त करना है।
- यह नीति राज्यों, केंद्रीय एजेंसियों, दूरसंचार और स्टार्टअप्स कंपनियों को इस बात का पता लगाने में मददगार साबित होगी कि भविष्य में सरकार इस क्षेत्र में किस प्रकार के कदम उठाने वाली है।

स्रोतः द हिंदू , पीआईबी

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह पर जोधपुर में पराक्रम पर्व का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 सितम्बर 2018 को सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरे सालगिरह के मौके पर जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में आर्मी एग्जिबिशन पराक्रम पर्व का उद्घाटन किया। पराक्रम पर्व 28 से 30 सितंबर तक चलेगा।

मुख्य तथ्य

- पाकिस्तान में घुस कर सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के दो वर्ष पूरे होने पर भारतीय सेना पराक्रम पर्व मना रही है। देश ने सेना के इस कारनामें पर गर्व जताया था। सर्जिकल स्ट्राइक के दो साल पूरा होने पर देश में कई जगह प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने कोणार्क कोर युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सेना प्रमुख बिपिन रावत, वायु सेना प्रमुख मार्शल बीएस धनोवा और नेवी प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इसके बाद पराक्रम पर्व प्रदर्शनी में रखे सैन्य उपकरणों का देखा।
- इस अवसर पर देश के 51 शहरों में पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है। कई स्थानों पर तीन दिनों तक सर्जिकल स्ट्राइक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इसमें सेना के हथियार और अन्य सैन्य उपकरण प्रदर्शित किए जाएंगे। 28 सितम्बर को दिल्ली में इंडिया गेट पर भी पराक्रम पर्व के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

सर्जिकल स्ट्राइक क्या है?

- सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन किसी विशेष क्षेत्र को निशाना बनाकर किया जाने वाला हमला होता है। इसमें आसपास के क्षेत्र में कम से कम नुकसान होने तथा केवल टारगेट को ही निशाना बनाये जाने पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार के हमले से टारगेट को निष्क्रिय करके बड़े हमले से भी बचा जा सकता है।
- भारत द्वारा इस प्रकार के सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन से लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आतंकवादी कैंपों को निशाना बनाया जाता है तथा बड़े टकराव से बचा जाता है।

भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइकः

- भारतीय सेना ने उरी हमले के ग्यारह दिन बाद जवाब में 28 सितंबर 2016 रात को पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन किया। भारतीय सेना द्वारा यह ऑपरेशन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकवादी कैंप को निशाना बनाते हुए किया गया था।
- डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल रनवीर सिंह ने अधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा था की भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की है।
- भारतीय सेना द्वारा सात आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया था। इसके लिए भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में दो किलोमीटर अंदर घुसकर यह ऑपरेशन किया था।

पहली कमांडर कॉन्फ्रेंसः

- वर्ष 2015 तक कमांडर कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ही आयोजित होती थी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2016 में यह कॉन्फ्रेंस दिल्ली से बाहर सैन्य क्षेत्र के पोत आईएनएस विक्रमादित्य और 2017 में देहरादून स्थित इंडियन मिलट्री एकेडमी में शुरू करवाई थी। इसके बाद पहली बार एशिया के सबसे बड़े जोधपुर एयर बेस पर यह कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सुखोई से सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों?

✸ हाल ही में वायु सेना ने देश में ही बनी हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सुखोई-30 लड़ाकू विमान से सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल दृष्टि सीमा से आगे तक मार करने में सक्षम है।

मुख्य तथ्य

- अस्त्र को सेना में शामिल किये जाने से पहले के अंतिम चरण के परीक्षणों का हिस्सा होने के कारण इस परीक्षण की सफलता को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अस्त्र मिसाइल को देश में ही निर्मित और विकसित किया गया है।
- वायु सेना ने मिसाइल का अपने कलाईकुंडा स्टेशन से परीक्षण किया और मिसाइल ने हवा में तैर रहे लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा।
- यह मिसाइल अपनी श्रेणी की हथियार प्रणालियों में श्रेष्ठ है और इसके 20 से भी अधिक परीक्षण किये जा चुके हैं।
- मिसाइल ने उच्च मारक क्षमता के साथ सफलतापूर्वक निशाना लगाया जो मिशन के लक्ष्य को पूरा करता है।
- अभी तक हुए परीक्षणों में अस्त्र को पूरी तरह सुखोई एसयू-30 विमान से दागा गया है।
- विमान परीक्षण इसलिए महत्व रखता है क्योंकि यह रक्षा बेड़े में शामिल किए जाने से पहले अंतिम परीक्षण का हिस्सा था।

अस्त्र मिसाइल की विशेषताएं

- अस्त्र मिसाइल दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने विकसित किया है।
- यह हवा से हवा में मार करने वाला भारत द्वारा विकसित पहला प्रक्षेपास्त्र है।
- यह उन्नत प्रक्षेपास्त्र लड़ाकू विमान चालकों को 80 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमानों पर निशाना लगाने और मार गिराने की क्षमता देता है।
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने प्रक्षेपास्त्र को मिराज 2000 एच, मिग 29, सी हैरियर, मिग 21, एच ए एल तेजस और सुखोई एसयू-30 एमकेआई विमानो में लगाने के लिए विकसित किया है।
- यह ठोस ईंधन प्रणोदक इस्तेमाल करती है हालांकि डीआरडीओ इसके लिये आकाश प्रक्षेपास्त्र जैसी प्रणोदन प्रणाली विकसित करना चाहती है।
- प्रक्षेपास्त्र पराध्वनि गति से लक्ष्य विमान अवरोधन करने में सक्षम है।

स्रोतः द हिंदू

आइएनएमएएस ने पहली स्वदेशी एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट तैयार की

चर्चा में क्यों?

- परमाणु चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान संस्थान (आइएनएमएएस) के वैज्ञानिकों ने स्वदेश निर्मित पहली एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। इससे परमाणु युद्ध या रेडियोधर्मी विकिरण की वजह से गंभीर रूप के घायल लोगों का इलाज किया जा सकेगा।
- देश की सुरक्षा में तैनात अर्धसैनिक बलों और पुलिस की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिकों द्वारा तैयार इस किट को बेहद उपयोगी माना जा रहा है। इस किट से परमाणु हमले की स्थिति में लोगों को विकिरण के संपर्क में आने से रोकने में भी उपयोग किया सकेगा।

एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किटः मुख्य तथ्य

- वैज्ञानिकों ने 20 वर्षो के निरंतर प्रयासों से इस किट को तैयार किया है।
- इस किट में लगभग 25 सामग्रियां हैं, जिनका अलग-अलग इस्तेमाल किया जा सकता है।
- इनमें विकिरण के असर को कम करनेवाले रेडियो प्रोटेक्टर, बैंडेज, गोलियां, मलहम आदि शामिल हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- इस किट में हल्के नीले रंग की गोलियां हैं, जो रेडियो सेसियम (सीएस-137) और रेडियो थैलियम आदि के असर को लगभग खत्म कर देती हैं।
- यह खतरनाक रसायन परमाणु बम का हिस्सा होते हैं, जो मानव शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं।
- यह गोली मानव शरीर में प्रवेश करने वाले विकिरणों को पूरी तरह से अवशोषित कर लेने में सक्षम है।
- इसमें एक एसिड (ईडीटीए) का इन्जेक्शन भी है, जो परमाणु हमले के दौरान यूरेनियम को शरीर में फैलने से रोकता है।

विशेष

- स्वदेशी रूप से इस किट का निर्माण पहली बार किया गया है. इससे देश को काफी फायदा होगा।
- अब तक भारत इस किट को सामरिक रूप से उन्नत राष्ट्रों जैसे रूस और अमेरिका से खरीदता था, जिसके लिए भारी कीमत चुकानी होती थी।
- आइएनएमएएस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार फिलहाल यह किट केवल अर्धसैनिक बलों और पुलिस वालों के लिए बनाई गई है, जिनको विकिरण का सबसे ज्यादा खतरा रहता है।
- इनका इस्तेमाल किसी परमाणु, रासायनिक हमले के दौरान या उसके बाद चलाए जाने वाले बचाव अभियान के दौरान ही किया जाएगा।

स्रोतः द हिंदू

सरकार ने सेरिडॉन सहित 328 एफडीसी दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई

चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आमतौर पर प्रयोग में लाई जाने वाली 328 दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के तकनीकी परामर्श बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश के तहत यह निर्णय लिया गया है।
- जिन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें सिरदर्द समेत कई रोगों की दवाएं शामिल हैं। इस प्रतिबंध से 1.18 लाख करोड़ रुपए के फार्मा उद्योग से 1500 करोड़ रुपये का कारोबार बंद हो सकता है।

328 दवाओं पर प्रतिबंध का फैसला

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से मानव उपयोग के उद्देश्य से 328 एफडीसी (फिक्स्ड डोज कांबिनेशन या निश्चित खुराक संयोजन) के उत्पादन, बिक्री अथवा वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- सरकार ने जिन दवाओं पर रोक लगाई है उनमें वो दवाएं हैं जो लोग जल्दन आराम पाने के लिए मेडिकल शॉप से बिना पर्चे के खरीद लेते हैं।
- परामर्श बोर्ड ने एफडीसी दवाओं पर सौंपी गई रिपोर्ट में कहा था कि इन 328 एफडीसी में निहित सामग्री का कोई चिकित्सकीय औचित्य नहीं है।
- बोर्ड ने सिफारिश की थी कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत व्यापक जनहित में इन एफडीसी के उत्पादन, बिक्री तथा वितरण पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है।

फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन क्या है?

- दो या दो से अधिक दवाओं को मिलाकर बनाई जाने वाली दवा को फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन अथवा एफडीसी कहा जाता है।
- इन दवाओं की पावरफुल एंटीबायोटिक के कॉम्बिनेशन के रूप में बिक्री होती है। देश में एफडीसी से हजारों दवाएं तैयार होती हैं और कई एफडीसी बिना मंजूरी के बनते हैं। एफडीसी से दर्द निवारक के लिए सबसे ज्यादा दवाएं बनती हैं।
- ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल शरीर के लिए खतरनाक होता, इसलिए सरकार ने इन दवाओं पर रोक लगाई गई है।
- आवश्यकता से अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक के उपयोग से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर होता है और ये लीवर के लिए भी नुकसानदायक होता है। एफडीसी से तैयार होने वाले एंटीबायोटिक के ज्यादा सेवन से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

पृष्ठभूमि

- इससे पहले केंद्र सरकार ने 2016 के मार्च में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत मानव उपयोग के उद्देश्य से 344 एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया था।
- इसके बाद सरकार ने समान प्रावधानों के तहत 344 एफडीसी के अलावा पांच और एफडीसी को प्रतिबंधित कर दिया था।
- हालांकि, इससे प्रभावित उत्पादकों अथवा निर्माताओं ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय को चुनौती दी थी जिससे कम्पनियों को अस्थायी अनुमति मिल गई थी।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रहार' का सफल परीक्षण किया

चर्चा में क्यों?

- भारत ने 20 सितंबर 2018 को स्वदेश में विकसित और सतह से सतह पर कम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रहार' का ओडिशा तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
- यह मिसाइल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित किया गया है। यह परीक्षण ओडिशा के बालासोर स्थित इंटिग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) के लांचिंग कांप्लेक्स से भारी बारिश के बीच किया गया।
- यह मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली शपिनाकाश और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शृपथ्वीश के अंतरों को पाटने में सक्षम है। इसके अलावा वह विभिन्न दिशाओं में कई लक्ष्यों को साध सकती है।

मिसाइल परीक्षण से संबंधित मुख्य तथ्य:

- यह परीक्षण सफल रहा, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने से पहले इसने 200 किलोमीटर तक की दूरी तय की और मिशन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया।
- इस अत्याधुनिक मिसाइल का यहां के पास स्थित चांदीपुर समन्वित परीक्षण रेंज (आईटीआर) से परीक्षण किया गया। इसे मोबाइल लॉन्चर से दागा गया।
- यह हर मौसम में, हर क्षेत्र में अत्यधिक सटीक और सहयोगी तरकीबी हथियार प्रणाली है।
- यह ठोस ईंधन से लैस कम दूरी वाली मिसाइल है।
- परीक्षण के दौरान रेंज स्टेशनों और इलैक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की मदद से मिसाइल के ट्रैक पर नजर रखी गई।
- सभी ऋतुओं में इस्तेमाल की संभावना को देखते हुए इस मिसाइल का परीक्षण किया गया।
- मिसाइल के परीक्षण से पहले चांदीपुर स्थित लॉन्च पैड संख्या तीन की दो किलोमीटर की परिधि में रहने वाले 4,494 लोगों को अस्थायी तौर पर वहां से हटाया गया।
- सुरक्षा उपायों के तहत पांच गांवों से इन लोगों को हटाया गया। परीक्षण के शीघ्र बाद आईटीआर अधिकारियों से इजाजत मिलने पर वे अपने घरों में लौट आए।

प्रहार मिसाइल के बारे में:

- प्रहार एक ठोस इंधन की, सतह-से-सतह तक मार करने में सक्षम कम दुरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है।
- प्रहार मिसाइल का प्रयोग किसी भी सामरिक और रणनीतिक लक्ष्यों को भेदने के लिए किया जा सकता है।
- प्रहार मिसाइल की मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। इस मिसाइल की लंबाई 7.32 मीटर है और इसका व्यास 420 मिलीमीटर है।
- इसका भार 1.28 टन है और यह 200 किलोग्राम का भार वहन कर सकती है।
- प्रहार समसामयिक हथियार प्रणाली है जो अनेक मुखास्त्र ले जाने के साथ साथ विभिन्न लक्ष्यों को एक साथ नष्ट करने की क्षमता रखती है।
- इससे पारंपरिक लड़ाई में दुश्मनों को गंभीर नुकसान हो सकता है। यह मोबाइल लॉन्चर से भी दागी जा सकती है।
- इसे दागे जाने की सभी तैयारी दो से तीन मिनट के अंदर ही पूरी की जा सकती है।
- इसकी खासियत यह है कि छह मिसाइल एक साथ एक जगह से अलग अलग दिशा में छोड़ी जा सकती हैं।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

जापान ने दक्षिण चीन सागर में पहली बार पनडुब्बी अभ्यास किया

चर्चा में क्यों?

- जापान ने पहली बार विवादित दक्षिण चीन सागर में पनडुब्बी अभ्यास किया है। यह सैन्य अभ्यास हालांकि चीन के दावे वाले जलक्षेत्र से दूर किया गया।
- मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स की पनडुब्बी कुरोशियो ने अन्य जंगी जहाजों के साथ दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास किया.

मुख्य तथ्य:

- इस सैन्य अभ्यास में कागा हेलीकॉप्टर पोत समेत जापानी युद्धपोतों ने भी हिस्सा लिया। यह पोत इस समय दो महीने के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया और हिद महासागर क्षेत्र की यात्रा पर है।
- यह पहला मौका है जब जापानी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में सैन्य अभ्यास शुरू किया है।
- रक्षा मंत्रालय ने एक अन्य बयान में कहा कि 80 चालकों के साथ कुरोशियो पनडुब्बी 17 सितम्बर 2018 से केम रान्ह खाड़ी के समीप वियतनाम के सामरिक नौसेना ठिकाने पर पांच दिनों तक रहेगा।
- अधिकतर समुद्री इलाके पर अपना दावा करने वाले चीन ने जापान को चेतावनी दी है कि वह ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे इलाके में शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचे।

दक्षिण चीन सागर पर दावा:

- चीन तकरीबन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है. इस दावे को मजबूती देने के लिए उसने कई कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य ठिकाने भी बना रखे हैं। दक्षिण चीन सागर से हर साल पोतों के जरिए पांच खरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार होता।
- चीन द्वारा वर्ष 2012 में फिलीपीन से जब्त किए जाने के बाद से ही स्कारबॉरो शोल को लेकर क्षेत्र में काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है। पनडुब्बी का अभ्यास दक्षिण चीन सागर में टोक्यो की तरफ से की गई पहली ऐसी कवायद थी।
- चीन वैसे तो पूरे दक्षिण चीन सागर पर ही अपने अधिकार का दावा करता है, लेकिन ब्रूनेई, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और ताइवान भी उस पर अपना दावा करते हैं। इस क्षेत्र में स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका भी सैन्य अभ्यास कर चुका है। पिछले माह (अगस्त 2018) ब्रिटेन की नौसेना का युद्धपोत एचएमएस एल्बियन दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे वाले द्वीपों के पास से गुजरा था।

स्रोतः द हिंदू

'मैन पोर्टेबल ऐंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल' का सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों?

- भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित किए गए मैन पोर्टेबल ऐंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (एमपीएटीजीएम) का 16 सितम्बर 2018 को महाराष्ट्र के अहमदनगर रेंज पर सफल परीक्षण किया गया।
- इसका पहला परीक्षण 15 सितम्बर 2018 को किया गया था. यह परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। बता दें कि इसे पूरी तरह भारत में ही विकसित किया गया है। इस परीक्षण से सभी मिशन उद्धेश्यों को पूरा किया गया है। दो मिशनों को अधिकतम सीमा क्षमता सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कर पूरा किया गया।

मैन पोर्टेबल ऐंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल:

मुख्य तथ्य:

- यह मिसाइल भारत की 'नाग' मिसाइल सीरीज का हिस्सा है। आसानी से ले जा सकने वाले इस मिसाइल से टैंक को ध्वस्त किया जा सकता है।
- इस तरह के हथियार होने से दुर्गम जगहों पर भी दुश्मनों के टैंक और अन्य ठिकानों को उड़ाने में सेना को काफी मदद मिलेगी।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- ये मिसाइल कंधे पर रखकर चलाई जा सकती है।
- कंधे पर रखकर चलाए जा सकने वाले इस मिसाइल की रेंज क्षमता 4 किलोमीटर तक हो सकती है।
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मिसाइल का अलग-अलग रेंज और अधिकतम रेंज क्षमता के लिए परीक्षण किया गया।
- ये दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइलो में शामिल है और सफल परीक्षण के बाद इसे फ्रांस निर्मित उन मिसाइलों की जगह पर इस्लेमाल किया जाएगा जिन्हें भारत इससे पहले इस्तेमाल करता आया है। वहीं, इसके आने के बाद सोवियत रूस के दौर से इस्तेमाल हो रही मिसाइलों को भी रिप्लेस कर दिया जाएगा।

स्रोतः द हिंदू

इसरो ने दो ब्रिटिश उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया

चर्चा में क्यों?

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 16 सितंबर 2018 को श्रीहरिकोटा से अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान - पी.एस. एल.वी- सी42 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।
- श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र के प्रथम प्रक्षेपण स्थल से इसरो ने इसके जरिए दो विदेशी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाया। इसमें नोवासार और एस 1-4 शामिल हैं। दोनों उपग्रहों को लेकर पीएसएलवी-सी 42 अंतरिक्ष यान रात 10:08 बजे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लांचपैड से रवाना हुआ। पीएसएलवी ने उपग्रहों को प्रक्षेपण के 17 मिनट 45 सेकंड बाद कक्षा में स्थापित कर दिया।

मुख्य तथ्यः

- इन उपग्रहों का वजन 800 किलोग्राम है। यह दोनों उपग्रह ब्रिटेन की सर्रे सेटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के हैं।
- यह इस वर्ष का पहला व्यवसायिक मिशन है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन व्यवसायिक स्तर पर 280 से अधिक विदेशी उपग्रह अंतरिक्ष में भेज चुका है।
- पीएसएलवी इसरो का एक मात्र ऐसा विश्वसनीय यान है जो 12वीं बार छोड़ा गया. पीएसएलवी-सी42 के सफल प्रक्षेपण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है।
- इसके साथ ही भारत उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया, जिसके पास विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने या भेजने की अपनी तकनीक और क्षमता मौजूद है।

ब्रिटिश उपग्रहों के बारे में जानकारी

- ब्रिटेन के दो उपग्रह नोवासार और एस 1- 4 को धरती की कक्षा में स्थापित किया गया है।
- नोवासार एक तकनीक प्रदर्शन उपग्रह मिशन है।
- इसमें कम लागत वाला एस बैंड सिंथेटिक राडार भेजा गया है।
- इसे धरती से 580 किलोमीटर ऊपर सूर्य की समकालीन कक्षा (एसएसओ) में स्थापित किया गया है।
- उपग्रह एसन 1-4 एक भू-अवलाकेन उपग्रह है, जो एक मीटर से भी छोटी वस्तु को अंतरिक्ष से देख सकता है। यह उपग्रह एसएसटीएल के अंतरिक्ष से भू-अवलोकन की क्षमता को बढ़ाएगा।

इसरो की पिछली प्रमुख उपलब्धियां

- इसरो (ISRO) ने पहली बार व्या वसायिक उद्देश्यत के लिए राकेट लॉन्च किया था।
- पीएसएलवी सी-ए ने इटली के खगोलीय उपग्रह एजाइल (AGILE) को प्रक्षेपित किया था।
- इसके बाद 10 जुलाई 2015 को इसरो ने एक और उपलब्धि हासिल की जब उसने पीएसएलवी-28 से पांच ब्रिट्रिश उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया, जिसका कुल वजन एक हजार 439 किलोग्राम था।
- इसरो अब तक 28 देशों के 237 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपण कर चुका है।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत में 21.40 लाख लोग एड्स से पीड़ित : नाको रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) द्वारा 14 सितंबर 2018 को एचआईवी आकलन 2017 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 तक भारत में 21.4 लाख लोग एचआईवी से ग्रस्त थे, जिनमें करीब 40 प्रतिशत महिलाएं थीं।
- एचआईवी आकलन 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल एचआईवी के करीब 87580 नए मामले दर्ज किये गए और 69110 लोगों की एड्स की वजह से मृत्यु हो गई. भारत में एचआईवी आकलन का पहला संस्करण 1998 में आया था, जबकि पिछला संस्करण वर्ष 2015 में जारी हुआ था।

नाको द्वारा जारी एचआईवी एड्स रिपोर्ट: मुख्य तथ्य:

- वर्ष 2000 के बाद से एचआईवी संक्रमण के सालाना नए मामलों में 60 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है, लेकिन 2010 और 2017 के बीच गिरावट की दर 27 प्रतिशत रही।
- यह संक्रमण के नए मामलों में 2020 तक 75 फीसदी कमी लाने के लक्ष्य पर पहुंचने के लिहाज से बहुत पीछे है।
- रिपोर्ट के अनुसार 2017 में भारत में एचआईवी पीड़ित लोगों (पीएलएचआईवी) की संख्याा लगभग 21.40 लाख थी, इनमें वयस्क पीडिघ्तों की संख्याव 0.22 फीसदी थी।
- साल 2000 के मुकाबले एचआईवी संक्रमण की दर 60% कम हुई है।
- व्यस्कों में एचआईवी संक्रमण की दर जम्मू-कश्मीर में सबसे कम 0.03% है, जबकि महाराष्ट्र 15% के साथ सबसे आगे है, यहां 3.30 लाख एड्स के मरीज हैं।

पांच राज्यों में बढ़ोतरी

- पांच राज्यों को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर नए संक्रमण के मामले कम हो रहे है। इन पांच राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय और उत्तराखंड हैं।
- इन राज्यों में 2010 की तुलना में पिछले साल इन मामलों में बढ़ोतरी हुई। संसद के एक पैनल ने स्वास्थ्य मंत्रालय से एचआईवी संक्रमितों के लिए देश भर में एंटी-रेट्रोवायरल उपचार केंद्र स्थापित करने और इसे जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा था।
- इससे एचआईवी प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए 'सस्ती और प्रभावकारी' दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

रिपोर्ट में दर्ज की गई कमी

- रिपोर्ट में बताया गया है कि 1995 में एड्स महामारी की अधिकता की तुलना में कार्यक्रम के प्रभाव में इसके संक्रमण में 80 फीसदी से अधिक की कमी आई है। इसी तरह 2005 में एड्स से संबंधित मौत की अधिकता की तुलना में 71 फीसदी की कमी आई है। यूएन-एड्स 2018 की रिपोर्ट के अनुसार एड्स के नये संक्रमण और एड्स से संबंधित मौतों का वैश्विक औसत घटकर क्रमश: 47 फीसदी और 51 फीसदी तक आ गया है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन

- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको (NACO) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित विभाग है। यह भारत में एचआईवी / एड्स की रोकथाम के लिए 35 नियंत्रण समुदायों के माध्यम से कार्यक्रम का नियंत्रण तथा नेतृत्व प्रदान करता है।
- 1986 में भारत में पहली बार एड्स के मामले का पता चलते ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन किया। एड्स के विस्तार के साथ ही भारत में इसके प्रति जागरुकता लाने तथा रोकथाम के उपाय करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाने की जरूरत महसूस होने लगी।
- इसके साथ ही ऐसे कार्यक्रम चलाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता भी महसूस की गई। 1992 में भारत का पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (1992-1999) शुरू किया गया था और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) कार्यक्रम को लागू करने के लिए गठित किया गया था।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत और फ्रांस ने गगनयान मिशन के लिए समझौता किया

चर्चा में क्यों?

- भारत और फ्रांस ने अंतरिक्ष तकनीक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाते हुए 06 सितंबर 2018 को गगनयान पर साथ मिलकर काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये. इस समझौते के पश्चात् भारत और फ्रांस ने गगनयान के लिए एक कार्यकारी समूह की घोषणा भी की।
- फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष जीन येव्स ली गॉल द्वारा बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के छठे संस्करण के दौरान घोषणा की गयी। भारत की 2022 से पहले अंतरिक्ष में तीन मनुष्यों को भेजने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर इसरो के पहले मानव यान मिशन की घोषणा की थी।

भारत-फ्रांस गगनयान समझौते की विशेषताएं

- इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी सीएनइएस अंतरिक्ष औषधि, अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी करने, जीवन रक्षा मुहैया कराने, विकिरणों से रक्षा, अंतरिक्ष के मलबे से रक्षा और निजी स्वच्छता व्यवस्था के क्षेत्रों में संयुक्त रूप से अपनी विशेषज्ञता मुहैया कराएंगे।
- दोनों एजेंसियां मिलकर इसरो के अन्तरिक्ष यात्रियों को बेहद कम गुरुत्वाकर्षण पर प्रयोग करेंगे।
- दोनों देशों ने मंगल ग्रह, शुक्र और क्षुद्र ग्रह पर भी काम करने की योजना के बारे में विचार साझा किये हैं।
- फ्रांस के पास अंतरिक्ष अस्पताल जैसी सुविधा में मौजूद है तथा वह भारत के साथ यह जानकारी साझा करने के लिए तैयार है।
- गौरतलब है कि फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों मार्च 2018 में दिल्ली की यात्रा पर आए थे और भारत तथा फ्रांस ने अंतरिक्ष सहयोग पर संयुक्त दृष्टिपत्र (विजन) जारी किया था।

गगनयान मिशन के उद्देश्य

- देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर में वृद्धि
- एक राष्ट्रीय परियोजना जिसमें कई संस्थान, अकादमिक और उद्योग शामिल हैं
- औद्योगिक विकास में सुधार
- युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत
- सामाजिक लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का विकास
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग में सुधार

✸ भारत की वर्ष 2022 से पहले, तीन मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है जिसे गगनयान नाम दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मिशन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत को दुनिया के चौथे देश की फेहरिस्त में शामिल करेगा जिसने कोई मानवयुक्त यान अंतरिक्ष में भेजा है।

स्रोत: द हिंदू

बीईएल को नेवी के लिए मिसाइल बनाने का अनुबंध प्राप्त हुआ

चर्चा में क्यों?

- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) को 05 सितंबर 2018 को भारतीय नौसेना के लिए लम्बी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एलआरएसएएम) बनाने हेतु अनुबंध प्राप्त हुआ है।
- बीईएल के साथ किये गये इस समझौते की लागत 9,200 करोड़ रुपये है। बीईएल का यह समझौता मैजगौन डॉक लिमिटेड (एमडीएल) एवं गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजिनियर्स (जीआरएसई) के साथ हुआ है।

मुख्य तथ्य:

- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) द्वारा बनाई जाने वाली मिसाइलें (एलआरएसएएम) सात नौसेनिक जहाजों पर तैनात की जायेंगी।
- बीईएल द्वारा किया गया यह अब तक का सबसे बड़ा समझौता है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- आकाश मिसाइल के प्रमुख निर्माता सहयोगी रही बीईएल ने टर्नकी मिसाइल सिस्टम में अपनी क्षमता दिखाई है।
- बीईएल इस समझौते के साथ ही थल सेना के लिए क्विक रिस्पांस सिस्टम मिसाइल (क्यूआरएसएएम), मीडियम रेंज सरफेस मिसाइल (एमआरएसएएम) वायु सेना के लिए तथा लॉन्ग रेंज सरफेस तो एयर मिसाइल (एलआरएसएएम) नौसेना के लिए निर्माण करेगी।

एलआरएसएएम मिसाइल प्रणाली

- भारत की सबसे पहले एलआरएसएएम प्रणाली को डीआरडीओ और इजराइल के आइएआइ के मध्य एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित किया गया।
- एलआरएसएएम हवाई लक्ष्यों और मिसाइलों के खिलाफ एक उन्नत मिसाइल रक्षा कवच है।
- यह हवा और सतह की निगरानी, खतरे की चेतावनी और आग पर नियंत्रण की पूर्ण क्षमता रखती है।
- मिसाइलों के उड़ान की गति को आईटीआर में स्थापित राडारों और विद्युत ऑप्टिकल प्रणालियों द्वारा पता लगाकर नजर रखी जा सकती है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सैन्य एवं नागरिक उपकरण एवं संयंत्र निर्माण ईकाई है।
- भारत सरकार द्वारा सन 1954 में सैन्य क्षेत्र की विशेष चुनौतीपूर्ण आवश्यकताऐं पूरी करने हेतु रक्षा मन्त्रालय के अधीन इसकी स्थापना की गई थी।
- इलेक्ट्रानिक उपकरण व प्रणालियों का विकास तथा उत्पादन देश में ही करने के उद्देश्य से इसका पहला कारखाना बंगलुरू में लगाया गया था, किन्तु आज यह अपनी नौ उत्पादन इकाईयों, कई क्षेत्रीय कार्यालय तथा अनुसन्धान व विकास प्रयोगशालाओं से युक्त सार्वजनिक क्षेत्र का एक विशाल उपक्रम है, जिसे अपने व्यावसायिक प्रदर्शन के फलस्वरूप भारत सरकार से नवरत्न उद्योग का स्तर प्राप्त हुआ है।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा की पहली बैठक दो अक्टूबर को होगी

चर्चा में क्यों?

- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा की पहली बैठक 02 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, उस दिन बैठक के बाद ग्रेटर नोएडा में मं त्रस्तरीय बैठक भी होगी।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। इसमें शामिल होने के लिए गठबंधन के दायरे में आने वाले सभी 121 देशों को आमंत्रित किया गया है।

मुख्य तथ्य:

- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) महासभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पहल है जो सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग के जरिये पेरिस जलवायु समझौता को लागू करने में योगदान देगा।
- आईएसए के स्थापना सम्मेलन का आयोजन 11 मार्च 2018 को संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने नई दिल्ली में किया था. इसका मकसद सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
- आईएसए की स्थापना बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 1.4 अरब डालर ऋण सुविधा की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी जो अफ्रीका समेत 15 देशों में 27 परियोजनाओं को आवरण करेगी।
- महासभा की बैठक के बारे में 20 सितंबर 2018 को पूर्वी क्षेत्र के सचिव टी एस त्रिमूर्ति ने विदेश मंत्रालय की एक बैठक में 50 से अधिक विदेशी रेसिडेंट मिशन को इसकी जानकारी दी थी। साथ ही इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक भी हो रही है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए):

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर-सरकारी संगठन है।
- भारत ने भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल की थी।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का एक सहयोग संगठन है।
- इसका शुभारंभ भारत और फ्राँस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था।
- इस संगठन में ये सभी देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे।
- इस प्रयास को वैश्विक स्तर पर ऊर्जा परिदृश्य में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
- आईएसए पहली ऐसी संस्था है जिसका मुख्यालय भारत में गुरूग्राम में है।
- फ्रांस, इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सफल होने के लिए 2022 तक 5600 करोड़ रुपये का फंड देगा जिससे सदस्य देशों में अन्य सोलर प्रोजेक्ट शुरू किये जायेंगे।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2030 तक 1 ट्रिलियन वाट (1000 गीगावाट) सौर ऊर्जा उत्पादन का है, जिस पर अनुमानत: 1 ट्रिलियन डॉलर का खर्च आयेगा।
- आईएसए के कार्यकारी मसौदे में यह स्पष्ट किया गया है कि आईएसए का मूल उद्देश्य सभी के लिये किफायती, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा की पहुँच सुनिश्चित करना है।
- इससे दूर-दराज के क्षेत्रों में भी उर्जा की बढती मांग को पूरा किया जा सकता है तथा जीवनस्तर में सुधार लाया जा सकता है।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

तमिलनाडु सरकार द्वारा नीलकुरिंजी पौधे के संरक्षण की घोषणा

चर्चा में क्यों?

- तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में नीलकुरिंजी नामक पौधे के संरक्षण के लिए योजना की घोषणा की है। यह पौधा बारह वर्षों में एक बार खिलता है। हाल ही में सरकार को इस पौधे के फूलों की व्यापारिक बिक्री की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया।

नीलकुरिंजी पौधा

- यह एक किस्म का उष्णकटिबंधीय पौधा है। यह पौधा पश्चिमी घाट के शोला वन में पाया जाता है। पूर्वी घाट में यह पौधा शेवरॉय पहाड़ियों में पाया जाता है।
- यह पौधा केरल में अनामलाई हिल्स और अगाली हिल्स तथा कर्नाटक के संदुरु हिल्स में पाया जाता है।
- इस पौधे की लम्बाई 30 से 60 सेंटीमीटर होती है। यह पौधा 1300 से 2400 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों पर उगता है।
- नीलकुरिंजी के फूल बैंगनी-नीले रंग के होते हैं। इसमें 12 वर्षों में एक बार ही फूल खिलते हैं।
- इन फूलों के कारण ही पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों को नीला पर्वत कहा जाता है।
- इसे दुर्लभ किस्म का पौधा घोषित किया गया है।
- यह पश्चिम घाट के अतिरिक्त विश्व के किसी दूसरे हिस्से में नहीं उगता। यह पौधा संकटग्रस्त पौधों की प्रजाति में शामिल है।

पौध-संरक्षण क्या होता है?

- फसल-उत्पादन के लक्ष्य हासिल करने में पौध-संरक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पौध संरक्षण के महत्वपूर्ण घटकों में समन्वित कीट प्रबंधन को प्रोत्साहन, फसल पैदावार को कीटों और बीमारियों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ज्यादा पैदावार देने वाली नई फसल प्रजातियों को तेजी से अपनाए जाने के लिए संगरोधन (क्वारन्टीन) उपायों को सुचारू बनाना शामिल है।
- इसके अंतर्गत बाहरी कीटों के प्रवेश की गुंजाइश समाप्त करना और पौध-संरक्षण कौशल में महिलाओं को अधिकारिता प्रदान करने सहित मानव संसाधन विकास पर भी ध्यान दिया जाता है।

स्रोत: द हिंदू

जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कार्बन टैक्स जरूरी: विश्व बैंक

चर्चा में क्यों?

- विश्व बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टलीना जॉर्जिया ने जलवायु परिवर्तन पर कनाडा में 20 सितंबर 2018 को हुई जी-7 की बैठक में कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन पर कर लगाना या कार्बन प्रदूषण पर शुल्क लगाना जरूरी है।
- प्रति टन कार्बन उत्सर्जन पर शुल्क आकलन की प्रक्रिया का हवाला देते हुए विश्व बैंक ने कहा कि हमारा मानना है कि कार्बन के लिए एक शैडो शुल्क तय करके हम एक आर्थिक संकेत दे सकते हैं।

46 देशों ने शुल्क लागू किया:

- इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इकोनॉमिक्स के अनुसार वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री इस पर एकमत हैं कि अर्थव्यवस्थाओं को व्यवहार में बदलाव लाने का संकेत देने का सबसे अच्छा तरीका कार्बन शुल्क है। 01 अप्रैल 2018 से 46 देशों और 26 द्वीपीय सरकारों ने कार्बन शुल्क लागू किया है।

कर के तहत कंपनियों को दिया जाएगा कोटा:

- कर के तहत सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों को कोटा दिया गया है। उन्हें साथ ही अन्य कंपनियों के साथ कोटे की खरीद-बिक्री का अधिकार भी दिया गया है। इन नीतियों के तहत एक टन उत्सर्जित कार्बन का मूल्य एक डॉलर से लेकर 133 डॉलर तक तय किया गया है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

कार्बन कर क्या है?

- कार्बन कर एक अप्रत्यक्ष कर है। यह उन आर्थिक गतिविधियों पर लगाया जाता है जिनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनजीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- इसके द्वारा सरकारें अपना राजकोष भी संवर्धित करती हैं। इस कर से दो अन्य कर भी संबंधित हैं- उत्सर्जन कर और ऊर्जा कर। उत्सर्जन कर जहाँ प्रत्येक टन हरितगृह गैस के उत्सर्जन पर लगने वाला कर है,
- वहीं ऊर्जा कर ऊर्जा से संबंधित वस्तुओं पर आरोपित कर है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1992 में बढ़ते हरितगृह गैस के स्तर को नियंत्रित करने तथा इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने की दिशा में पहल की।

भारत में कार्बन कर:

- भारत मे 01 जुलाई 2010 से कार्बन कर को लागू कर दिया गया है। वर्तमान मानक के अनुसार प्रति मीट्रिक टन कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन पर 50 रुपये कर स्वरूप संबंधित कम्पनियों को अदा करना पड़ता है।
- भारत कार्बन कर को स्वविवेक पहल प्रक्रिया और पर्यावरण पर राष्ट्रीय कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए दायित्वबोध से प्रेरित होकर कर रहा है।

अन्य देश:

- हालांकि इस दिशा में पहले से पहल करते हुए फिनलैण्ड ने वर्ष 1990 मे अपने यहाँ कार्बन कर लगाने की शुरुआत की। ऐसा करने वाला फिनलैण्ड पहला राष्ट्र है। तत्पश्चात स्वीडन और ब्रिटेन ने वर्ष 1991 में इस प्रक्रिया को अपनी भूमि पर लागू किया।

पृष्ठभूमि:

- यूरोपीय संघ ने वर्ष 2005 में अपने यहां एमिशन ट्रेडिंग स्कीम (ईटीएस) लागू की थी। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाना था। यूरोपीय संघ के अनुसार कार्बन उत्सर्जन में तीन प्रतिशत भागीदारी विमानों से फैलने वाले प्रदूषण की है। इसे रोकने हेतु संघ ने यूरोप के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और वहां के आकाश से गुजरने वाले विमानों पर कार्बन उत्सर्जन टैक्स लगाने की घोषणा की थी।

स्रोत: द हिंदू

प्रदूषण नियंत्रण हेतु 'वायु' प्रणाली का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण से निजात पाने की दिशा में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पहल की गई है जिसके तहत दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए "वायु" नामक मशीनें लगाई जायेंगी।
- काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च-नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट(सीएसआईआर-नीरी) की तरफ से विकसित विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिंग यूनिट (वायु) का केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीक मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा शुभारंभ किया गया।

वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली

- यह हवा साफ करने की एक मशीन है जिसे व्यस्त व प्रदूषित चौराहों पर लगाया जायेगा।
- यह धूल कणों को सोख लेगा तथा वायु यंत्र दो सिद्धांत पर काम करेगा।
- पहले, हवा में जो प्रदूषित कण है उसे सोखेगा. दूसरा, एक्टिव प्रदूषण उसमें से हटा देगा।
- ये यंत्र पर्टिकुलेट मैटर निकालकर उसमें कार्बन एक्टिवेट करेगा. यह जहरीली गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड को हवा से खत्म करेगा।
- इस यंत्र में 1 पंखा और 1 फिल्टर है जो पर्टिकुलेट मैटर को सोखेगा।
- दो लैंप और आधा किलो कार्बन चारकोल जिसमें टाइटेनियम डाईऑक्साइड कैमिकल मिला होगा, वो भी यंत्र में होगा।
- उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण पद्धति के अतिरिक्त नीरी ने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को शवदाह गृहों में धुएं को रोकने के लिए स्क्रबर और ढाबों में इस्तेमाल के लिए एक खास तरह का तंदूर डिजाइन सौंपा है। यह शवदाह गृहों व ढाबों में होने वाले प्रदूषण को 40% तक कम करेगा।

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

❒ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा फ्रांस के राष्ट्रपति को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान से सम्मानित किया गया

चर्चा में क्यों?

❒ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को 26 सितंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान, 'चौंपियंस ऑफ द अर्थ' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मुख्य तथ्य

❒ भारत के साथ-साथ फ्रांस को भी इस पुरस्कार के लिए इसलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि दोनों ही देशों ने समान प्रयासों के साथ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की है।

❒ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को लेकर अग्रणी एवं उत्साही कार्यों के लिए और पर्यावरणीय कार्यों में सहयोग के नये क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी और इमैनुएल मैक्रों को श्नीति नेतृत्वश श्रेणी के तहत यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

❒ प्रधानमंत्री को 2022 तक भारत में प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने का संकल्प लेने और मैक्रों को पर्यावरण के लिए वैश्विक समझौते को लेकर सराहना की गयी।

❒ दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने पूरे विश्व में इस बारे में जाग्रति फैलाई तथा अन्य देशों को भी सौर गठबंधन में शामिल करने हेतु सफलतापूर्वक प्रोत्साहित किया।

चौंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड

❒ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने वर्ष 2005 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से उत्कृष्ट पर्यावरण हितैषी कार्य करने वाले व्यक्तियों को पहचानने के लिए वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम के रूप में 'चौंपियंस ऑफ अर्थ' पुरस्कार की स्थापना की।

❒ आम तौर पर प्रतिवर्ष पांच से सात विजेताओं का चयन किया जाता है. प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक ट्रॉफी प्राप्त करने के लिए एक पुरस्कार समारोह में आमंत्रित किया जाता है. विजेता पुरस्कार प्राप्ति हेतु भाषण देते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं।

❒ वर्ष 2017 में 'यंग चौंपियंस ऑफ अर्थ' श्रेणी की भी शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत 18 से 30 वर्ष के उन व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक एवं उत्कृष्ट पहल की हो।

स्रोतः द हिंदू

गृह मंत्रालय एवं इसरो ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये

चर्चा में क्यों?

❒ गृह मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने गृह मंत्रालय में आपातकालीन स्थिति के लिए एक अत्याधुनिक समेकित नियंत्रण कक्ष की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया।

❒ इस एमओयू पर गृह मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन) संजीव कुमार जिंदल एवं इसरो के एनआरएससी के उपनिदेशक डॉ. पी वी एन राव ने हस्ताक्षर किए।

प्रमुख तथ्य

❒ इसरो प्रस्तावित समेकित नियंत्रण कक्ष की स्थापना के लिए अपनी तकनीकी विशेषज्ञता देगा जबकि परियोजना का निष्पादन गृह मंत्रालय के पर्यवेक्षण में होगा।

❒ प्रस्तावित नियंत्रण कक्ष के अगले डेढ़ वर्ष में स्थापित हो जाने की उमीद है।

❒ यह आईसीआर-ईआर आपदा प्रबंधन के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करेगा।

❒ आईसीआर-ईआर निकट वास्तविक समय के आधार पर जानकारी प्राप्त होने की आवश्यकता को संबोधित करेगा।

❒ यह रणनीतिक स्तर की निगरानी, स्थिति पर नजर बनाए रखना, आदेश और नियंत्रण, तैयारी और विविध आंतरिक सुरक्षा स्थिति और आपदा से संबंधित आपात स्थिति में प्रतिक्रिया को भी संबोधित करेगा।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)

- वर्ष 1962 में जब भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (इन्कोंस्पार) का गठन हुआ तब भारत ने अंतरिक्ष में जाने का निर्णय लिया।
- वर्ष 1959 में इसरो की स्थापना की गई थी तथा प्रोफेसर विक्रम साराभाई को इसका चेयरमैन बनाया गया।
- आज भारत न सिर्फ अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है बल्कि दुनिया के बहुत से देशों को अपनी अंतरिक्ष क्षमता से व्यापारिक और अन्य स्तरों पर सहयोग कर रहा है।
- इसरो को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए साल 2014 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- मंगलयान के सफल प्रक्षेपण के लगभग एक वर्ष बाद इसरो ने 29 सितंबर 2015 को एस्ट्रोसैट के रूप में भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित की।
- वर्ष 2017 में इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों का सफल परीक्षण करके विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था।

स्रोत: पीआईबी

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ रिपोर्ट: गंगा विश्व की सबसे संकटग्रस्त नदियों में से एक

चर्चा में क्यों?

- वर्ल्ड वाइड फंड फोर नेचर (WWF) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गंगा विश्व की सबसे अधिक संकटग्रस्त नदियों में से एक है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लगभग सभी दूसरी भारतीय नदियों की तरह गंगा में लगातार पहले बाढ़ और फिर सूखे की स्थिति पैदा हो रही है।
- देश के सबसे पवित्र स्थानों में शामिल ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग और काशी, गंगा के तट पर स्थित हैं। इसके अलावा केदारनाथ, बद्रीनाथ और गोमुख गंगा और उसकी उपनदियों के किनारे स्थित तीर्थ स्थानों में से एक हैं। जिन चार स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, उनमें से दो शहर हरिद्वार और प्रयाग गंगा तट पर स्थित हैं।

गंगा नदी के बारे में WWF की रिपोर्ट

- रिपोर्ट के अनुसार गंगा ऋषिकेश से ही प्रदूषित हो रही है।
- गंगा के किनारे लगातार बसायी जा रही बस्तियों चन्द्रभागा, मायाकुंड, शीशम झाड़ी में शौचालय तक नहीं हैं। इसलिए यह गंदगी भी गंगा में मिल रही है।
- कानपुर की ओर 400 किलोमीटर विपरीत जाने पर गंगा की दशा सबसे दयनीय दिखती है।
- ऋषिकेश से लेकर कोलकाता तक गंगा के किनारे परमाणु बिजलीघर से लेकर रासायनिक खाद तक के कारखाने लगे हैं जिसके कारण गंगा लगातार प्रदूषित हो रही है।
- गंगा के पानी में विषैले हानिकारक तत्व मिलकर इसे विश्व की सबसे भयावह नदियों में से एक बनाते हैं।
- इसका एक अन्य सबसे महत्वपूर्ण कारण इसमें प्रत्येक वर्ष भारी बाढ़ आना तथा फिर सूखे की स्थिति झेलना है।

गंगा नदी

- देश की सबसे प्राचीन और लंबी नदी गंगा उत्तराखंड के कुमायूं में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से 3140 मीटर है।
- उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक गंगा विशाल भू-भाग को सींचती है. गंगा भारत में 2,071 किमी और उसके बाद बांग्लादेश में अपनी सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है।
- यमुना गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, जो हिमालय की बंदरपूंछ चोटी के यमुनोत्री हिमखण्ड से निकलती है।
- गंगा उत्तराखंड में 110 किमी, उत्तर प्रदेश में 1,450 किलोमीटर , बिहार में 445 किमी और पश्चिम बंगाल में 520 किमी का सफर तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ

- पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष का गठन वर्ष 1961 में हुआ तथा उसी वर्ष इसका पंजीकरण एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में हुआ।
- यह संगठन पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रख-रखाव संबंधी मामलों पर कार्य करता है।
- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के प्रमुख उद्देश्य हैं – आनुवंशिक जीवों और पारिस्थितिक विभिन्नताओं का संरक्षण करना। यह सुनिश्चित करना कि नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग पृथ्वी के सभी जीवों के वर्तमान और भावी हितों के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं।
- इसका अन्य उद्देश्य प्रदूषण, संसाधनों और उर्जा के अपव्ययीय दोहन और खपत को न्यूनतम स्तर पर लाना भी है।

स्रोतः द हिंदू

विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सफाई अभियान 'ओशियन क्लीनअप' आरंभ

चर्चा में क्यों?

- विश्व भर में समुद्रों से प्रदूषण हटाने तथा समुद्रों की सफाई करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा अभियान 'ओशियन क्लीनअप' कैलिफोर्निया से आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य समुद्र से प्लास्टिक तथा अन्य कचरा निकालना एवं समुद्र को प्रदूषित होने से बचाना है।
- इस अभियान की शुरुआत करने वाले बोयान स्लाट नामक 24 वर्षीय युवा हैं. उनके अभियान को विश्व भर के वैज्ञानिकों ने समर्थन दिया। छह वर्ष तक इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद इसे 08 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया।

प्रोजेक्ट ओशियन क्लीनअप

- इस अभियान के तहत समुद्र में 'यू' आकार का 2,000 फुट का कलेक्शन सिस्टम डाला गया है जिसकी मदद से पानी में मिले कचरे को अलग किया जाता है।
- इस अभियान के तहत सबसे पहले कैलिफॉर्निया से हवाई तक लगभग 6,00,000 किलोमीटर के क्षेत्र में समुद्री क्षेत्र को साफ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- अनुमानित क्षेत्र 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर अर्थात टेक्सास के आकार से दोगुना अथवा फ्रांस के आकार का तीन गुना है।
- इस क्षेत्र में 80 हजार टन प्लास्टिक कचरा होने का अनुमान है जो कि 500 जंबो जेट विमानों के वजन के समान है।
- इस अभियान का लक्ष्य है कि हर साल समुद्र से करीब 50 टन कचरा साफ किया जा सके।
- यही नहीं समुद्र से निकाले जाने के बाद उन प्लास्टिक के कचरों को रिसाइकल करने की भी योजना बनाई गई है।

बोयान स्लाटः द ओशियन क्लीनअप

- डच नागरिक बोयान स्लाट जब सिर्फ 18 साल के थे तभी उन्होंने द ओशियन क्लीनअप नामक संस्था की शुरुआत की थी।
- बोयान अब से आठ साल पहले जब 16 साल के थे तब उन्होंने समुद्र मार्ग से ग्रीस की यात्रा की और उस दौरान वे समुद्र में प्लास्टिक कचरे के अम्बार देख कर हैरान हुए।
- उन्होंने ग्रीस जाने के दौरान समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक देखी तो इस अभियान पर काम करने का निर्णय लिया।
- उन्होंने अपने प्रोटोटाइप के जरिये वैज्ञानिकों को समुद्री कचरे से निपटने का मार्ग सुझाया. उनके इस अभियान से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने इस पर काम करने का निर्णय लिया।
- बोयान स्लाट को फोर्ब्स पत्रिका ने 2016 में 30 अंडर 30 सूची में स्थान दिया था।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

झारखंड सरकार ने अधिकारिक उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक कारों की सेवा आरंभ की

चर्चा में क्यों?

- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को सौंपे गए इलेक्ट्रिक वाहनों से 13 सितंबर 2018 को राज्य में इलेक्ट्रिक कारों की पहली बार शुरुआत की गई। इन कारों को राज्य के उर्जा विभाग के लिए खरीदा गया है।
- ऊर्जा विभाग ने इन कारों को अपने अधिकारियों के उपयोग के लिए खरीदा है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्रदूषण रहित पर्यावरण के लिए ऐसे उपाय और उपयोग जरूरी हैं।
- इस कार्य से झारखंड पूर्वी क्षेत्र का पांचवां राज्य बन गया है जिसने सरकारी उपयोग के लिए पर्यावरण हितैषी वाहनों का उपयोग आरंभ किया है।
- यह वाहन न केवल प्रदूषण कम करके पर्यावरण के संरक्षण में सहायक हैं बल्कि महंगे विदेशी वाहनों पर होने वाले खर्च में भी कमी लाने में सहायक हैं।

मुख्य तथ्य

- इलेक्ट्रिक कार 50 ऐसे वाहनों का हिस्सा हैं जो ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड अपने आधिकारिक उपयोग के लिए झारखंड बिजली विजन निगम (जेबीवीएनएल) को आपूर्ति करेगी।
- इस श्रेणी के लिए 20 इलेक्ट्रिक कारें डिलीवर कर दी गई हैं बाकी 30 कारें अगले दो सप्ताह में डिलीवर कर दी जायेंगी।
- झारखंड में सभी सरकारी कार्यालय जल्द ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने और राज्य प्रदूषण मुक्त रखने में मदद करने के लिए इलेक्ट्रिक कारों का चयन शुरू कर देंगे।
- राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार लोगों को ऐसी कारें खरीदने और चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए अपील करेगी।
- अब तक, रांची में 12 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं और बाकी जल्द ही आरंभ होने वाले हैं।
- इस कदम से राज्य को 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों के साथ 30 प्रतिशत सरकारी वाहनों को बदलने के केंद्र के ई-मोबिलिटी लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
- झारखंड से पहले दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना सरकारी काम-काज के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग आरंभ कर चुके हैं। पचास कारों के बेड़े के साथ आने से जेबीवीएनएल का हर साल 1.20 लाख लीटर ईंधन बचेगा और लगभग 14 सौ टन कार्बन डाईआक्साइड सालाना कम उत्सर्जित होगा। जेबीवीएनएल मरम्मत, देखरेख और परिचालन के क्षेत्र में भी बचत करेगा, क्योंकि इन इलेक्ट्रिक वाहनों में परिचालन पर कॉम्बस्टन इंजन के मुकाबले खर्च एक चौथाई होता है।

स्रोतः द हिंदू

अन्य खबरें

नोबल पुरस्कार 2018: चिकित्सा तथा भौतिकी क्षेत्र में पुरस्कार विजेताओं की घोषणा

- नोबेल पुरस्कार समिति द्वारा 02 अक्टूबर 2018 को भौतिकी के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की इस बार भौतिकी का नोबेल तीन लोगों को दिया जाएगा, जिसमें आर्थर अशकिन और गेर्राड मौरोउ और डोना स्ट्रिकलैंड का नाम शामिल है।
- इस पुरस्कार में आधा भाग आर्थर अशकिन जबकि आधे भाग में से गेर्राड मौरोउ और डोना स्ट्रिकलैंड को सम्मानित किया गया है।

भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2018

- नोबेल पुरस्कार इन वैज्ञानिकों को लेजर भौतिकी के फील्ड में अहम अविष्कार करने के लिए दिया गया है।
- डोन्ना स्ट्रिकलैंड भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला वैज्ञानिक हैं।
- आर्थर एश्किन अमेरिकन वैज्ञानिक हैं, जिनके ऑप्टिकल ट्वीजर्स और बायोलॉजिकल सिस्टम्स के संबंध में किए गए प्रयोगों को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने मान्यता दी है।
- गेरार्ड मोरोउ (फ्रांस) और डोन्ना स्ट्रिकलैंड (कनाडा) को हाई-इंटेसिटी, अल्ट्रा शॉर्ट ऑप्टिकल पल्स को जेनरेट करने के तरीके के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है।
- पिछले वर्ष भी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकों रेनर वीस, बैरी बैरिश और किप थ्रोन को दिया गया था। इन तीनों वैज्ञानिकों को गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था।

चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2018

- इस बार चिकित्सा के क्षेत्र में दो लोगों को सामूहिक तौर पर यह पुरस्कार दिया जा रहा है।
- जेम्स पी एलिसन और तासुकू होंजो को कैंसर थेरपी की खोज के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है।
- कैंसर की दुर्लभ बीमारी की इलाज के लिए दोनों वैज्ञानिकों ने ऐसी थेरपी विकसित की है।
- इससे शरीर की कोशिकाओं में इम्यून सिस्टम को कैंसर ट्यूमर से लड़ने के लिए मजबूत बनाया जा सकेगा।

डोना स्ट्रिकलैंड 55 वर्ष में नोबेल जीतने वाली पहली महिला

- कनाडा की डोना स्ट्रिकलैंड यह अवॉर्ड जीतने वाली तीसरी महिला हैं। उनसे पहले मैरी क्यूरी को 1903 और मारिया गोपर्ट-मेयर ने 1963 में भौतिकी का नोबेल जीता था। डॉक्टर स्ट्रिकलैंड और डॉक्टर मौरोउ ने बेहद छोटी मगर तेज लेजर पल्स बनाने में योगदान दिया है। उन्होंने चर्प्ड पल्स एंप्लिफिकेशन (सीपीए) नाम की तकनीक विकसित की है। अब इस तकनीक का इस्तेमाल कैंसर के इलाज और आंखों की सर्जरी में होता है।

नोबेल पुरस्कार

- प्रत्येक वर्ष विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में महान अविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
- यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस की ओर से प्रदान किया जाता है।
- इसमें पुरस्कार स्वरुप 7,70,000 पाउंड की राशि दी जाती है।
- इस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है क्योंकि नोबेल पुरस्कार का चुनाव करने वाली संस्था स्वीडिश एकेडमी की ज्यूरी की एक सदस्य के पति यौन शोषण के आरोपों में घिरे हैं जिसके चलते स्वीडिश एकेडमी विवादों में घिरी हुई है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

दिल्ली सरकार ने 40 सेवाओं के लिए डोरस्टेप डिलीवरी योजना आरंभ की

- राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ड्रीम प्रॉजेक्ट डोरस्टेप डिलिवरी योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत लोग अपनी इच्छा से घर बैठे जन्म और जाति प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड जैसे डॉक्युमेंट्स बनवा सकते हैं तथा इसके किसी भी सरकारी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी।
- वर्तमान दिल्ली सरकार का दावा है कि ऐसा देश ही नहीं दुनिया में पहली बार हो रहा है जिसमें जनता को इन 40 सेवाओं के लिए सरकारी विभाग या दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। सात सरकारी विभागों की 40 सेवाओं का लाभ घर बैठे उठाया जा सकता है।

डोरस्टेप डिलीवरी में शामिल सेवाएं

- जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शादी का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन, नया पानी या सीवर कनेक्शन या कटवाने के लिए आवेदन, इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, आरसी में पता बदलवाना आदि सुविधाओं का लाभ घर बैठे उठाया जा सकता है। इन सुविधाओं में शामिल विभाग हैं:

- राजस्व विभाग – 15 सेवाएं
- श्रम विभाग – 02 सेवाएं
- दिल्ली जलबोर्ड – 04 सेवाएं
- परिवहन विभाग – 11 सेवाएं
- खाद्य आपूर्ति – 02 सेवाएं
- समाज कल्याण – 03 सेवाएं
- एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग – 03 सेवाएं

डोरस्टेप डिलीवरी योजना

- दिल्ली सरकार इन सभी 40 सेवाओं के लिए एक खास नंबर जारी करेगीं
- आवेदक या सेवा लेने के इच्छुक व्यक्ति को उस नंबर पर फोन करके 'मोबाइल सहायक' से अपॉइंटमेंट तय करना होगा यानी सरकार के प्रतिनिधि को वो किस समय अपने घर बुलाना चाहता है ये तय करना होगां
- सुबह 8 से रात 8 बजे के बीच किसी भी समय आवेदक मोबाइल सहायक के लिए अपॉइंटमेंट तय कर सकता है।
- तय समय के मुताबिक मोबाइल सहायक एक टैबलेट के साथ आवेदक के बताए पते पर आएगा और जरूरी दस्तावेज अपलोड करेगा।
- प्रक्रिया पूरी होने के बाद मोबाइल सहायक 50 रुपये सुविधा शुल्क नाम की फीस वसूल करेगा जिसके बाद जो सर्टिफिकेट आवेदकों चाहिए वह पोस्ट के जरिए उसके घर पहुंच जाएगा।

एशियाई खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

- इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किये गये 18वें एशियाई खेलों के समापन होने तक भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 69 मेडल हासिल किये जिसमें 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं।
- 14वें दिन ब्रिज प्रतियोगिता में भारत के प्रणब बर्धन और शिबनाथ सरकार ने गोल्ड मेडल जीतते ही इतिहास बना दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने न सिर्फ इस गेम में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता बल्कि एशियाई खेलों में भारत के गोल्ड मेडलों की संख्या 15 की।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन

- भारत ने उन खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन किया जिनमें भारत अब तक विशेष पहचान नहीं बना सका है। एक जमाना था जब कहा जाता था कि भारत में क्रिकेट के अतिरिक्त किस और खेल के लिए जगह नहीं है। एथलेटिक्स खेलों को भारतीयों के लायक नहीं समझा जाता था लेकिन 18वें एशियाई खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने इस भ्रम को भी दूर किया है।
- हेप्टाथलॉन में स्वप्ना बर्मन ने देश को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया।
- ट्रिपल जम्प में अपरिंदर सिंह द्वारा 50 वर्ष बाद गोल्ड मेडल जीता गया।
- पीवी सिंधू एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनीं।
- विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी रहीं जिन्होंने एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता।
- नीरज चोपड़ा भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने।
- फवाद मिर्जा घुड़सवारी में 1982 के बाद मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने।
- एथलेटिक्स में भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं जबकि 10 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल भी अर्जित किये हैं।

पृष्ठभूमि

- जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में स्वर्ण पदकों के मामले में भारत ने वर्ष 1951 के रिकॉर्ड की बराबरी की है। पदकों की कुल संख्या के आधार पर भी भारत ने इन खेलों के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाया है। पिछले एशियाई गेम्स (2014) में भारत 57 पदक ही जीत पाया था, जिनमें 11 स्वर्ण पदक थे। भारत दक्षिण कोरिया के इंचियोन में हुए खेलों में आठवें नंबर पर रहा था।

खेल : मेडल

खेल	गोल्ड	सिल्वर	ब्रॉन्ज	कुल
एथलेटिक्स	7	10	2	19
शूटिंग	2	4	3	9
कुश्ती	2	–	1	3
ब्रिज	1	–	2	3
रोइंग	1	–	2	3
टेनिस	1	–	2	3
बॉक्सिंग	1	–	1	3
तीरंदाजी	–	2	–	2
एक्वेस्ट्रियन	–	2	–	2
स्क्वैश	–	1	4	5
नौकायन	–	1	2	3
बैडमिंटन	–	1	1	2
हॉकी	–	1	1	2
कबड्डी	–	1	1	2
कुराश	–	1	1	2
वुशु	–	–	4	4
टेबल टेनिस	–	–	2	2
सेपक्ताक्राव	–	–	1	1

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अच्छे प्रदर्शन का कारण और सरकार की खेल योजनाएं

- भारतीय खिलाड़ियों द्वारा 18वें एशियाई खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने का श्रेय न केवल खिलाड़ियों की व्यक्तिगत तैयारियों को जाता है बल्कि सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं से मिलने वाले लाभ को भी जाता है। केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई खेलो इंडिया योजना, अखिल भारतीय छात्रवृत्ति योजना, टारगेट ओलंपिक पोडियम तथा राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम योजनाओं से भी खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर कर सामने आई है।

- खेलो इंडिया कार्यक्रमः भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए खेलों इंडिया कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। पूर्व सरकारों द्वारा संचालित राजीव गांधी खेल अभियान, शहरी खेल विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। इस योजना के अंतर्गत देश में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा हैं योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष चुनिंदा खेलों में 1000 प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत चुने गए प्रत्येक खिलाड़ी को 1 वर्ष में 5 लाख रूपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष प्रतिभावान खिलाड़ियों को लंबे समय तक विकास का मार्ग उपलब्ध कराया जाना है।

- टारगेट ओलंपिक पोडियम योजनाः केंद्र सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (ज्व्च्ै) शुरू की है. इस योजना में खिलाड़ियों के चयन और प्रशिक्षण की जिम्मेदारी पूर्व खिलाड़ियों और लंबे समय से खेल प्रशासन से जुड़े लोगों को दी गई है. इस योजना को लागू करने के लिए आठ सदस्यीय पैनल का भी गठन किया गया है. यह योजना वर्ष 2020 तक आयोजित होने वाले सभी महत्वपूर्ण खेल आयोजनों तक लागू रहेगी. आठ सदस्यीय पैनल विभिन्न खेलों के 75 से 100 खिलाड़ियों के पूल का चयन करेगा. चयनित खिलाड़ियों को अगले दो ओलंपिक खेलों में 25 से 30 मेडल जीतने के लक्ष्य के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा ध्यान एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी और निशानेबाजी के साथ-साथ उन खेलों पर भी होगा जिनमें भारतीय खिलाड़ियों के पदक जीतने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं।

- राष्ट्रीय खेल विकास कोषः केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खेल विकास कोष का गठन देश में खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसके अंतर्गत प्रवासी भारतीयों और निजी-कार्पोरेट क्षेत्र सहित सरकारी और गैर-सरकारी सभी स्रोतों से पैसा जुटाया जाता है। कोष में सहायता करने को आकर्षक बनाने के लिए अंशदान की राशि को आयकर से शत प्रतिशत छूट दी जाती है। राष्ट्रीय खेल विकास कोष में प्राप्त धनराशि का उपयोग खेल-कूद को सामान्य रूप से बढ़ावा देने के साथ-साथ खेलों और कुछ विशिष्ट खिलाड़ियों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने में किया जाता है।

- राष्ट्रीय खेल विश्विद्यालयः वर्ष 2014-15 के बजट भाषण में राष्ट्रीय खेल विश्विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए, पश्चिम इम्फाल जिले के कोउतुक में 325.90 एकड़ जमीन चिह्नित की है। यह राष्ट्रीय खेल विश्विद्यालय अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पहला पूर्ण खेल विश्विद्यालय होगा। इस विश्विद्यालय का लक्ष्य खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन और खेल कोचिंग के क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना है।

'कॉफी कनेक्ट' मोबाइल एप्प लॉन्च

- वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने 04 सितंबर 2018 को कॉफी हितधारकों के लिए डिजिटल मोबाइल विस्तार सेवाएं, कॉफी कनेक्ट - इंडिया कॉफी फील्ड फोर्स एप्प, और 'कॉफी कृषिथारंगा' लॉन्च किये।

- मोबाइल एप्प कॉफी कनेक्ट को बागानों में काम करने वाले मजदूरों का काम आसान करने और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है।

कॉफी कनेक्ट मोबाइल एप्प

- कॉफी कनेक्ट मोबाइल एप्प का आरंभ इस क्षेत्र में कार्यरत कामगारों की कार्यकुशलता में सुधार तथा उनकी काम को आसान बनाने के लिए किया गया है।

- यह एप्प, कॉफी उत्पादकों को ऑनलाइन करने, नवीनतम तकनीक से परिचित कराने तथा जियो टैगिंग जैसे कार्यों के लिए सहायता प्रदान करेगा।

- यह एप्प अधिकारियों तथा उत्पादकों के बीच समन्वय, पारदर्शिता एवं सब्सिडी वितरण को लेकर बेहतर तालमेल स्थापित करने में सहायक होगा।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

कॉफी कृषिथारंगा

- 'कॉफी कृषिथारंगा' सेवा शुरू करने का उद्देश्य उत्पादन, लाभ, वातावरण, निरंतरता को बढ़ाने के लिए सही सूचना और सेवाएं प्रदान करना है। 'कॉफी कृषिथारंगा' का कर्नाटक राज्य के चिकमगलुर और हासन जिलों में 30,000 से अधिक किसानों पर पहले साल के दौरान प्रायोगिक परीक्षण हो चुका है और चरणबद्ध तरीके से इसका विस्तार बाकी कॉफी उत्पादकों तक भी होगा। नाबार्ड ने इस प्रायोगिक परियोजना के लिए आंशिक आर्थिक मदद दी है।

पूर्व भारतीय कप्तान सरदार सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया

- पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान सरदार सिंह ने 12 सितम्बर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है।
- उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में वह काफी हॉकी खेल चुके हैं और अब युवाओं के लिए जिम्मेदारी लेने का समय आ गया है।
- सरदार सिंह ने कहा कि उन्होंने एशियाई खेलों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद यह फैसला लिया है, जिसमें भारत अपने खिताब का बचाव करने में असफल रहा और उसे कांस्य पदक के साथ संतोष करना पड़ा।
- उन्होंने यह भी कहा कि वह घरेलू सर्किट में हॉकी खेलना जारी रखेंगे।

जस्टिस रंजन गोगोई भारत के नये मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

- जस्टिस रंजन गोगोई 28 फरवरी 2001 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज बने थे। इसके बाद 12 फरवरी 2011 को उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया।

अप्रैल 2012 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया

- वे पूर्वोत्तर भारत से देश के पहले प्रधान न्यायाधीश होंगे। वे इस समय सुप्रीम कोर्ट में असम की एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन) अपडेट करने की प्रक्रिया की निगरानी कर कर रहे हैं।

वियतनाम के राष्ट्रपति त्रान दाई क्वांग का निधन

- वियतनाम के राष्ट्रपति त्रान दाई क्वांग का 21 सितम्बर 2018 को निधन हो गया. वे 61 वर्ष के थे। वे पिछले कुछ समय से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। राष्ट्रपति त्रान दाई क्वांग का इलाज हनोई के एक सैन्य अस्पताल में चल रहा था।
- वियतनाम टेलीविजन की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू और अतंरराष्ट्रीय डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद लंबे समय से बीमार चल रहे राष्ट्रपति त्रान को नहीं बचाया जा सका।
- त्रान दाई क्वांग मार्च 2018 में भारत की तीन दिन दौरे पर आए थे और बिहार के बोधगया में पवित्र बौद्ध तीर्थस्थल का भी दौरा किया था।
- वर्ष 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब इस कम्युनिस्ट देश के दौरे पर पहली बार आए थे, तब क्वांग ने उनकी मेजबानी की थी।

आईसीसी ट्वेंटी-20 विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा की गई

- भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा 28 सितंबर 2018 को जारी जानकारी के अनुसार ट्वेंटी-20 विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी गई है।
- बीसीसीआई के अनुसार आक्रामक बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर आगामी 9 से 24 नवंबर के बीच वेस्टइंडीज में होने वाले छठे आईसीसी महिला विश्व टी20 में भारत की 15 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेंगी। वेस्टइंडीज में होने वाले आईसीसी महिला वर्ल्ड टी-20 टूर्नामेंट के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा की गई है।

ट्वेंटी-20 विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम

- अखिल भारतीय महिला चयन समिति ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व हरमनप्रीत कौर करेंगी।
- स्मृति मंधाना उनके साथ उप-कप्तान के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगी।
- आईसीसी महिला वर्ल्ड टी-20 टूर्नामेंट के छठे संस्करण का आयोजन 9 से 24 नवम्बर तक वेस्टइंडीज में होगा।
- भारतीय महिला टीम को विश्व कप का प्रबल दावेदार माना जा रहा है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

महिला ट्वेंटी-20 विश्व में भारत की स्थिति

- भारतीय टीम को ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और आयरलैंड के साथ शामिल किया गया है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट का आगाज गयाना में न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 नवम्बर को खेले जाने वाले मैच से करेगी। इसके बाद उसका सामना 11 नवम्बर को पाकिस्तान, 15 नवम्बर को आयरलैंड और 17 नवम्बर को आस्ट्रेलिया से होगा।

भारतीय महिला टीम:

- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), मिताली राज, जेमिमाह रोड्रिगेज, वेदा कृष्णमूर्ति, दीप्ति शर्मा, तान्या भाटिया (विकेटकीपर), पूनम यादव, राधा यादव, अनुजा पाटिल, एकता बिष्ट, डी हेमलता, मानसी जोशी, पूजा वास्त्राकार और अरुणदति रेड्डी।

एशिया कप 2018: भारत ने बांग्लादेश को हराकर सातवीं बार खिताब जीता

- 28 सितंबर 2018 को भारत ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हराकर 7वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश की ओर से दिए गए 223 रनों का लक्ष्य 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया।
- केदार जाधव 23 और कुलदीप यादव 5 रन बनाकर नाबाद लौटे। इससे पहले टॉस हारकर भारत की तरफ से बल्लेबाजी का न्यौता पाने के बाद बांग्लादेश को ओपनर्स से शानदार शुरुआत मिली।
- इस मैच में बांग्लादेश के लिटन दास और मेहदी हसन की सलामी जोड़ी ने ओपनिंग विकेट के लिए 120 रनों की साझेदारी की।

एशिया कप 2018 के प्रमुख तथ्य

- एशिया कप के फाइनल मुकाबले में लिटन दास को उनकी शानदार शतकीय पारी के लिए श्मैन ऑफ द मैचश चुना गया।
- वहीं टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए।
- उन्होंने एशिया कप 2018 में 5 मैच खेलकर, दो शतकों के साथ सत्तर से कुछ कम की औसत से 342 रन बनाए।
- भारत की ओर से कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अपने कोटे के 10 ओवर में 45 रन देकर तीन विकेट हासिल किये।

भारत का सातवां एशिया कप खिताब

- भारतीय टीम ने इससे पहले वर्ष 1984, 1988, 1990, 1991, 1995, 2010 और 2016 में ये खिताब जीता था।
- बांग्लादेश लगातार दूसरी बार एशिया कप के फाइनल में पहुंचा था लेकिन उसे इस बार भी हार का सामना करना पड़ा।
- इससे पहले वर्ष 2016 में भी बांग्लादेश को एशिया कप के फाइनल में भारत ने हराया था।
- बांग्लादेश तीन बार एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुका है लेकिन उसे एक बार भी जीत हासिल नहीं हुई है।

फाइनल मुकाबले में दोनों देशों की टीमें:

- भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), शिखर धवन (उपकप्तान), अंबाती रायडू, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह।
- बांग्लादेश: लिटन दास (विकेटकीपर), सौम्य सरकार, मोहम्मद मिथुन, मुशफिकुर रहीम, इमरुल कायेस, महमुदुल्लाह, मेहदी हसन, मशरफे मुर्तजा (कप्तान), नजमुल इस्लाम, रुबेल हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान।

श्रीशंकर ने लम्बी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया

- केरल के 19 वर्षीय मुरली श्रीशंकर ने 58वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चौंपियनशिप के तीसरे दिन 27 सितंबर 2018 को 8.20 मीटर की छलांग लगाकर अंकित शर्मा के 2016 में अलमाटी में बनाये 8.19 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया।
- श्रीशंकर का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7.99 मीटर था जो उन्होंने इस साल मार्च में फेडरेशन कप में बनाया था। सेना के वीओ जिनेश ने 7.95 मीटर की छलांग के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। हरियाणा के साहिल महाबली 7.81 मीटर की छलांग के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2018 की घोषणा

- राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रति वर्ष खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन को पहचानने और सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष खेलों में मान्यता प्रदान करने और उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने के लिए दिए जाते हैं।
- इस वर्ष इन पुरस्कारों के लिए बड़ी संख्या में नामांकन प्राप्त हुए जिनपर पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी, अर्जुन पुरस्कार विजेताओं, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं, ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं, खेल पत्रकार/विशेषज्ञ/आंखों देखा हाल सुनाने वाले कमेंटेटर और खेल प्रकाशकों की चयन समितियों द्वारा विचार किया गया। यह पुरस्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर और उचित जांच के बाद सरकार ने निम्नलिखित खिलाडिय्यों/कोचों/संगठनों को प्रदान करती है।

देश की पहली महिला आईएएस अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा का निधन

- आजादी के बाद देश की पहली आईएएस अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा का 17 सितम्बर 2018 को मुंबई के अंधेरी स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 91 वर्ष की थीं. अन्ना राजम मल्होत्रा ने देश के कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभाई और देश की प्रगति में अपना योगदान दिया।
- केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के दौरान उन्हें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) का कार्य मिला था। अन्ना राजम मल्होत्रा भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। वे 1951 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने मद्रास कैडर का विकल्प चुना और तत्कालीन मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में मद्रास राज्य की सेवा की।

के.एन. व्यास एटॉमिक एनर्जी कमीशन के प्रमुख नियुक्त

- भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बार्क) के निदेशक के.एन. व्यास को 19 सितंबर 2018 को एटॉमिक एनर्जी कमीशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्हें शेखर बासु के स्थान पर इस पद पर नियुक्त किया गया है।
- शेखर बासु को दो बार एक-एक साल का सेवा विस्तार दिया गया था. उन्हें पहली बार वर्ष 2016 में और दूसरी बार 2017 में सेवा विस्तार दिया गया। उनका विस्तारित कार्यकाल 19 सितंबर 2018 को समाप्त हो गया।

के.एन. व्यास के बारे में

- के. एन. व्यास बार्क प्रशिक्षण स्कूल से 1979 में प्रशिक्षण लेने के बाद वह बार्क के फ्यूल डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेक्शन ऑफ रिएक्टर इंजीनियरिंग डिवीजन से जुड़े थे।
- व्यास ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वडोदरा के एमएस विश्वविद्यालय से स्नातक किया है।
- व्यास के अधिकारिक बायोडाटा के मुताबिक, व्यास परमाणु रिएक्टर ईंधन के डिजाइन और विश्लेषण के लिए काम कर चुके हैं।
- उन्होंने 23 फरवरी, 2016 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) के रिएक्टर समूह के एसोसिएट निदेशक और अग्रणी वैज्ञानिक के.एन. व्यास ने इस केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
- वे बार्क प्रशिक्षण स्कूल के 22वें बैच के स्नातक हैं और उन्होंने इस केंद्र के रिएक्टर इंजीनियरिंग डिवीजन के फ्यूल डिजाइन एवं डेवलपमेंट सेक्सन में नौकरी शुरू की थी।

सेल्सफोर्स के संस्थापक मार्क बेनिओफ ने टाइम मैगजीन को खरीदा

- विश्व की प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली साप्ताहिक पत्रिकाओं में से एक 'टाइम' मैगजीन को अमेरिकी अरबपति मार्क बेनिऑफ और उनकी पत्नी लिन ने 19 करोड़ डॉलर (1,368 करोड़ रुपये) में खरीदा।
- टाइम मैगजीन की खरीद के साथ मार्क उन सभी अमीर टेक उद्योगपतियों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने अखबारों और पत्रिकाओं को खरीदा है। इसमें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और अमेजन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस भी शामिल हैं। अमेरिकी मीडिया कंपनी मेरेडिथ कॉर्प ने मशहूर 'टाइम' मैगजीन को बेच दिया है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में आरम्भ हुआ

- तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पालतू कुत्तों के लिए विशेष 'डॉग पार्क' का निर्माण किया गया है। इसमें सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं।
- बृहद हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) ने कोंडापुर में 1.1 करोड़ रुपये की लागत से 1.3 एकड़ में इस पार्क को विकसित किया है। यह भारत का एक्स्क्लूसिव डॉग पार्क है।

डॉग पार्क की विशेषताएं

- इसमें वॉकिंग ट्रैक और क्लिनिक की सुविधा भी है। जहां यह पार्क बनाया गया है वहां पहले कूड़े का डंपिंग यार्ड था। इस पार्क में कुत्तों को प्रशिक्षण देने वाले उपकरण, दो लॉन, एक एम्फीथिएटर, बड़े और छोटे कुत्तों के लिए अलग अलग अहाते समेत अन्य सुविधाएं हैं।
- यह पार्क देश का पहला पहला प्रमाणित डॉग पार्क है। यहां पर एक पशु चिकित्सक, कुत्ते का प्रशिक्षक,मानकों के अनुरूप सफाई और कुत्तों को निशुल्क टीकाकरण की भी सुविधा होगी। लोग अपने पालतू कुत्तों को यहां ला सकते हैं और पार्क की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।

नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन का खिताब जीता

- जापान की नाओमी ओसाका यूएस ओपन ग्रैंडस्लैम जीतने वाली पहली जापानी महिला खिलाड़ी बन गई हैं. नाओमी ओसाका ने 08 सितम्बर 2018 को सेरेना विलियम्स को हराते हुए ये खिताब अपने नाम किया. 20 वर्षीय नाओमी ओसाका ने इस मैच में 6-2, 6-4 से सेरेना विलियम्स को हराकर जीत हासिल की।
- ओसाका की यह जीत इसलिए भी खास है कि कोई ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वालीं वह जापान की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नाओमी ओसाका की सेरेना विलियम्स पर दो मैचों में यह दूसरी जीत है। इसी साल मार्च में उन्होंने मियामी ओपन में सेरेना को हराया था।

नोवाक जोकोविच ने 14वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता

- सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 09 सितम्बर 2018 को अर्जेंटीना के जुआन मार्टिन डेल पोत्रो को हराकर अपना तीसरा यूएस ओपन खिताब जीता। इस जीत के साथ ही नोवाक जोकोविच ने अमेरिकी खिलाड़ी पीट सम्प्रास के 14 ग्रैंड स्लैम जीतने के उपलब्धि की बराबरी कर ली।
- पीट सम्प्रास और नोवाक जोकोविच सर्वाधिक ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने के मामले में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अब उनसे आगे सिर्फ रोजर फेडरर (20) और राफेल नडाल (16) ही हैं। यूएस ओपन फाइनल में जुआन मार्टिक के खिलाफ फाइनल में जोकोविच ने 6-3, 7-6, 6-3 से खिताबी जीत दर्ज की।

अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2018

- विश्वभर में 08 सितंबर 2018 को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। इस वर्ष का विषय था – साक्षरता और कौशल विकास **(Literacy and skills development)**।
- इसका उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना है। यह उत्सव दुनियाभर में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में साक्षरता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। आज भी विश्व में अनेक लोग निरक्षर है। इस दिवस को मनाने का मुख्य लक्ष्य विश्व में सभी लोगो को शिक्षित करना है। बच्चे, वयस्क, महिलाओं और बूढों को साक्षर बनाना ही इसका मुख्य लक्ष्य है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

क्यों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस?

- मानव विकास और समाज के लिए उनके अधिकारों को जानने और साक्षरता की ओर मानव चेतना को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत में या देश-दुनिया में गरीबी को मिटाना, बाल मृत्यु दर को कम करना, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, लैंगिक समानता को प्राप्त करना आदि को जड़ से उखाड़ना बहुत जरूरी है। ये क्षमता सिर्फ साक्षरता में है जो परिवार और देश की प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है।
- साक्षरता दिवस लगातार शिक्षा को प्राप्त करने की ओर लोगों को बढ़ावा देने हेतु और परिवार, समाज तथा देश के लिये अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को व्यक्ति, समाज और समुदाय के लिये साक्षरता के बड़े महत्व को ध्यान दिलाने के लिए विश्व भर में मनाना शुरु किया गया। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिये वयस्क शिक्षा और साक्षरता की दर को ध्यान दिलाने के लिये खासतौर पर मनाया जाता है।

बिमल जालान मुख्य आर्थिक सलाहकार चयन समिति के अध्यक्ष घोषित

- केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान को मुख्य आर्थिक सलाहकार चयनित करने हेतु बनाई गयी समिति का अध्यक्ष घोषित किया है। दो माह पूर्व अरविन्द सुब्रमणियन द्वारा पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद यह पैनल गठित किया गया है।
- बिमल जालान के अतिरिक्त, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव सी चंद्रमौली और आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग पैनल के सदस्य होंगे जो साक्षात्कार प्राप्त करने और साक्षात्कार आयोजित करने के लिए कार्यरत होंगे।

ELITE IAS